

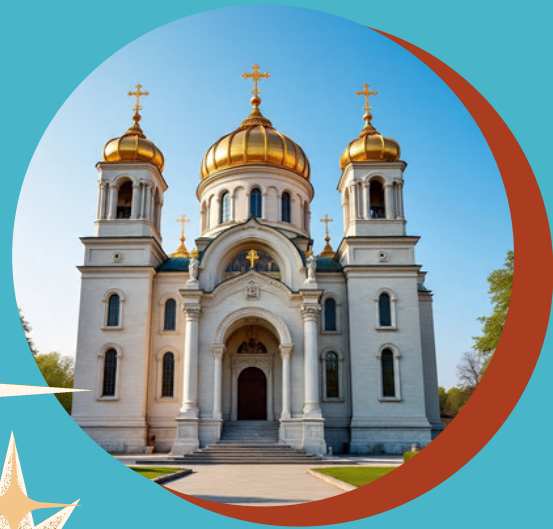


Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



OCTOBER MONTH BANKING AND FINANCIAL AWARENESS



120+ MCQ
with detailed
explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: Which organization has directed banks to settle unclaimed deposits through special camps between October and December 2025?

किस संगठन ने बैंकों को अवितरित जमा राशि के निपटारे के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है?

- A. SEBI / सेबी
- B. IRDAI / आईआरडीएआई
- C. RBI / आरबीआई
- D. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E. NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has asked all banks to settle unclaimed deposits such as savings/current accounts inactive for 10 years, term deposits not claimed within 10 years, dividends, interest warrants, pensions, etc., over the next three months (October–December 2025).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अगले तीन महीनों (अक्टूबर–दिसंबर 2025) में अवितरित जमा राशि जैसे 10 वर्षों से निष्क्रिय बचतचालू खाते/, परिपक्वता के बाद 10 वर्षों तक न निकाले गए सावधि जमा, डिविडेंड, ब्याज वारंट, पेंशन आदि का निपटारा करें।
- Such deposits are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) maintained by RBI, but claimants can withdraw them later with interest.
- इस प्रकार की राशि RBI द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानांतरित की जाती है, लेकिन जमाकर्ता बाद में ब्याज सहित इसे निकाल सकते हैं।
- To facilitate settlement, RBI will organize district-level week-long joint camps, starting in Gujarat in October 2025 and continuing across India until December.
- निपटारे को सुगम बनाने के लिए RBI जिलास्तरीय सप्ताहभर के संयुक्त शिविर - आयोजित करेगा; पहला शिविर अक्टूबर 2025 में गुजरात में होगा और दिसंबर तक देशभर में आयोजित होंगे।
- The State Level Bankers' Committee (SLBC) will lead the initiative in respective states to ensure maximum claim settlements.

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) राज्यों में इस पहल का नेतृत्व करेगी और अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करेगी।

Ques: What is the Ways and Means Advances (WMA) limit set by the RBI for the second half of FY 2025-26 (October 2025–March 2026)?

RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (अक्टूबर) 2025–मार्च 2026) के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा कितनी तय की है?

- A. ₹25,000 crore
- B. ₹50,000 crore
- C. ₹75,000 crore
- D. ₹1,00,000 crore
- E. ₹1,50,000 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the Government of India, set the WMA limit for H2 FY 2025-26 (Oct–Mar 2026) at ₹50,000 crore.
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारत सरकार के परामर्श से FY 2025-26 की दूसरी छमाही (अक्टूबर)–मार्च 2026) के लिए WMA सीमा ₹50,000 करोड़ तय की है।
- RBI may trigger fresh market loan floatation once the Government utilises 75% of this limit.
- जब सरकार इस सीमा का 75% उपयोग कर लेगी, तब RBI नया बाजार ऋण जारी कर सकता है।
- For the first half (H1) of FY 2025-26, the WMA limit was ₹1,50,000 crore.
- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1) के लिए सीमा ₹1,50,000 करोड़ थी।
- Interest rate: WMA = Repo Rate; Overdraft = Repo Rate + 2%.
- ब्याज दर: WMA = रेपो रेट; ओवरड्राफ्ट + रेपो रेट = 2%।

Ques: What is the minimum net worth requirement for an SRO in the Fintech (SRO-FT) sector?

फिनटेक (SRO-FT) क्षेत्र में एक SRO के लिए न्यूनतम नेट वर्थ आवश्यकता क्या है?

- A. ₹1 crore
- B. ₹2 crore
- C. ₹5 crore
- D. ₹10 crore
- E. ₹15 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE) is India's first Self-Regulatory Organisation for Fintech (SRO-FT).
- फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (FACE) भारत का पहला स्व-नियामक संगठन (SRO-FT) है।
- To qualify as an SRO-FT, an entity must have a minimum net worth of ₹2 crore.
- एक SRO-FT बनने के लिए न्यूनतम नेट वर्थ ₹2 करोड़ होना आवश्यक है।
- In comparison, general financial market SROs like FIMMDA require ₹10 crore, while SROs within the Account Aggregator (AA) ecosystem also need ₹2 crore.
- तुलना के लिए, सामान्य वित्तीय बाजार SRO जैसे FIMMDA के लिए ₹10 करोड़ आवश्यक हैं, जबकि AA इकोसिस्टम के SROs के लिए भी न्यूनतम ₹2 करोड़ है।
- After RBI recognition, FACE's membership grew from 60 in August 2024 to 275 in August 2025, showing its expanding role in fintech regulation and consumer empowerment.
- आरबीआई मान्यता के बाद, FACE की सदस्यता अगस्त 2024 में 60 से बढ़कर अगस्त 2025 में 275 हो गई, जो भारत में फिनटेक विनियमन और उपभोक्ता सशक्तिकरण में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

Ques: SBI Mutual Fund recently launched its first scheme under the Specialised Investment Fund (SIF) category. What is its name?

SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) श्रेणी के तहत अपनी पहली योजना लॉन्च की। इसका नाम क्या है?

- A. SBI Magnum Balanced Fund / SBI मैग्नम बैलेंस्ड फंड
- B. SBI Magnum Equity Hybrid Fund / SBI मैग्नम इक्विटी हाइब्रिड फंड
- C. SBI Magnum Hybrid Long Short / SBI मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट
- D. SBI Magnum Debt Fund / SBI मैग्नम डेट फंड
- E. SBI Magnum Arbitrage Fund / SBI मैग्नम आर्बिट्राज फंड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI Mutual Fund launched its first Magnum Hybrid Long Short scheme under the Specialised Investment Fund (SIF) category.
 - SBI म्यूचुअल फंड ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) श्रेणी के तहत अपनी पहली मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट योजना लॉन्च की है।
 - The scheme aims to generate regular income through derivatives strategies, including covered calls, arbitrage, and cash & derivatives segments.
 - यह योजना डेरिवेटिव रणनीतियों जैसे कवर कॉल्स, आर्बिट्राज, और नकद व डेरिवेटिव सेगमेंट्स में निवेश करके नियमित आय उत्पन्न करना लक्ष्य करती है।
 - Investment allocation: 65–75% equity, 25–35% debt, and 10% in REITs & InVITs; target returns are 8–11% (not guaranteed).
 - निवेश आवंटन :65–75% इक्विटी, 25–35% डेट, और 10% REITs व InVITs; लक्षित रिटर्न 8–11% है) गारंटीकृत नहीं।
 - The New Fund Offer (NFO) opened for subscription from October 1, 2025.
 - नया फंड ऑफर (NFO) 1 अक्टूबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला।
-

Ques: Which public sector bank became the second PSB to be approved as a Trading-Cum-Clearing Member (TCM) on the India International Bullion Exchange (IIBX)?

कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (IIBX) पर ट्रेडिंग-क्लियरिंग सदस्य-कम(TCM) के रूप में अनुमोदित होने वाला दूसरा PSB बन गया?

- A. Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B. Indian Bank / इंडियन बैंक
- C. Canara Bank / केनरा बैंक
- D. Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- E. Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda (BOB) has been approved by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) to operate as a Trading-Cum-Clearing Member (TCM) on the India International Bullion Exchange (IIBX) at GIFT City, Gujarat.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) को IFSCA द्वारा GIFT सिटी, गुजरात में India International Bullion Exchange (IIBX) पर ट्रेडिंग) क्लियरिंग सदस्य-कम(TCM) के रूप में संचालन की अनुमति दी गई है।
- BOB becomes the second Public Sector Bank (PSB) after SBI to receive the TCM status.
- BOB SBI के बाद दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसे TCM का दर्जा मिला।
- IIBX, established by the Government of India in July 2022 at Gandhinagar, Gujarat, is India's first international bullion exchange.
- IIBX, जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2022 में गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है।

Ques: BRICS-backed New Development Bank (NDB) will issue its first rupee-denominated bond in India before which year?

ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) भारत में अपना पहला रुपए मूल्यवर्गित बॉन्ड किस वर्ष से पहले जारी करेगा?

- A. 2024
- B. 2025
- C. 2026
- D. 2027
- E. 2028

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The BRICS-backed New Development Bank (NDB) will issue its first rupee-denominated bond in India's domestic market before end-March 2026.
 - ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) भारत के घरेलू बाजार में मार्च 2026 से पहले अपना पहला रुपए मूल्यवर्गित बॉन्ड जारी करेगा।
 - Earlier, NDB raised funds in Chinese yuan and South African rand and is in advanced discussions with the RBI for this debut issuance.
 - इससे पहले NDB ने चीनी युआन और दक्षिण अफ्रीकी रैंड में फंड जुटाए थे और यह पहली रुपए निर्गम के लिए RBI के साथ उन्नत चरण की बातचीत में है।
 - The bank plans to raise \$400–500 million via 3–5 year bonds in the first tranche.
 - बैंक पहली किस्त में \$400–500 मिलियन को 3–5 साल के बॉन्ड्स के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखता है।
-

Ques: The Central Consumer Protection Authority (CCPA) recently imposed a penalty of ₹2,00,000 on which company for false and misleading price representations?

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में झूठे और भ्रामक मूल्य प्रस्तुतिकरण के लिए किस कंपनी पर ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया है?

- A. Amazon / अमेज़न
- B. Flipkart / फ्लिपकार्ट
- C. FirstCry (Digital Age Retail Pvt. Ltd.) / फर्स्टक्राई (डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड)
- D. Snapdeal / स्नैपडील
- E. Myntra / मिंत्रा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The CCPA has imposed a penalty of ₹2,00,000 on M/s Digital Age Retail Pvt. Ltd. (FirstCry) for misleading price representations.
- CCPA ने M/s Digital Age Retail Pvt. Ltd. (FirstCry) पर भ्रामक मूल्य प्रस्तुतिकरण के लिए ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया है।
- The order was passed under Sections 10, 20, and 21 of the Consumer Protection Act, 2019.
- यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया।
- The company displayed products as “MRP inclusive of all taxes,” but later levied extra GST at checkout, amounting to deceptive pricing.
- कंपनी ने उत्पादों पर “एमआरपी सभी करों सहित” दिखाया, लेकिन चेकआउट पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया, जो भ्रामक मूल्य निर्धारण माना गया।
- This was held as misleading advertisement [Section 2(28)] and unfair trade practice [Section 2(47)] under the Act.
- इसे अधिनियम की धारा 2(28) (भ्रामक विज्ञापन) और धारा 2(47) (अनुचित व्यापार प्रथा) माना गया।
- By engaging in “drip pricing”, a dark pattern under the Dark Patterns Guidelines, 2023, consumers were misled about the final price.
- कंपनी ने “ड्रिप प्राइसिंग” अपनाई, जिसे डार्क पैटर्न गाइडलाइन्स, 2023 के तहत उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला माना गया।
- This also violated Rule 7(1)(e) of the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, requiring total price inclusive of taxes to be shown upfront.
- यह ई-कॉमर्स नियम, 2020 के नियम 7(1)(e) का उल्लंघन था, जिसमें कुल मूल्य (सभी करों सहित) अग्रिम रूप से दिखाना आवश्यक है।

Ques: Which regulator barred HDFC Bank’s DIFC branch from taking new clients?

एचडीएफसी बैंक की DIFC शाखा को नए ग्राहक लेने से किस नियामक ने रोका?

A. DFSA | दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी

- B. SEBI | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- C. RBI | भारतीय रिज़र्व बैंक
- D. IMF | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- E. FATF | वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Dubai Financial Services Authority (DFSA) has barred HDFC Bank's DIFC branch from soliciting or conducting business with new clients, effective 26 September 2025.
- दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) ने एचडीएफसी बैंक की DIFC शाखा को 26 सितंबर 2025 से नए ग्राहकों के साथ कारोबार करने से रोका।
- The restriction covers all financial services, including advising on financial products, arranging investments, arranging credit, custody services, and client onboarding.
- यह रोक सभी वित्तीय सेवाओं पर लागू है – जैसे वित्तीय उत्पादों पर सलाह, निवेश सौदे तय करना, ऋण की व्यवस्था करना, कस्टडी सेवाएं और ग्राहकों का ऑनबोर्डिंग।
- HDFC Bank opened its DIFC branch on 4 August 2014 to provide wealth management services to the Indian diaspora in the Gulf.
- एचडीएफसी बैंक ने अपनी DIFC शाखा 4 अगस्त 2014 को खोली थी ताकि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय को वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- This was HDFC Bank's third overseas branch, after Bahrain and Hong Kong.
- यह एचडीएफसी बैंक की तीसरी विदेशी शाखा थी, बहरीन और हांगकांग के बाद।

Genius

Ques: Which bank signed an MoU with Tata Power Renewable Energy Limited to provide financial support for solar energy adoption by MSMEs and C&I customers?

किस बैंक ने MSME और C&I ग्राहकों के लिए सौर ऊर्जा अपनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Tata Power Renewable Energy Limited के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए?

- A. State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B. Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

- C. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D. Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda (BOB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) to support MSMEs and Commercial & Industrial (C&I) customers in adopting solar energy.
 - बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) के साथ MSME और C&I ग्राहकों के लिए सौर ऊर्जा अपनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए।
 - Under the MoU, BOB will offer loans for solar projects with interest rates starting from 7.75% for capacities up to 10 MW, through TPREL or its authorized partners.
 - MoU के तहत, BOB 10 मेगावाट तक क्षमता वाले सौर परियोजनाओं के लिए 7.75% से शुरू होने वाली ब्याज दर पर ऋण TPREL या उसके अधिकृत साझेदारों के माध्यम से प्रदान करेगा।
 - The bank provides collateral-free loans up to ₹10 crore, covered under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), with flexible repayment tenure up to 120 months, relaxed margin requirements starting at 20%, and concessional processing fees.
 - बैंक ₹10 करोड़ तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण, CGTMSE के तहत कवर, 120 महीने तक लचीला पुनर्भुगतान अवधि, 20% से शुरू होने वाली आसान मार्जिन आवश्यकताएं, और सुपरिशुल्क में रियायत . प्रदान करेगा।
-

Ques: Which digital payments platform, in collaboration with Mastercard, launched the exclusive 'Tap & Pay' feature for Mastercard cardholders in India?

भारत में मास्टरकार्ड धारकों के लिए एक्सक्लूसिव 'टैप एंड पे' फीचर लॉन्च करने वाला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो मास्टरकार्ड के साथ सहयोग में है?

- A. Paytm / पेटीएम
- B. Google Pay / गूगल पे
- C. PhonePe / फोनपे
- D. Amazon Pay / अमेज़न पे
- E. BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- PhonePe Private Limited, a leading digital payments platform, in collaboration with Mastercard Inc., launched an exclusive 'Tap & Pay' feature for Mastercard cardholders in India.
- फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ने मास्टरकार्ड इंक के सहयोग से भारत में मास्टरकार्ड धारकों के लिए 'टैप एंड पे' फीचर लॉन्च किया।
- Objective: To provide secure and frictionless 'tap and pay' experiences at physical retail outlets and support tokenised e-commerce transactions.
- उद्देश्यभौतिक रिटेल आउटलेट्स पर सुरक्षित और निर्बाध : 'टैप एंड पे' अनुभव प्रदान करना और टोकनाइज्ड ईनदेन का समर्थन करना।कॉमर्स ले-
- Eligible Users: Mastercard credit, debit, and prepaid cardholders in India.
- पात्र उपयोगकर्ता: भारत में मास्टरकार्ड क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड धारक।

About PhonePe:

- Established : 2015
- HQ : Bengaluru, Karnataka
- CEO : Sameer Nigam

Ques: Which body currently selects Non-Official Directors (NODs) for Public Sector Banks (PSBs)?

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए वर्तमान में गैर) आधिकारिक निदेशकों-NODs) का चयन कौन करता है?

- A. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B. Ministry of Finance (Department of Financial Services) / वित्त मंत्रालय वित्तीय) (सेवाएं विभाग
- C. Boards of PSBs / पीएसबी के बोर्ड
- D. P J Nayak Committee / पी जे नायक समिति
- E. SEBI / सेबी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Central Government has retained control over the appointment of Non-Official Directors (NODs) in Public Sector Banks (PSBs) to ensure consistent oversight and effective implementation of financial inclusion schemes.
- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में गैर) आधिकारिक निदेशकों-NODs) की नियुक्ति पर नियंत्रण बनाए रखा है ताकि निरंतर निगरानी और वित्तीय समावेशन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- During PSB Manthan 2025, experts suggested that PSB boards should get this power, but the Govt rejected it.
- PSB मंथन 2025 के दौरान विशेषज्ञों ने यह शक्ति बोर्ड को देने का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- In 2014, the P J Nayak Committee (RBI-appointed) had also recommended that PSB boards should appoint NODs, but this was not implemented.
- 2014 में आरबीआई द्वारा नियुक्त पीनायक समिति .जे. ने भी सिफारिश की थी कि PSB बोर्ड NODs नियुक्त करें, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
- Currently, the Department of Financial Services (Finance Ministry) selects NODs for PSBs.
- वर्तमान में वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग PSBs के लिए NODs का चयन करता है।
- Non-board directors in PSBs include Govt-nominated, RBI-nominated, Independent, and Shareholder-elected directors.
- PSBs में गैरमें बोर्ड निदेशकों- सरकारनामित-, RBI-नामित, स्वतंत्र, और शेयरधारकों द्वारा

चुने गए निदेशक शामिल होते हैं।

Ques: Who has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI) effective from October 9, 2025?

9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए उप-गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A. Rajeshwar Rao / राजेश्वर राव
- B. Poonam Gupta / पूनम गुप्ता
- C. Swaminathan Janakiraman / स्वामीनाथन जनकीरामन
- D. T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर
- E. Shirish Chandhra Murmu / शिरीष चंद्र मुरमु

Answer : Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Appointments Committee of the Cabinet approved the appointment of Shirish Chandhra Murmu as the Deputy Governor of RBI for a three-year term effective October 9, 2025.
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने शिरीष चंद्र मुरमु को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का उप-गवर्नर तीन वर्ष की अवधि के लिए 9 अक्टूबर 2025 से नियुक्त किया है।
- He will succeed Rajeshwar Rao, whose extended term as Deputy Governor ends on October 8, 2025.
- वे राजेश्वर राव के उत्तराधिकारी होंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगा।
- Currently, Murmu is serving as Executive Director (ED), Department of Supervision, RBI.
- वर्तमान में मुरमु कार्यकारी निदेशक (ED), पर्यवेक्षण विभाग, RBI के रूप में कार्यरत हैं।
- RBI has four deputy governors: T. Rabi Sankar, Swaminathan Janakiraman, Poonam Gupta, and now Shirish Chandhra Murmu.
- RBI में कुल चार उप-गवर्नर होते हैं: टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जनकीरामन, पूनम गुप्ता और अब शिरीष चंद्र मुरमु।
- As per the RBI Act, 1934, RBI must have four Deputy Governors – two from within RBI, one from the commercial banking sector, and one economist to

head the Monetary Policy Department.

- RBI अधिनियम, 1934 के अनुसार RBI में चार उप-गवर्नर होना अनिवार्य है – दो RBI से, एक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से और एक अर्थशास्त्री जो मौद्रिक नीति विभाग का नेतृत्व करता है।

Ques: RBI is likely to allow which company's exit from the Upper Layer NBFC classification?

RBI किस कंपनी को अपर लेयर NBFC वर्गीकरण से बाहर निकलने की अनुमति देने जा रहा है?

- A. Reliance Capital / रिलायंस कैपिटल
- B. Shriram Finance / श्रीराम फाइनेंस
- C. Tata Sons / टाटा सन्स
- D. Bajaj Finance / बजाज फाइनेंस
- E. HDFC Ltd / एचडीएफसी लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The RBI had classified Tata Sons as an Upper Layer NBFC in September 2022, mandating that it list by 30 September 2025.
- RBI ने सितंबर 2022 में टाटा सन्स को अपर लेयर NBFC में रखा था और उन्हें 30 सितंबर 2025 तक लिस्टिंग करने का निर्देश दिया था।
- In March 2024, Tata Sons requested de-registration to avoid listing, and RBI is now considering approval subject to certain conditions.
- मार्च 2024 में टाटा सन्स ने लिस्टिंग से बचने के लिए डिरजिस्ट्रेशन का अनुरोध किया था, और RBI अब इसे शर्तों के साथ मंजूरी देने पर विचार कर रहा है।
- Shapoorji Pallonji Group (holding 18% stake) sought a fair exit route, while Tata Trusts, the major stakeholder, wants Tata Sons to remain unlisted.
- शापूरजी पालोनजी ग्रुप)18% हिस्सेदारीने न्यायसंगत एग्जिट रूट मांगा है (, जबकि टाटा ट्रस्ट मुख्य हिस्सेदार के रूप में चाहता है कि टाटा सन्स अनलिस्टेड रहे।
- The decision will balance financial stability, investor exit, and regulatory compliance.
- यह निर्णय वित्तीय स्थिरता, निवेशक एग्जिट और रेगुलेटरी अनुपालन के बीच संतुलन बनाएगा।

Ques: Which company has been barred by SEBI and fined along with its three senior executives for alleged financial misstatement?

किस कंपनी को सेबी ने कथित वित्तीय गड़बड़ी के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रतिबंधित और दंडित किया है?

- A. Man Industries (India) Ltd. / मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इंडिया)
- B. Adani Enterprises / अडाणी एंटरप्राइजेज
- C. Reliance Power / रिलायंस पावर
- D. L&T Finance / एल एंड टी फाइनेंस
- E. Hindustan Zinc / हिंदुस्तान जिंक

Answer :Option A

Explanation / व्याख्या:

- SEBI (Securities and Exchange Board of India) barred Man Industries (India) Ltd. and three of its senior executives from accessing the securities market for two years.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इंडिया) और इसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
- A monetary penalty of ₹25 lakh each was imposed for alleged financial misstatements.
- प्रत्येक पर ₹25 लाख का जुर्माना लगाया गया, जो कथित वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित है।
- This action was taken to ensure corporate governance and investor protection
- यह कार्रवाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए की गई।

Penalised executives include / दंडित अधिकारियों में शामिल हैं:

- Ramesh Mansukhani – Chairman / रमेश मंसुखानी – चेयरमैन
- Nikhil Mansukhani – Executive Director / निखिल मंसुखानी – एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
- Ashok Gupta – Former Executive Director & Current CFO / अशोक गुप्ता – पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं वर्तमान CFO

Ques: The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹2.7 lakh on which company for non-compliance with norms related to 'Internal Ombudsman'?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'आंतरिक लोकपाल' से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर ₹2.7 लाख का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया?

- A. Manappuram Finance Limited / मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड
- B. Mahindra Finance / महिंद्रा फाइनेंस
- C. Bajaj Finance Limited / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
- D. Shriram Finance Limited / श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
- E. Muthoot FinCorp Limited / मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड

Answer : Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of ₹2.7 lakh on Muthoot FinCorp Limited for non-compliance with Internal Ombudsman guidelines.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आंतरिक लोकपाल दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर ₹2.7 लाख का मौद्रिक दंड लगाया।
- RBI found that the company failed to establish an auto-escalation system of complaints rejected partly or wholly by its grievance redress mechanism to the Internal Ombudsman.
- RBI ने पाया कि कंपनी अपने शिकायत निवारण तंत्र द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत शिकायतों को आंतरिक लोकपाल तक स्वतः अग्रेषित करने की प्रणाली स्थापित करने में विफल रही।
- The penalty was imposed under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the RBI Act, 1934.
- यह दंड RBI अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) तथा 58B(5)(aa) के तहत लगाया गया।

Ques: Which two institutions have partnered to co-lend gold loans targeting semi-urban and rural customers?

किस दो संस्थानों ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करते हुए गोल्ड लोन सह-वित्तपोषण के लिए साझेदारी की है?

- A. SBI and Bajaj Finance / एसबीआई और बजाज फाइनेंस
- B. Bank of Baroda and IIFL Finance / बैंक ऑफ बड़ौदा और IIFL फाइनेंस
- C. HDFC Bank and Muthoot Finance / एचडीएफसी बैंक और मुथूट फाइनेंस
- D. Axis Bank and Manappuram Finance / एक्सिस बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस
- E. PNB and Shriram Finance / पीएनबी और श्रीराम फाइनेंस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda and IIFL Finance have partnered to co-lend gold loans, targeting semi-urban and rural customers.
- बैंक ऑफ बड़ौदा और IIFL फाइनेंस ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को लक्षित करते हुए गोल्ड लोन सहवित्तपोषण- के लिए साझेदारी की है।
- The scheme primarily focuses on underserved and unbanked customers.
- यह योजना मुख्य रूप से अविकसित और बिना बैंक सुविधा वाले ग्राहकों को लक्षित करेगी।
- The objective is to provide fast, easy, and affordable credit, especially for agricultural and allied activities.
- उद्देश्य है छोटे उधारकर्ताओं को तेज़, आसान और किफायती ऋण उपलब्ध कराना, विशेषकर कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए।
- This initiative will enhance financial inclusion and bring more rural customers into the formal credit system.
- इस पहल से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक ग्रामीण ग्राहक औपचारिक ऋण प्रणाली में जुड़ेंगे।

Ques: From which date will the RBI's new rules on interest rates, gold loans, and exposure norms come into effect?

आरबीआई के ब्याज दर, सोना ऋण और जोखिम मानकों पर नए नियम किस तारीख से प्रभावी होंगे?

- A. September 15
- B. October 1
- C. November 1
- D. December 31
- E. January 1

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced sweeping regulatory changes effective from October 1, 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले बड़े बदलावों की घोषणा की।

Key changes include:

- Banks can reduce spread components on advances earlier than the 3-year lock-in period, benefiting borrowers or allowing switch to fixed rates.
- ऋण पर ब्याज दर में ढील बैंकों को :3 साल की लॉक इन अवधि-से पहले स्प्रेड घटाने की अनुमति, जिससे उधारकर्ताओं को लाभ और फिक्स्ड रेट पर स्विच करने का विकल्प।
- Working capital loans against gold/silver for manufacturers and Tier-3/Tier-4 banks.
- सोनाचांदी का उप/उत्पादन में सोने :चांदी के विरुद्ध वर्किंग कैपिटल ऋण/योग करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, टियर-3/टियर-4 बैंक भी ऐसे ऋण दे सकते हैं।
- Revised limits for foreign currency and rupee-denominated debt instruments.
- विदेशी मुद्रा और रुपये में ऋण साधनों के लिए संशोधित सीमा।
- Exposure of Indian branches of foreign banks to their HO & subsidiaries to be reckoned only under Large Exposure Framework (LEF), not Intra-group Transactions (ITE).
- विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं का अपने मुख्यालय और सहायक कंपनियों के प्रति जोखिम केवल बड़े एक्सपोज़र ढांचे (LEF) में गिना जाएगा, ITE में नहीं।

- These measures aim to enhance financial flexibility, inclusion, and transparency in India's banking system.
- ये बदलाव भारत के बैंकिंग सिस्टम में वित्तीय लचीलापन, समावेशन और पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं।

Ques: Who have been recently appointed as the Managing Directors (MD) & Chief Executive Officers (CEO) of Union Bank of India ?

हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कौन नियुक्त किए गए हैं?

- A. Asheesh Pandey / आशीष पांडे
- B. A. Manimekalai / ए. मणिमेकलै
- C. Rajeev Pandey / राजीव पांडे
- D. Kalyan Kumar / कल्याण कुमार
- E. Rajesh Kumar / राजेश कुमार

Answer : Option A

Explanation / व्याख्या:

- Asheesh Pandey, Executive Director of Bank of Maharashtra, has been appointed as MD & CEO of Union Bank of India (UBI) for a three-year tenure, replacing A. Manimekalai.
- अशीष पांडे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक, को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) का MD & CEO तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वे ए. मनीमेकलाई का स्थान ले रहे हैं।
- Kalyan Kumar, Executive Director of Punjab National Bank (PNB), has been appointed as MD & CEO of Central Bank of India (CBI) for a three-year tenure, replacing Matam Venkata Rao.
- कल्याण कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक, को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) का MD & CEO तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वे मातम वेंकट राव का स्थान ले रहे हैं।

Ques: Which organisation launched 'Ideabaaz', India's first integrated marketplace for start-ups and investors?

भारत का पहला एकीकृत मंच 'आइडियाबाज़', जो स्टार्टअप्स और निवेशकों को जोड़ता है, किस संगठन ने लॉन्च किया?

- A) SEBI / सेबी
- B) BSE / बीएसई
- C) NSE / एनएसई
- D) SIDBI / सिडबी
- E) Invest India / इन्वेस्ट इंडिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The National Stock Exchange (NSE) launched Ideabaaz, India's first integrated marketplace connecting start-ups with investors.
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने आइडियाबाज़ लॉन्च किया, जो देश का पहला एकीकृत मंच है जहाँ स्टार्टअप्स और निवेशकों को जोड़ा जाएगा।
- The platform aims to nurture India's entrepreneurial spirit and support start-ups in growing into listed companies.
- यह मंच भारत की उद्यमिता भावना को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को- सूचीबद्ध कंपनियों में विकसित करने में मदद करेगा।
- NSE MD & CEO Ashishkumar Chauhan stated that Ideabaaz will empower start-ups and accelerate India's growth journey.
- NSE के प्रबंध निदेशक एवं CEO अशिशकुमार चौहान ने कहा कि आइडियाबाज़ स्टार्टअप्स को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा को गति देगा।
- Mudith Kumar, Co-Founder & COO, emphasized that the platform is creating an inclusive, transparent, and future-ready ecosystem.
- मुदित कुमार, सह संस्थापक एवं-COO, ने कहा कि यह मंच समावेशी, पारदर्शी और भविष्यउन्मुख- इकोसिस्टम बना रहा है।

Ques: Moody's has affirmed India's long-term local and foreign-currency issuer ratings at which level?

मूडीज़ ने भारत की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग किस स्तर पर बरकरार रखी है?

- A. BBB+
- B. BBB
- C. Baa3
- D. A2
- E. P-3

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Moody's Ratings has affirmed India's long-term local and foreign-currency issuer ratings and the local-currency senior unsecured rating at Baa3.
- मूडीज़ रेटिंग्स ने भारत सरकार की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और स्थानीय मुद्रा सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा।
- India's short-term local-currency rating is affirmed at P-3.
- भारत की अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग P-3 पर बरकरार रखी गई है।
- The stable outlook reflects India's credit strengths, including a large, fast-growing economy, sound external position, and resilient domestic financing base.
- स्थिर दृष्टिकोण भारत की क्रेडिट ताकतों को दर्शाता है, जिसमें बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति, और लचीला घरेलू वित्तपोषण आधार शामिल है।
- Challenges remain due to high debt burden, fiscal weaknesses, and external risks such as US tariffs and global policy measures.
- चुनौतियां बनी हुई हैं जैसे उच्च ऋण बोझ, राजकोषीय कमजोरियां और अमेरिकी टैरिफ एवं वैश्विक नीतिगत उपाय जैसी बाहरी जोखिम।
- India's long-term local-currency bond ceiling remains unchanged at A2.
- भारत की दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा बांड सीमा A2 पर अपरिवर्तित रही

Ques: Which insurance company signed a bancassurance agreement with Equitas Small Finance Bank to expand insurance access?

किस इंश्योरेंस कंपनी ने Equitas Small Finance Bank के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकअस्सुरेंस समझौता किया?

- A. ICICI Lombard / ICICI लोम्बार्ड
- B. HDFC ERGO / HDFC ईआरजीओ
- C. TATA AIG General Insurance / TATA AIG जनरल इंश्योरेंस
- D. SBI General Insurance / SBI जनरल इंश्योरेंस
- E. Reliance General Insurance / रिलायंस जनरल इंश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- TATA AIG General Insurance Company signed a bancassurance agreement with Equitas Small Finance Bank (SFB) to expand insurance access across rural and urban areas.
- TATA AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने Equitas Small Finance Bank (SFB) के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकअस्सुरेंस समझौता किया।
- The tie-up aims to strengthen financial protection for households and small businesses in emerging India markets.
- इस साझेदारी का उद्देश्य उभरते भारत के बाजारों में घरों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

About Equitas Small Finance Bank :

- Established : 2016
 - HQ : Chennai, Tamil Nadu
 - MD & CEO : Vasudevan P N
 - Tagline : It's Fun Banking
-

Ques : According to the World Gold Council (WGC), what is India's global rank as an investor in gold ETFs in 2025?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, 2025 में भारत का गोल्ड ईटीएफ निवेशकों में वैश्विक स्थान कौनसा है-?

- A. 5th
- B. 6th
- C. 7th
- D. 8th
- E. 9th

Answer : Option c

Explanation | व्याख्या:

- As per the World Gold Council (WGC), India ranked 7th globally among nations investing in gold ETFs as of September 26, 2025.
 - वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, भारत 26 सितंबर 2025 तक वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रहा।
 - The US led with AUM of \$231.5 billion, followed by UK, Switzerland, Germany, China, and France.
 - अमेरिका शीर्ष पर रहा (\$231.5 अरब), इसके बाद यूके, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चीन और फ्रांस का स्थान रहा।
 - India's AUM stood at \$8.9 billion, equal to Canada, indicating growing interest among Indian investors amid global price volatility and economic uncertainty.
 - भारत का AUM \$8.9 अरब रहा, जो कनाडा के बराबर है, जिससे वैश्विक मूल्य अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारतीय निवेशकों की बढ़ती रुचि दिखाई देती है।
-

Ques : According to the Asian Development Bank (ADB), what is India's GDP growth forecast for FY26?

एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है?

- A. 6.2%
- B. 6.5%
- C. 6.7%
- D. 7.0%
- E. 7.2%

Answer : Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB), in its Asian Development Outlook September 2025 report, has retained India's GDP growth forecast at 6.5% for FY26.
 - एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी एशियाई विकास दृष्टिकोण सितंबर 2025 रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% बनाए रखी है।
 - Strong domestic consumption and robust services exports are cited as key growth drivers.
 - मजबूत घरेलू उपभोग और सेवा निर्यात प्रमुख विकास कारक होंगे।
 - Inflation is expected to ease to 3.1% in FY26, but risks remain from global trade tensions and geopolitical uncertainties.
 - मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 में 3.1% तक घट सकती है, हालांकि वैश्विक व्यापार तनाव और भूराजनीतिक अनिश्चितताओं से जोखिम ब-ने रहेंगे।
 - The services sector will remain the major driver of growth in FY26 and FY27.
 - सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2026 और 2027 में विकास का प्रमुख चालक बना रहेगा।
-

Ques: As per the Controller General of Accounts (CGA), what percentage of the full-year fiscal deficit target had the Centre reached by August-end 2025? महालेख नियंत्रक (CGA) के अनुसार, अगस्त 2025 के अंत तक केंद्र अपने वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का कितने प्रतिशत तक पहुंच चुका था?

- A. 25%
- B. 27%
- C. 33%
- D. 38.1%
- E. 40%

Answer :Option D

Explanation | व्याख्या:

- According to the Controller General of Accounts (CGA), India's fiscal deficit reached 38.1% of the full-year target by the end of August 2025.

- महालेख नियंत्रक (CGA) के अनुसार, अगस्त 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य का 38.1% तक पहुंच गया।
- This was higher compared to the same period of 2024-25, when it was 27% of the Budget Estimates (BE).
- यह 2024-25 की समान अवधि की तुलना में अधिक था, जब यह बजट अनुमान (BE) का 27% था।
- The fiscal deficit in absolute terms stood at ₹5.98 lakh crore during April–August 2025-26.
- सकल रूप में, अप्रैल–अगस्त 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹5.98 लाख करोड़ रहा।
- Fiscal deficit represents the gap between the government's total revenue and total expenditure.
- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर दर्शाता है।

Ques : According to the new RBI guidelines, what flexibility have lenders received regarding EMI-based floating rate personal loans?

नए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, ईएमआईआधारित फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन के - संबंध में ऋणदाताओं को क्या लचीलापन मिला है?

- A) Mandatory switch to fixed rate | फिक्स्ड रेट में स्विच अनिवार्य
- B) No option to switch | स्विच का कोई विकल्प नहीं
- C) Discretion to offer switch at reset | रीसेट के समय स्विच देने का अधिकार
- D) Switch allowed only once during loan tenure | लोन अवधि में केवल एक बार स्विच की अनुमति
- E) Borrower must decide at loan sanction | उधारकर्ता को लोन स्वीकृति पर तय करना होगा

Answer | सही उत्तर: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Earlier, RBI made it mandatory for lenders to provide borrowers the option to switch floating rate EMI-based loans to fixed rate at the time of reset.
- पहले, आरबीआई ने ऋणदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग रेट ईएमआईआधारित लोन को रीसेट के समय फिक्स्ड रेट में बदलने का विकल्प -

दें।

- Now, RBI has left it to the discretion of lenders, offering greater flexibility to banks, NBFCs, and housing finance companies.
- अब, आरबीआई ने यह ऋणदाताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है, जिससे बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अधिक लचीलापन मिला है।
- Banks can also adjust spread components like operating cost, cost of funds, tenor premium, and profit margin earlier than three years if it benefits borrowers.
- बैंकों को यह अनुमति भी है कि वे यदि उधारकर्ताओं को लाभ होता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, फंड की लागत, टेन्योर प्रीमियम और प्रॉफिट मार्जिन को तीन साल से पहले समायोजित कर सकें।

Ques: Which bank, in partnership with Freecharge, launched India's first gold-backed credit line on UPI?

किस बैंक ने फ्रीचार्ज के साथ साझेदारी में भारत की पहली सोने समर्थित क्रेडिट लाइन-UPI पर शुरू की?

- A. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- C. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D. Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- E. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer : Option B

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank, in partnership with Freecharge, launched India's first gold-backed credit line on UPI.
- एक्सिस बैंक ने फ्रीचार्ज के साथ साझेदारी में भारत की पहली सोने समर्थित क्रेडिट लाइन-UPI पर शुरू की।
- The initiative follows the guidelines of NPCI (National Payments Corporation of India).
- यह पहल NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानिर्देशों के अनुसार है।-के दिशा (
- The product is aimed at simplifying working capital access, financing for

business growth, and urgent liquidity needs.

- यह उत्पाद कार्यशील पूंजी की आसान पहुंच, व्यवसाय वृद्धि वित्तपोषण और तात्कालिक तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
- It is designed for MSMEs, self-employed individuals, and merchants, enabling them to leverage gold assets for instant, flexible credit.
- यह एमएसएमई, स्वरोजगार करने वालों और व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जिससे वे अपने सोने की संपत्तियों का उपयोग तुरंत और लचीले क्रेडिट के लिए कर सकें।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: RBL Bank has partnered with which organization for a bancassurance agreement?

RBL बैंक ने बैंकएश्योरेंस समझौते के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है?

- A. SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
- B. HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
- C. Max Life Insurance / मैक्स लाइफ इंश्योरेंस
- D. Life Insurance Corporation of India (LIC) / भारतीय जीवन बीमा निगम)LIC)
- E. ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

- RBL Bank entered into a bancassurance partnership with LIC, India's largest life insurer.
- RBL बैंक ने भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम)LIC) के साथ बैंकएश्योरेंस साझेदारी समझौता किया।
- This tie-up enables RBL Bank customers to access the entire range of LIC's life insurance products.

- इस साझेदारी से RBL बैंक के ग्राहक LIC के सभी जीवन बीमा उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे।
- Products will be available through RBL Bank's branch network and digital channels.
- ये उत्पाद RBL बैंक की शाखाओं और डिजिटल चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
- The collaboration aims to boost insurance penetration and offer comprehensive financial solutions.
- यह साझेदारी बीमा कवरेज बढ़ाने और समग्र वित्तीय समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

Ques : For Q3 FY26 (Oct–Dec 2025), what is the interest rate for the Public Provident Fund (PPF)?

वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (दिसंबर-अक्टूबर) 2025) के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की ब्याज दर क्या है?

- A) 7.5%
- B) 7.7%
- C) 8.2%
- D) 7.1%
- E) 6.9%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Finance Ministry confirmed that for Oct–Dec 2025 (Q3 FY26), the PPF interest rate remains unchanged at 7.1%.
- वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि अक्टूबर-दिसंबर-2025 (Q3 FY26) के लिए पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% अपरिवर्तित रहेगी।
- Other small savings schemes like Sukanya Samriddhi (8.2%), NSC (7.7%), and Kisan Vikas Patra (7.5%) also remain unchanged.
- अन्य छोटी बचत योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि (8.2%), एनएससी (7.7%), और किसान विकास पत्र (7.5%) भी अपरिवर्तित रहेंगी।
- These schemes are mostly operated by post offices and banks, with both principal and interest guaranteed by the Government of India.
- ये योजनाएं मुख्य रूप से डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित होती हैं और इनमें मूलधन और ब्याज भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत होता है।

**Ques : RBI's "Scheme for Facilitating Accelerated Payout – Inoperative Accounts and Unclaimed Deposits" will be effective for which period?
आरबीआई की "Scheme for Facilitating Accelerated Payout – Inoperative Accounts and Unclaimed Deposits" किस अवधि के लिए लागू होगी?**

- A. April 2025 – March 2026
- B. October 2025 – September 2026
- C. January 2025 – December 2025
- D. July 2025 – June 2026
- E. None of these

Answer : Option B

Explanation | व्याख्या:

- The RBI launched the "Payout Structure" scheme to encourage banks to trace inactive customers and return unclaimed deposits.
- RBI ने "पेवआउट स्ट्रक्चर" योजना शुरू की है ताकि बैंकों को निष्क्रिय खाताधारकों तक पहुँचने और अनक्लेम्ड जमा राशि लौटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- Duration: October 1, 2025 – September 30, 2026 (one-year scheme).
- अवधि: 1 अक्टूबर 2025 – 30 सितम्बर 2026 (एक वर्ष की योजना)।
- Under the scheme, banks will receive differential payouts based on account inactivity period and deposit amount, which encourages reactivation of dormant accounts.
- इस योजना के तहत, बैंक खाते की निष्क्रिय अवधि और जमा राशि के आधार पर भुगतान प्राप्त करेंगे, जिससे निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने में मदद मिलेगी।

Example of Payout Structure | भुगतान संरचना उदाहरण:

अवधि (Years)	भुगतान प्रतिशत	अधिकतम राशि (Whichever is less)
Up to 4	5% of amount	₹5,000
4–8	6% of amount	₹10,000
8–10	7% of amount	₹15,000
10+ (Unclaimed with DEA Fund)	7.5% of amount	₹25,000

- This **one-year scheme** motivates banks to locate customers, reactivate accounts, and ensure rightful claimants receive their unclaimed deposits.
- यह एक वर्ष की योजना बैंकों को ग्राहकों तक पहुँचाने, खातों को पुनः सक्रिय करने और सही दावेदारों को उनकी अनक्लेम्ड राशि लौटाने के लिए प्रेरित करती है।

Ques: What type of deposit insurance premium model has been proposed by the Reserve Bank of India (RBI)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस प्रकार का डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम मॉडल प्रस्तावित किया है?

- A. Flat-rate premium model / समान दर प्रीमियम मॉडल
- B. Interest-linked premium model / ब्याजआधारित प्रीमियम मॉडल-
- C. Risk-based premium model / जोखिमआधारित प्रीमियम मॉडल-
- D. Credit growth-based model / ऋणवृद्धि आधारित मॉडल-
- E. Market-linked model / बाजारसंलग्न मॉडल-

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed a risk-based deposit insurance premium model, replacing the earlier flat-rate system where all banks paid a uniform premium of 12 paise per ₹100 of deposits to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पुराने फ्लैटरेट सिस्टम को बदलते हुए- जोखिमआधारित - डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें सभी बैंक समान प्रीमियम नहीं देंगे।
- Under this model, financially stronger and well-managed banks will pay lower premiums, while weaker banks will pay higher premiums.
- इस मॉडल के तहत वित्तीय रूप से मजबूत और सुव्यवस्थित बैंक कम प्रीमियम, और कमजोर बैंक अधिक प्रीमियम देंगे।
- Importantly, the deposit insurance cover of ₹5 lakh per depositor per bank (including principal and interest) will remain unchanged.
- महत्वपूर्ण रूप से, प्रत्येक जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अपरिवर्तित रहेगी।

- Detailed guidelines for implementation will be issued soon, likely effective from FY 2026.
- इस मॉडल को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे और यह अगले वित्त वर्ष (FY 2026) से लागू होने की संभावना है।

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) :

- Established: 1961
- Headquarters: Mumbai
- Parent Organisation: Reserve Bank of India (RBI)
- Current Deposit Insurance Cover: ₹5 lakh per depositor per bank
- Current Premium (before change): ₹0.12 per ₹100 of deposits (Flat Rate)

Ques: By how much has RBI recently raised the limits for IPO financing and loans against shares?

RBI ने हाल ही में IPO फाइनेंसिंग और शेयरों के खिलाफ लोन की सीमा कितनी बढ़ाई है?

- A. ₹10 Lakh to ₹20 Lakh
- B. ₹10 Lakh to ₹25 Lakh and ₹20 Lakh to ₹50 Lakh
- C. ₹10 Lakh to ₹25 Lakh and ₹20 लाख to ₹1 Crore
- D. ₹5 Lakh to ₹15 Lakh
- E. ₹5 Lakh to ₹35 Lakh

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed raising the IPO financing limit from ₹10 lakh to ₹25 lakh per individual.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने IPO फाइनेंसिंग सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव रखा है।
- The limit for Loans Against Shares (LAS) will increase sharply from ₹20 lakh to ₹1 crore.
- Loans Against Shares (LAS) की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ की जाएगी।
- These higher limits also apply to REITs and InvITs, aiming to encourage High-Net-Worth Individuals (HNIs) and deepen engagement in the primary market.

- ये बढ़ी हुई सीमाएं REITs और InvITs पर भी लागू होंगी, जिसका उद्देश्य उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों (HNIs) की भागीदारी बढ़ाना और प्राथमिक बाजार में गहराई लाना है।
- RBI noted that these limits were unchanged for many years despite improvements in banking capacity, necessitating the update.
- RBI ने कहा कि बैंकिंग क्षमता में सुधार के बावजूद ये सीमाएं कई वर्षों से अपरिवर्तित थीं, इसलिए अब उन्हें अपडेट किया जा रहा है।

Ques: The newly formed Payments Regulatory Board (PRB) by RBI replaces which of the following?

RBI द्वारा गठित नया भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) निम्नलिखित में से किसकी जगह बना है?

- A. Board for Financial Supervision (BFS) / वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
- B. Monetary Policy Committee (MPC) / मौद्रिक नीति समिति
- C. Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS) / भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
- D. Financial Stability Board (FSB) / वित्तीय स्थिरता बोर्ड
- E. Digital Payment Council (DPC) / डिजिटल भुगतान परिषद

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has constituted a six-member Payments Regulatory Board (PRB) under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, replacing the earlier Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS), which was a committee of the RBI Central Board.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छहसदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) को भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत गठित किया है, और इसने पहले के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह ली, जो RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति थी।
- Unlike the earlier five-member BPSS, the new PRB includes government nominees, giving the government a role in payment system oversight.
- पहले के पांच सदस्यीय-BPSS के विपरीत, नए PRB में सरकारी नामांकित सदस्य शामिल हैं, जिससे सरकार को भुगतान प्रणाली की निगरानी में भूमिका मिली है।

Ques: Which major reforms did the RBI recently announce for the cooperative banking sector?

आरबीआई ने हाल ही में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए कौन से प्रमुख सुधारों की घोषणा की है?

- A. Introduction of new digital banking platforms / नए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत
- B. Reexamination of licensing framework for UCBs and expansion of grievance redressal system / UCBs के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की पुनः समीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार
- C. Merger of all cooperative banks with commercial banks / सभी सहकारी बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों के साथ विलय
- D. Reduction in repo rate for cooperative banks / सहकारी बैंकों के लिए रेपो दर में कमी
- E. Introduction of private equity participation in cooperative banks / सहकारी बैंकों में निजी इक्विटी भागीदारी की शुरुआत

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced two landmark proposals with significant implications for the cooperative banking sector.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की, जिनका व्यापक प्रभाव होगा।
- RBI Governor Sanjay Malhotra stated that the central bank will reexamine the licensing framework for Urban Co-operative Banks (UCBs) after more than two decades, as licensing for new UCBs has been paused since 2004 due to supervisory and governance concerns.
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की दो दशकों से अधिक समय बाद पुनः समीक्षा करेगा, क्योंकि 2004 से नई UCBs के लिए लाइसेंसिंग रुक गई थी, निगरानी और शासन संबंधी चिंताओं के कारण।
- Additionally, the RBI announced a major consumer-centric reform by revamping its grievance redressal system.
- इसके साथ ही, आरबीआई ने अपने शिकायत निवारण प्रणाली को पुनर्गठित कर एक महत्वपूर्ण उपभोक्ताकेंद्रित सुधार की घोषणा की।

- The Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), which currently covers commercial banks, NBFCs, and select financial entities, will now be extended to include rural cooperative banks for the first time.
- एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), जो वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं को कवर करती है, अब ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा।
- This means District Central Cooperative Banks (DCCBs) and State Cooperative Banks (StCBs) will come under the direct ambit of RBI's ombudsman mechanism.
- इसका मतलब है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंक (StCBs) अब सीधे आरबीआई के ओम्बड्समैन तंत्र के अंतर्गत आएंगे।

Ques: Which major step has been taken by RBI in its final guidelines on "Forms of Business and Prudential Regulation for Investments"?

RBI ने "Forms of Business and Prudential Regulation for Investments" की अंतिम गाइडलाइन्स में कौन सा प्रमुख कदम उठाया है?

- A. Increased capital requirement for NBFCs / NBFCs के लिए पूंजी आवश्यकता बढ़ाई
- B. Removed proposed restriction on overlap between banks and group entities / बैंकों और समूह संस्थाओं के बीच ओवरलैप पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटाया
- C. Imposed limits on banks' lending to NBFCs / NBFCs को बैंक से उधार लेने पर सीमा लगाई
- D. Restricted IPO participation of bank subsidiaries / बैंक सहायक कंपनियों की IPO भागीदारी प्रतिबंधित की
- E. Introduced new investment ceiling for mutual funds / म्यूचुअल फंड्स के लिए नई निवेश सीमा लागू की

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has withdrawn the earlier proposed restrictions on overlapping business activities between banks and their group entities, including NBFCs and investment arms.
- आरबीआई ने बैंकों और उनकी समूह इकाइयों (जैसे) NBFCs और निवेश शाखाओं के बीच (

समान व्यवसाय करने पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटा दिया है।

- This decision allows large private banks like HDFC, ICICI, Axis, and Kotak to maintain operational flexibility and pursue strategic business plans for their subsidiaries.
- इस निर्णय से HDFC, ICICI, Axis और Kotak जैसे बड़े निजी बैंक अपनी संचालनात्मक लचीलापन बनाए रख सकेंगे और अपनी सहायक कंपनियों के लिए रणनीतिक योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे।
- The move also eases IPO and investment plans for group NBFCs, which were earlier impacted by the overlap rule.
- इस कदम से समूह NBFCs के IPO और निवेश योजनाओं में पहले लगे ओवरलैप नियम का प्रभाव कम होगा।

Ques: In October 2025, the RBI's Monetary Policy Committee decided to keep the repo rate unchanged at –

अक्टूबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर यथावत रखा?

- A. 5.25%
- B. 5.5%
- C. 5.75%
- D. 6%
- E. 6.25%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) decided to keep the benchmark repo rate unchanged at 5.5% in its October 2025 meeting — the second consecutive time.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अक्टूबर 2025 की बैठक में बेंचमार्क रेपो रेट को 5.5% पर यथावत रखा, जो लगातार दूसरी बार है।
- The policy stance was also maintained as 'Neutral'.
- नीति का रुख भी 'न्यूट्रल' (तटस्थ) रखा गया।
- Accordingly, Standing Deposit Facility (SDF) Rate is 5.25%, Marginal Standing Facility (MSF) Rate & Bank Rate is 5.75%.

- इसके अनुसार, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर तथा बैंक रेट 5.75% है।
- RBI noted that the overall inflation outlook has turned more benign due to a sharp fall in food prices. The average headline inflation for FY25 has been revised down to 2.6% from the earlier 3.1%.
- आरबीआई ने कहा कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अब अधिक स्थिर हो गया है, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज गिरावट के कारण। FY25 के लिए औसत मुद्रास्फीति दर को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया है।
- The FY26 GDP growth projection has been revised upward to 6.8% from the earlier estimate of 6.5%.
- FY26 की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है।
- RBI also announced a Risk-Based Premium Framework for Deposit Insurance, allowing financially sound banks to pay lower premiums, effective from the next financial year.
- RBI ने डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए जोखिमआधारित प्रीमियम ढांचा- लागू करने की घोषणा की, जिससे वित्तीय रूप से सशक्त बैंक कम प्रीमियम देंगे। यह अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा।

Ques: Which institution recently unveiled its most comprehensive reforms in over a decade to expand corporate credit and deepen capital market activity?

किस संस्था ने हाल ही में एक दशक से अधिक समय में अपने सबसे व्यापक सुधारों का अनावरण किया है ताकि कॉर्पोरेट ऋण का विस्तार हो और पूंजी बाजार की गतिविधि गहराई जाए?

- A. Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- B. Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- C. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- D. NITI Aayog / नीति आयोग
- E. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India unveiled its most comprehensive reforms in over a decade, aimed at countering US-driven headwinds and expanding credit to companies while deepening capital market activity.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक दशक से अधिक समय में अपने सबसे व्यापक सुधारों का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करना और कॉर्पोरेट ऋण के विस्तार के साथ पूंजी बाजार की गतिविधियों को गहराई देना है।
- Banks can now finance mergers, acquisitions, and IPOs more freely, while limits on loans against shares and listed debt securities have been raised.
- बैंक अब विलय, अधिग्रहण और आईपीओ को अधिक स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित कर सकेंगे, साथ ही शेयरों और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण सीमा भी बढ़ा दी गई है।
- Borrowing rules for companies with loans above Rs 10,000 crore have been eased by removing earlier caps and extra capital requirements.
- 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वाली कंपनियों के लिए उधार नियमों को आसान बनाया गया है, पहले की सीमा और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को हटाकर।
- Loans against shares have been increased from Rs 20 lakh to Rs 1 crore per individual, and IPO financing limits from Rs 10 lakh to Rs 25 lakh per person.
- शेयरों के विरुद्ध ऋण की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है, और आईपीओ वित्तपोषण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है।
- These reforms, effective from October 2025, aim to expand credit access, improve liquidity, and encourage broader participation in equity markets.
- ये सुधार, जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे, का उद्देश्य ऋण पहुंच का विस्तार करना, तरलता में सुधार करना और इक्विटी बाजारों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

Ques: What is the main objective of RBI's proposal to reduce risk weights for NBFCs' infrastructure loans?

RBI के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें NBFCs के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर जोखिम भार घटाने की बात कही गई है?

- A. To increase tax benefits for NBFCs / NBFCs के लिए कर लाभ बढ़ाना
- B. To reduce cost of infrastructure financing and promote long-term lending / इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की लागत कम करना और दीर्घकालिक ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना
- C. To stop NBFCs from giving infra loans / NBFCs को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने से रोकना
- D. To merge NBFCs with banks / NBFCs को बैंकों में विलय करना

E. To raise deposit insurance limit / जमा बीमा सीमा बढ़ाना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has proposed reducing risk weights for NBFCs' loans to operational and high-quality infrastructure projects.
 - आरबीआई ने NBFCs द्वारा संचालित और उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जोखिम भार घटाने का प्रस्ताव रखा है।
 - This move will lower financing costs for NBFCs and encourage more long-term, sound lending in the infrastructure sector.
 - इस कदम से NBFCs की फाइनेंसिंग लागत कम होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दीर्घकालिक और सुरक्षित ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।
 - The framework also ensures better risk assessment and capital optimization, while promoting competitiveness among NBFCs.
 - यह ढांचा बेहतर जोखिम मूल्यांकन और पूंजी अनुकूलन सुनिश्चित करेगा, साथ ही NBFCs के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा।
-

Ques: Which ministry is coordinating the nationwide campaign “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” — Your Money, Your Right?

“आपकी पूंजी, आपका अधिकार” — Your Money, Your Right नामक राष्ट्रीय अभियान का समन्वय कौन सा मंत्रालय कर रहा है?

- A. Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- B. Ministry of Consumer Affairs / उपभोक्ता मामले मंत्रालय
- C. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- D. Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- E. Ministry of Labour / श्रम मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Financial Services (DFS) under the Ministry of Finance is

coordinating the nationwide awareness campaign on unclaimed financial assets in collaboration with RBI, IRDAI, SEBI, and IEPFA.

- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) इस अभियान का समन्वय RBI, IRDAI, SEBI, और IEPFA के सहयोग से कर रहा है।
- The campaign, titled “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” (Your Money, Your Right), will run from October to December 2025 and aims to guide citizens on claiming their unclaimed financial assets.
- यह अभियान “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” शीर्षक से अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी अप्राप्त वित्तीय संपत्तियों का दावा करने में मार्गदर्शन देना है।

Ques: What new facility has the RBI allowed for NRIs regarding investment in India?

भारत में निवेश के संबंध में RBI ने NRI को कौन सी नई सुविधा दी है?

- A. NRIs can invest in Indian mutual funds through rupee accounts. / NRI रुपये खातों से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
- B. NRIs can invest in Indian debt market through rupee accounts. / NRI रुपये खातों से भारतीय ऋण बाजार में निवेश कर सकते हैं।
- C. NRIs can invest in real estate using rupee accounts. / NRI रुपये खातों से रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं।
- D. NRIs can invest in gold bonds only. / NRI केवल गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
- E. NRIs can open rupee accounts for remittance only. / NRI रुपये खाते केवल प्रेषण के लिए खोल सकते हैं।

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has amended the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, to allow NRIs to invest in non-convertible debentures (NCDs), bonds, and commercial papers through their rupee accounts.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (जमा), 2016 में संशोधन किया है ताकि NRI रुपये खातों के माध्यम से गैरपरिवर्तनीय डिबेंचर-, बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों में

निवेश कर सकें।

- This facility aims to facilitate debt investment, strengthen the internationalisation of the Indian rupee, boost India's debt market, reduce borrowing costs, and support GDP growth, especially in infrastructure and renewable energy sectors.
- इस सुविधा का उद्देश्य ऋण निवेश को सुगम बनाना, रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को मजबूत करना, भारत के ऋण बाजार को बढ़ावा देना, उधारी की लागत को कम करना और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में GDP वृद्धि को बढ़ावा देना है।

Ques: What is the purpose of the Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) platform launched by SEBI?

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा लॉन्च किए गए म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA) प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है?

- A. To provide tax benefits on mutual fund investments / म्यूचुअल फंड निवेश पर कर लाभ प्रदान करना
- B. To help investors track and reclaim inactive or unclaimed mutual fund folios / निवेशकों को निष्क्रिय या अप्राप्त म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने में मदद करना
- C. To offer high-risk mutual fund schemes / उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड योजनाएं पेश करना
- D. To facilitate direct mutual fund purchases without brokers / ब्रोकर के बिना सीधे म्यूचुअल फंड खरीदने की सुविधा प्रदान करना
- E. To provide educational courses on mutual fund investing / म्यूचुअल फंड निवेश पर शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- SEBI launched the Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) to help investors track and reclaim inactive or unclaimed Mutual Fund folios.
- SEBI ने निवेशकों को निष्क्रिय या अप्राप्त म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA)

लॉन्च किया।

- The platform was introduced under SEBI's regulatory powers to protect investor interests and promote orderly development of the securities market.
- यह प्लेटफॉर्म निवेशक हितों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए SEBI के नियामक शक्तियों के तहत पेश किया गया।
- MITRA is jointly managed by two Qualified Registrar and Transfer Agents: CAMS and KFin Technologies Limited.
- MITRA का प्रबंधन दो योग्य रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट्स, CAMS और KFin Technologies Limited, द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

Ques: Who has joined the board of the Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE) as an Independent Director?

फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (FACE) के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसने बोर्ड जॉइन किया है?

- A. M. Rajeshwar Rao / एमराजेश्वर राव .
- B. T. Rabi Sankar / टीरबी शंकर .
- C. Manoranjan Mishra / मनोरंजन मिश्रा
- D. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E. Sugandh Saxena / सुगंध सक्सेना

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Former RBI Executive Director Manoranjan Mishra has been appointed as an Independent Director on the board of the Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE).
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (FACE) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- FACE, recognized by RBI as an SRO-FT, is a self-regulatory body for fintech companies in India.
- FACE, जिसे RBI द्वारा SRO-FT के रूप में मान्यता प्राप्त है, भारत में फिनटेक कंपनियों के लिए एक स्वनियामक संस्था है।-

- Mishra's experience is expected to guide FACE in promoting innovation, growth, development, and consumer protection in the fintech sector.
- मिश्रा का अनुभव FACE को फिनटेक क्षेत्र में नवाचार, विकास और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

Ques: What is the new deadline set by SEBI for the complete rollout of algorithm trading rules for retail investors?

SEBI ने खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग नियमों के पूर्ण कार्यान्वयन की नई समय सीमा क्या तय की है?

- A. October 01, 2025
- B. January 03, 2026
- C. August 01, 2025
- D. November 30, 2025
- E. April 01, 2026

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has extended the deadline for the complete rollout of algorithm trading rules for retail investors to April 01, 2026.
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग नियमों के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा 1 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है।
- Retail Algo Trading allows investors to use automated trading strategies through computer programs.
- रिटेल एल्गो ट्रेडिंग निवेशकों को कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने की अनुमति देती है।
- The framework, initially set for August 01, 2025, was first deferred to October 01, 2025, and now extended further.
- यह ढांचा पहले 1 अगस्त 2025 से लागू होना था, फिर इसे 1 अक्टूबर 2025 तक स्थगित किया गया और अब आगे बढ़ाया गया है।
- Brokers failing to meet these milestones will be barred from onboarding new retail clients after January 05, 2026.
- जो ब्रोकर्स इन माइलस्टोन का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 5 जनवरी 2026 से नए रिटेल

क्लाइंट जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

- The complete algo framework will become mandatory for all brokers from April 01, 2026.
- पूरा एल्गो फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से सभी ब्रोकर्स के लिए अनिवार्य होगा।

SEBI has introduced a glide path with 3 key milestones for phased implementation:

SEBI ने चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए 3 प्रमुख माइलस्टोन तय किए हैं:

- Milestone 1: Brokers must apply for registration of at least one retail algo strategy by October 31, 2025.
- माइलस्टोन 1: 31 अक्टूबर 2025 तक कम से कम एक रिटेल एल्गो रणनीति के पंजीकरण के लिए आवेदन।
- Milestone 2: Full registration of retail algo products by November 30, 2025.
- माइलस्टोन 2: 30 नवंबर 2025 तक एल्गो उत्पादों का पूरा पंजीकरण।
- Milestone 3: Brokers must participate in a mock trading session by January 03, 2026.
- माइलस्टोन 3: 3 जनवरी 2026 तक मॉक ट्रेडिंग सत्र में भाग लेना।

Ques: Which organisation has been granted SRO status by the RBI for the non-bank lending sector?

गैरबैंकिंग ऋण क्षेत्र के लिए RBI ने किस संगठन को SRO का दर्जा दिया है?

- A. NAFR / NAFR
- B. FINO Council / FINO काउंसिल
- C. FIDC / FIDC
- D. MFIN / MFIN
- E. IBA / IBA

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) granted Self-Regulatory Organisation (SRO) status to the Finance Industry Development Council (FIDC) to promote self-

regulation and ensure compliance in the non-bank lending sector.

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को गैरबैंकिंग - ऋण क्षेत्र में आत्म नियमन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए-SRO का दर्जा दिया है।
- FIDC is a representative body of NBFCs registered with the RBI and will help improve governance, transparency, and fair representation for smaller NBFCs.
- FIDC, RBI के साथ पंजीकृत NBFCs का एक प्रतिनिधि संगठन है और यह प्रशासन, पारदर्शिता और छोटे NBFCs के लिए उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- To be recognised as an SRO, FIDC meets conditions like being a non-profit under Section 8 of the Companies Act, having minimum net worth of ₹2 crore, and including at least 10% of Base Layer NBFCs as members.
- SRO के रूप में मान्यता पाने के लिए FIDC गैररि संस्था होना चाहिएलाभका-, न्यूनतम ₹2 करोड़ की निवल संपत्ति हो और बेस लेयर के कम से कम 10% NBFCs को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा।

Ques: From which date will UIDAI's revised Aadhaar service charges become effective?

UIDAI की संशोधित आधार सेवा शुल्क दरें किस तारीख से प्रभावी होंगी?

- A. July 1, 2025 / 1 जुलाई 2025
- B. October 1, 2025 / 1 अक्टूबर 2025
- C. January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026
- D. September 30, 2025 / 30 सितंबर 2025
- E. April 1, 2026 / 1 अप्रैल 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- UIDAI announced a revision in Aadhaar-related service charges, effective from October 1, 2025, to September 30, 2028.
- UIDAI ने आधार सेवाओं के शुल्कों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा।
- Under the new rates, ₹50 services will increase to ₹75, and ₹100 services will

increase to ₹125. From October 2028, these will further rise to ₹90 and ₹150 respectively.

- नई दरों के अनुसार, ₹50 की सेवाओं की फीस ₹75 और ₹100 की सेवाओं की फीस ₹125 होगी। अक्टूबर 2028 से यह क्रमशः ₹90 और ₹150 हो जाएगी।
- Biometric updates for children aged 5–7 and 15–17 years will remain free, while updates for 7–15-year-olds will be free until September 30, 2026, to reduce Mandatory Biometric Update (MBU) pendency.
- 5–7 और 15–17 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निशुल्क रहेंगे; जबकि 7–15 वर्ष के बच्चों के लिए यह 30 सितंबर 2026 तक निशुल्क रहेगा ताकि MBU लंबित मामलों को कम किया जा सके।

Ques: As per the draft Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) Directions, 2025 issued by the Reserve Bank of India (RBI), by when will the new framework be implemented?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार नया ढांचा कब तक लागू किया जाएगा?

- A. December 31, 2025
- B. January 31, 2026
- C. April 30, 2026
- D. March 31, 2026
- E. June 30, 2026

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) issued the draft of the Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) Directions, 2025, applicable to all banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों पर लागू होने वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA) दिशानिर्देश, 2025 का मसौदा जारी किया।
- The framework is set to be implemented by March 31, 2026.
- यह ढांचा 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा।
- Every bank must offer BSBD accounts with certain minimum facilities free of charge, regardless of a minimum balance.
- प्रत्येक बैंक को न्यूनतम बैलेंस की परवाह किए बिना कुछ न्यूनतम सुविधाओं के साथ मुफ्त

BSBD खाता प्रदान करना अनिवार्य होगा।

- These free facilities include an ATM/Debit Card (with no annual fee), a cheque book with at least 25 leaves per year, and internet/mobile banking.
- इन मुफ्त सेवाओं में एटीएम(बिना वार्षिक शुल्क) डेबिट कार्ड/, प्रति वर्ष कम से कम 25 पन्नों वाली चेक बुक, और इंटरनेटमोबाइल बैंकिंग शामिल हैं।/
- A minimum of four free withdrawals per month is allowed, excluding digital payments like UPI, NEFT, RTGS, IMPS, etc.
- प्रति माह न्यूनतम चार मुफ्त निकासी की अनुमति दी जाएगी, जिसमें UPI, NEFT, RTGS, IMPS आदि जैसे डिजिटल भुगतान शामिल नहीं होंगे।
- Account holders cannot maintain another savings account in the same or any other bank simultaneously.
- खाता धारक एक ही समय में उसी या किसी अन्य बैंक में कोई अन्य बचत खाता नहीं रख सकते।

Ques: Which two initiatives has SEBI launched to enhance payment security and curb fraudulent fund collections?

भुगतान सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी वाले फंड संग्रह को रोकने के लिए सेबी ने कौन सी दो पहलें शुरू की हैं?

- A. UPI Safe & SEBI Verify / यूपीआई सेफ और सेबी वेरीफाई
- B. Validated UPI Handles & SEBI Check / वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल और सेबी चेक
- C. Investor Shield & UPI Trust / इन्वेस्टर शील्ड और यूपीआई ट्रस्ट
- D. Saarthi Pay & SafeHandle / सार्थी पे और सेफ हैंडल
- E. SEBI SecurePay & UPI Trust / सेबी सिक्योरपे और यूपीआई ट्रस्ट

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- SEBI launched Validated UPI Handles and SEBI Check to ensure secure payments and reduce fraud in fund transactions.
- सेबी ने Validated UPI Handles और SEBI Check की शुरुआत की ताकि भुगतान सुरक्षित रहें और फंड ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी को कम किया जा सके।
- A new exclusive “@valid” UPI handle will be used by SEBI-registered intermediaries, including brokers and mutual funds, with category-specific

suffixes like “.brk” for brokers and “.mf” for mutual funds.

- नया “@valid” यूपीआई हैंडल अब सेबीम्यूचुअल पंजीकृत बिचौलियों जैसे ब्रोकर और-फंड्स द्वारा उपयोग किया जाएगा, जिसमें “.brk” ब्रोकरों और “.mf” म्यूचुअल फंड्स के लिए श्रेणीविशिष्ट प्रत्यय होंगे।
- SEBI Check allows investors to independently verify bank account details and UPI IDs of intermediaries through the Saarthi app or SEBI’s platform.
- SEBI Check निवेशकों को सार्थी ऐप या सेबी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिचौलियों के बैंक खाता विवरण और यूपीआई ID की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की सुविधा देता है।

Ques: Which organisation has provided a USD 190 million loan for the Indore Metro Rail Project?

किस संगठन ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है?

- A. World Bank / विश्व बैंक
- B. International Monetary Fund (IMF) / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- C. New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- D. Japan International Cooperation Agency (JICA) / जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)
- E. Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (ADB)

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has approved a USD 190 million loan for the Indore Metro Rail Project in Madhya Pradesh.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मध्य प्रदेश की इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है।
- The project is being implemented by the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) and is expected to be operational by January 2030.
- इस परियोजना को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) द्वारा लागू किया जा रहा है और इसे जनवरी 2030 तक चालू करने की योजना है।
- The loan will finance the construction of an 8.62 km-long underground metro

line with 7 stations to enhance urban mobility and reduce traffic congestion in Indore.

• यह ऋण 8.62 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन के 7 स्टेशनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे इंदौर में शहरी परिवहन में सुधार और यातायात जाम में कमी आएगी।

Ques: As per RBI's draft proposal, what is the maximum materiality threshold for lending to related parties for large banks with asset size above ₹10 lakh crore?

आरबीआई के ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार, ₹10 लाख करोड़ से अधिक परिसंपत्ति वाले बड़े बैंकों के लिए संबंधित पक्षों को ऋण देने की अधिकतम सीमा क्या होगी?

- A. ₹5 crore
- B. ₹10 crore
- C. ₹25 crore
- D. ₹50 crore
- E. ₹1 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- RBI's draft framework proposes scale-based materiality thresholds for banks and NBFCs for loans to related parties, including personal loans to directors.
- आरबीआई के ड्राफ्ट ढांचे के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी के लिए संबंधित पक्षों को दिए जाने वाले ऋणों पर स्केल-आधारित मटीरियलिटी सीमा प्रस्तावित की गई है, जिसमें निदेशकों को व्यक्तिगत ऋण भी शामिल हैं।
- For large banks with assets above ₹10 lakh crore, the maximum permissible lending limit to related parties is ₹50 crore. Smaller banks have proportionately lower thresholds (₹5 crore and ₹10 crore).
- ₹10 लाख करोड़ से अधिक परिसंपत्ति वाले बड़े बैंकों के लिए संबंधित पक्षों को ऋण देने की अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ होगी। छोटे बैंकों के लिए यह क्रमशः ₹5 करोड़ और ₹10 करोड़ निर्धारित है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has granted an extension of tenure to Raghavendra Srinivas Bhat as MD & CEO of which bank?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट के कार्यकाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बढ़ाया है?

- A. South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
- B. Karnataka Bank / कर्नाटक बैंक
- C. Federal Bank / फेडरल बैंक
- D. Karur Vysya Bank / करूर वैश्य बैंक
- E. City Union Bank / सिटी यूनियन बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved a one-month extension in the tenure of Raghavendra Srinivas Bhat as the MD & CEO of Karnataka Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट को कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एक माह का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है।
- The extension will be effective from October 16, 2025, or until the appointment of a regular MD & CEO, whichever is earlier.
- यह विस्तार 16 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा या नियमित एमडी और सीईओ की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो।
- Karnataka Bank is a private sector bank headquartered in Mangaluru, Karnataka.
- कर्नाटक बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

Ques: Which reforms were announced by the Reserve Bank of India (RBI) alongside the Monetary Policy Committee (MPC) meeting to strengthen the banking sector?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के साथ कौन से सुधारों की घोषणा की?

- A. Risk Based Premium Framework, ECL Provisioning, Revised Basel III norms, Capital Market Lending Reforms / जोखिम आधारित प्रीमियम ढांचा, ECL प्रावधान,

संशोधित बेसल III मानदंड, पूंजी बाजार ऋण सुधार

B. Repo Rate Cut, CRR Hike, Forex Market Reforms, NBFC Liquidity Scheme / रेपो दर में कटौती, सीआरआर वृद्धि, विदेशी मुद्रा बाजार सुधार, एनबीएफसी तरलता योजना

C. Digital Rupee Expansion, Credit Card Framework, UPI Internationalisation, Bond Market Reform / डिजिटल रुपया विस्तार, क्रेडिट कार्ड ढांचा, यूपीआई अंतर्राष्ट्रीयकरण, बॉन्ड बाजार सुधार

D. Gold Monetisation Scheme, Banking Merger Policy, Priority Sector Lending Expansion / स्वर्ण मुद्राकरण योजना, बैंकिंग विलय नीति, प्राथमिक क्षेत्र ऋण विस्तार

E. Inflation Targeting Framework, FPI Investment Reform, Exchange Rate Stabilisation Measures / मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचा, एफपीआई निवेश सुधार, विनिमय दर स्थिरीकरण उपाय

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced four major reforms alongside the Monetary Policy Committee (MPC) meeting to enhance the resilience of the banking sector and streamline regulatory processes.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के साथ बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और नियामक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख सुधारों की घोषणा की।

Risk Based Premium Framework for Deposit Insurance

- Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) will now charge banks based on their risk profile instead of a flat rate of 12 paise per ₹100 of deposits.
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अब बैंकों से उनकी जोखिम प्रोफाइल के आधार पर प्रीमियम वसूलेगा, न कि ₹100 पर 12 पैसे की समान दर पर।

Expected Credit Loss (ECL) Provisioning Framework

- Replaces the "Incurred Loss Model" with a forward-looking system where banks estimate potential future losses based on borrower risk, repayment history, and economic conditions.
- यह "Incurred Loss Model" को बदलकर एक अग्रिम अनुमान मॉडल लाता है, जिसमें

बैंक उधारकर्ता की जोखिम प्रोफ़ाइल, पुनर्भुगतान इतिहास और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के संभावित नुकसान का अनुमान लगाते हैं।

Revised Basel III Capital Adequacy Norms

- To be effective from April 1, 2027, the updated framework lowers capital requirements for MSME and residential real estate loans, enhancing credit flow.
- 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होने वाले संशोधित ढांचे के तहत MSME और आवासीय रियल एस्टेट ऋणों के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम किया गया है, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार होगा।

Broadening Capital Market Lending Scope

- Banks can now finance acquisitions by Indian corporations and have enhanced limits for lending against shares.
- बैंकों को अब भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण करने और शेयरों के विरुद्ध ऋण देने की सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

About Expected Credit Loss (ECL) : Instead of waiting for a borrower to default, banks will now estimate how much loss they might face in the future — based on the borrower's risk profile, repayment history, economic conditions, etc

Ques: As per RBI's new draft ECB framework, what is the maximum amount firms can raise without prior approval?

आरबीआई के नए ईसीबी ड्राफ्ट के अनुसार, कंपनियां बिना पूर्व अनुमति के अधिकतम कितनी राशि तक उधार ले सकती हैं?

- A. \$500 million / \$500 मिलियन
- B. \$750 million / \$750 मिलियन
- C. \$1 billion or 300% of net worth (whichever is higher) / \$1 बिलियन या नेट वर्थ के 300% तक, जो भी अधिक हो
- D. \$2 billion / \$2 बिलियन
- E. \$50 million / \$50 मिलियन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI's draft External Commercial Borrowing (ECB) framework proposes to increase the borrowing limit for Indian firms from \$750 million to \$1 billion or 300% of net worth, whichever is higher, without needing prior approval.
- RBI के इस ड्राफ्ट के तहत कंपनियां \$750 मिलियन की जगह \$1 बिलियन या नेट वर्थ के 300% तक उधार ले सकती हैं, जो भी अधिक हो, और इसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- The framework also specifies a minimum 3-year maturity, with manufacturing firms allowed 1–3 years maturity if their total ECB does not exceed \$50 million.
- यह ढांचा न्यूनतम 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि तय करता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को 1–3 वर्ष की अवधि की अनुमति दी गई है, यदि कुल ईसीबी \$50 मिलियन से अधिक नहीं है।

Ques: Which development bank reported a 19.5% growth in net profit for FY 2024–25, reaching ₹4,811 crore, with a focus on digital innovation, green finance, and financial inclusion?

किस विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में शुद्ध लाभ में 19.5% वृद्धि दर्ज की, ₹4,811 करोड़ तक पहुँचाया, और डिजिटल नवाचार, ग्रीन फाइनेंस और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया?

- A. NABARD / नाबार्ड
- B. SIDBI / एसआईडीबीआई
- C. EXIM Bank / एक्सिम बैंक
- D. RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E. LIC / एलआईसी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) reported a net profit

of ₹4,811 crore for FY 2024–25, registering a 19.5% growth over the previous year (FY24: ₹4,026 crore).

- लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹4,811 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष (FY24: ₹4,026 करोड़) की तुलना में (19.5% की वृद्धि) है।
- SIDBI focuses on digital innovation, green finance, and financial inclusion, positioning itself as a key pillar of India's economic development.
- SIDBI डिजिटल नवाचार, ग्रीन फाइनेंस और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है और भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनता है।

Key Financial Metrics for FY25 / FY25 के प्रमुख वित्तीय संकेतक :

- Balance Sheet / Asset Base: ₹5,68,238 crore (↑ 8.7%)
 - बैलेंस शीट :संपत्ति आधार /₹5,68,238 करोड़)↑ 8.7%)
 - Loans & Advances Portfolio: ₹4,96,282 crore (↑ 8.8%)
 - ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो :₹4,96,282 करोड़)↑ 8.8%)
 - Total Income: ₹38,511 crore (↑ ~20.6% YoY)
 - कुल आय :₹38,511 करोड़)↑ ~20.6% वार्षिक(
- Asset Quality: Gross NPA at 0.04% and Net NPA at nil as of March 31, 2025.
 - संपत्ति गुणवत्ता :31 मार्च 2025 तक सकल NPA 0.04% और शुद्ध NPA शून्य रहा।

Ques: What is SBI's target for its asset size as a percentage of India's GDP by 2047?

2047 तक भारत की GDP के प्रतिशत के रूप में SBI का संपत्ति आकार लक्ष्य क्या है?

- A. 20%
- B. 22%
- C. 25%
- D. 30%
- E. 28%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI Chairman C.S. Setty stated that the bank aims to expand its asset size from 20% to 25% of India's GDP by 2047.
- SBI के चेयरमैन सीसेठी ने कहा कि बैंक का लक्ष्य अपनी संपत्ति का आकार वर्तमान .एस. में भारत की GDP के 20% से बढ़ाकर 2047 तक 25% तक करना है।
- The bank plans to support emerging sectors like semiconductors, green hydrogen, and battery storage, aligning with India's "Viksit Bharat" vision.
- बैंक सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे उभरते क्षेत्रों में वित्तीय सहयोग देगा, जो भारत के "विकसित भारत" दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- SBI's global presence and overseas operations are also planned to grow, strengthening its position among the top 10–20 banks worldwide.
- SBI की वैश्विक उपस्थिति और विदेशी संचालन भी बढ़ाने की योजना है, जिससे यह विश्व के शीर्ष 10–20 बैंकों में शामिल होने की स्थिति मजबूत करेगा।

Ques: Which organization has introduced new guidelines to provide relief to financially stressed borrowers by easing loan repayment rules?

किस संगठन ने आर्थिक रूप से तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को ऋण पुनर्भुगतान नियमों में राहत देने के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं?

- A. SEBI / सेबी
- B. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- C. NABARD / नाबार्ड
- D. Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- E. NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has introduced new guidelines to provide relief to financially stressed borrowers by making loan terms more flexible and borrower-friendly.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर्थिक रूप से तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को राहत देने और ऋण शर्तों को अधिक लचीला व उधारकर्ता अनुकूल बनाने के लिए नई दिशानिर्देश जारी

किए हैं।

Key benefits / मुख्य लाभ:

- **Faster EMI relief:** Earlier, banks could not change the “spread” (extra margin) for 3 years even if RBI reduced benchmark rates. Now, RBI has removed this restriction, allowing banks to reduce interest rates faster when RBI cuts rates.
- **तेजी से EMI राहत:** पहले बैंक 3 साल तक “स्प्रेड” (अतिरिक्त मार्जिन) नहीं बदल सकते थे, भले ही RBI ब्याज दरें घटा दे। अब RBI ने यह प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे बैंकों को ब्याज दर घटाने में आसानी होगी।
- **More choice at reset:** Borrowers with floating-rate loans can now choose to either continue with a floating rate or switch to a fixed rate at every interest rate reset (usually every 6 months).
- **रीसेट पर अधिक विकल्प:** फ्लोटिंग रेट लोन वाले उधारकर्ता अब हर ब्याज दर रीसेट-आमतौर पर हर)6 महीने पर यह चुन सकते हैं कि वे फ्लोटिंग रेट जारी रखें या फिक्स्ड (रेट पर स्विच करें)।
- **No penal interest:** Banks can no longer charge penalty interest for missed EMIs. Only a fixed late payment fee (e.g., ₹500 or ₹1000) can be applied.
- **कोई दंडात्मक ब्याज नहीं:** अब बैंक विलंबित EMI भुगतान पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगा सकते। केवल एक निश्चित लेट फीस (जैसे) ₹500 या ₹1000) ही ली जा सकती है।
- **Restructuring or moratorium options:** Banks are required to support borrowers facing financial hardships (like job loss, business failure, or medical emergencies) through restructuring or temporary payment relief.
- **पुनर्गठन या मोरेटोरियम विकल्प:** यदि उधारकर्ता को नौकरी छूटने, व्यापार हानि या चिकित्सा आपात स्थिति जैसी समस्या हो, तो बैंक को दंडित करने के बजाय पुनर्गठन या अस्थायी राहत प्रदान करनी होगी।
- RBI says lenders should provide relief options such as : 1. Restructuring of Loan Tenure 2. EMI Moratorium 3. One-Time Settlement (OTS)
- RBI का कहना है कि ऋणदाताओं को निम्नलिखित राहत विकल्प प्रदान करने चाहिए: 1. ऋण अवधि का पुनर्गठन 2. EMI स्थगन 3. एकमुश्त निपटान (OTS)

Ques: Which bank, in collaboration with PhonePe, launched the Wish Credit Card powered by RuPay?

किस बैंक ने PhonePe के सहयोग से RuPay द्वारा संचालित Wish क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?

- A. Utkarsh Small Finance Bank / उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E. SBI Card / एसबीआई कार्ड

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Wish Credit Card was launched by PhonePe in collaboration with Utkarsh Small Finance Bank and is powered by RuPay.
- Wish क्रेडिट कार्ड को PhonePe ने Utkarsh Small Finance Bank के सहयोग से लॉन्च किया है और यह RuPay द्वारा संचालित है।
- The card is backed by a fixed deposit with a minimum deposit of Rs. 2,000.
- इस कार्ड को फिक्स्ड डिपॉजिट द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि ₹2,000 है।

About Utkarsh Small Finance Bank:

- Headquarters: Varanasi, Uttar Pradesh
- CEO: Govind Singh
- Tagline: Aapki Umeed Ka Khata

Ques: Which company, in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited, launched the National Pension System (NPS) Platform Workers Model under the supervision of PFRDA?

किस कंपनी ने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से, पीएफआरडीए के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली र्स मॉडल लॉन्च कियाप्लेटफॉर्म वर्क (एनपीएस)?

- A. Swiggy / स्विगी
- B. Blinkit / ब्लिंकिट
- C. Ola / ओला
- D. Urban Company / अर्बन कंपनी
- E. Zomato / जोमैटो

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Zomato, in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited, launched the National Pension System (NPS) Platform Workers Model under the supervision of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- जोमैटो ने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल लॉन्च किया।
- The initiative aims to provide structured retirement planning for gig-based delivery partners and integrate them into the formal financial system.
- इस पहल का उद्देश्य गिगत डिलीवरी पार्टनर्स को सआधारि-रचित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करना और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है।
- Within the first 72 hours, over 30,000 delivery partners generated their Permanent Retirement Account Numbers (PRANs).
- पहले 72 घंटों के भीतर, 30,000 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स ने अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (PRAN) प्राप्त किए।
- Zomato aims to onboard more than 1,00,000 partners by December 2025.
- जोमैटो का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 1,00,000 से अधिक पार्टनर्स को जोड़ने का है।
- The NPS Platform Workers Model is a special version of the National Pension System (NPS) designed specifically for gig and platform workers such as those working with Zomato, Swiggy, Ola, Uber, Blinkit, and Urban Company.
- एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक विशेष संस्करण है, जिसे जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट और अर्बन कंपनी जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए तैयार किया गया है।
- The model was formally launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman on October 1 at an event organised by PFRDA.
- इस मॉडल को 1 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा PFRDA द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।

Ques: In which country did Union Minister Piyush Goyal launch India's Unified Payments Interface (UPI) to enhance digital and financial cooperation?

किस देश में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लॉन्च किया?

- A. Qatar / क़तर
- B. UAE / संयुक्त अरब अमीरात
- C. Saudi Arabia / सऊदी अरब
- D. Oman / ओमान
- E. Bahrain / बहरीन

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal launched India's Unified Payments Interface (UPI) at the Lulu Mall in Doha, Qatar, marking a new milestone in digital and financial cooperation between India and Qatar.
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क़तर के दोहा स्थित लुलु मॉल में भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लॉन्च किया, जो भारत और क़तर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में एक नया मील का पत्थर है।
- UPI, launched nine years ago, now accounts for 85% of India's digital payments and nearly half of global digital transactions.
- UPI, जिसे नौ वर्ष पहले लॉन्च किया गया था, अब भारत के कुल डिजिटल भुगतानों का 85% और वैश्विक डिजिटल लेनदेन का लगभग आधा हिस्सा बनाता है।
- The rollout in Qatar is a collaboration between NPCI International Payments Ltd (NIPL), Qatar National Bank (QNB), and Japanese payment gateway NETSTARS.
- क़तर में यह लॉन्च एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), क़तर नेशनल बैंक (QNB) और जापानी पेमेंट गेटवे NETSTARS के सहयोग से किया गया है।

Ques: According to the World Bank, what is India's GDP growth estimate for FY26?

विश्व बैंक के अनुसार, भारत की FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान कितना है?

- A) 6.3%
- B) 6.5%
- C) 6.7%
- D) 6.8%
- E) 6.9%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The World Bank has raised India's FY26 GDP growth forecast from 6.3% to 6.5%, backed by strong domestic demand and rural growth.
- विश्व बैंक ने भारत की FY26 GDP ग्रोथ अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जिसकी वजह मजबूत घरेलू मांग और ग्रामीण विकास बताई गई है।
- However, the FY27 outlook has been lowered to 6.3% due to potential impacts from higher US tariffs on Indian exports.
- हालांकि, FY27 का अनुमान घटाकर 6.3% किया गया है क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत के उत्पादों पर बढ़ाए गए टैरिफ का असर पड़ेगा।

Ques: Which insurance company launched the "Health Alpha" plan — the first retail health insurance product introduced after GST reforms?

किस बीमा कंपनी ने "हेल्थ अल्फा" योजना लॉन्च की — जो जीएसटी सुधारों के बाद पेश किया गया पहला रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद है?

- A. HDFC ERGO General Insurance / एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस
- B. ICICI Lombard General Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
- C. SBI General Insurance / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस
- D. Bajaj Allianz General Insurance / बजाज एलियांज़ जनरल इंश्योरेंस
- E. New India Assurance / न्यू इंडिया एश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI General Insurance launched Health Alpha, India's first retail health insurance product introduced after GST reforms.
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ अल्फा लॉन्च किया, जो जीएसटी सुधारों के बाद पेश किया गया पहला रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद है।
- The plan is fully customisable with over 50 coverage options, offering sum insured from ₹5 lakh to unlimited cover, and allows add-on benefits tailored to customers' lifestyle and budget.
- यह योजना पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है, जिसमें 50 से अधिक कवरेज विकल्प, ₹5 लाख से असीमित बीमित राशि और ग्राहकों की जीवनशैली और बजट के अनुसार अतिरिक्त लाभ चुनने की सुविधा उपलब्ध है।

Ques: Which company, in collaboration with YES Bank, launched India's first biometric card authentication system compliant with RBI's 2025 guidelines?
YES बैंक के सहयोग से RBI की 2025 दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत की पहली बायोमेट्रिक कार्ड प्रमाणीकरण प्रणाली किस कंपनी ने शुरू की?

- A. Paytm / पेटीएम
- B. Razorpay / रेज़रपे
- C. PhonePe / फोनपे
- D. Google Pay / गूगल पे
- E. BharatPe / भारतपे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Razorpay, in collaboration with YES Bank, launched India's first biometric card authentication system compliant with the Reserve Bank of India's (RBI) 2025 guidelines.
- रेज़रपे ने YES बैंक के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 2025 दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत की पहली बायोमेट्रिक कार्ड प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की।

- This system enables online card payments through facial recognition, replacing traditional two-factor authentication methods that relied on PINs and SMS OTPs.
- यह प्रणाली पारंपरिक दोकार-क प्रमाणीकरण विधियों जैसे PIN और SMS OTP की जगह चेहरे की पहचान (फेशियल रिकग्निशन) के माध्यम से ऑनलाइन कार्ड भुगतान को प्रमाणित करने की अनुमति देती है।
- It can process up to 10,000 transactions per second, reducing OTP-related errors and improving the overall payment experience.
- यह प्रणाली प्रति सेकंड 10,000 लेनदेन संसाधित करने में सक्षम है, जिससे OTP से संबंधित त्रुटियाँ कम होती हैं और भुगतान अनुभव अधिक सुगम बनता है।

About YES Bank :

- Established : 2004
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Prashant Kumar
- Chairman : Rama Subramaniam Gandhi
- Tagline : Experience our Expertise

Ques: Which Indian stock-trading platform recently achieved unicorn status after a \$120 million funding round led by Hornbill Capital and MUFG?

किस भारतीय स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में-Hornbill Capital और MUFG द्वारा संचालित \$120 मिलियन फंडिंग राउंड के बाद यूनिकॉर्न दर्जा प्राप्त किया है?

- A. Groww / ग्रो
- B. Zerodha / ज़ेरोधा
- C. Angel One / एंजल वन
- D. Dhan / धन
- E. Upstox / अपस्टॉक्स

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Dhan, a stock-trading platform under Raise Financial Services, became a unicorn after raising \$120 million in a round led by Hornbill Capital and Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).
- Dhan, जो Raise Financial Services के अंतर्गत आता है, ने Hornbill Capital और MUFG के नेतृत्व में \$120 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया।
- The investment values Dhan at \$1.2 billion (₹10,000 crore), making it one of India's newest fintech unicorns.
- इस निवेश से Dhan का मूल्यांकन लगभग \$1.2 बिलियन)₹10,000 करोड़ हो गया (, जिससे यह भारत के नवीनतम फिनटेक यूनिकॉर्न में शामिल हो गया।
- Dhan competes with top trading platforms like Groww, Zerodha, and Angel One, and had 0.9 million active traders as of August 2025.
- Dhan, Groww, Zerodha और Angel One जैसे प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा करता है, और अगस्त 2025 तक इसके पास 0.9 मिलियन सक्रिय ट्रेडर्स थे।

Ques: What is the revised world goods trade growth forecast for 2025 as per WTO?

WTO के अनुसार 2025 के लिए विश्व वस्तु व्यापार वृद्धि का नया अनुमान क्या है?

- A. 0.9%
- B. 1.8%
- C. 2.4%
- D. 4.6%
- E. 0.5%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The World Trade Organization (WTO) increased the global goods trade growth forecast for 2025 to 2.4%, citing AI-driven demand and frontloading of US imports as major reasons.
- WTO ने AI-आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग और अमेरिका द्वारा टैरिफ से बचने के लिए अग्रिम आयात को कारण बताते हुए 2025 के लिए वस्तु व्यापार वृद्धि का अनुमान 2.4% कर दिया।

- Meanwhile, the 2026 projection has been revised downward to 0.5%, showing the expected slowdown after the tariff adjustments.
- वहीं, 2026 का अनुमान घटाकर 0.5% कर दिया गया है, जो टैरिफ समायोजन के बाद संभावित मंदी को दर्शाता है।

Ques: Which co-operative bank launched India's first youth-focused digital banking app 'Cosmos Galgal'?

भारत का पहला युवा केंद्रित डिजिटल बैंकिंग ऐप-'Cosmos Galgal' किस सहकारी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया?

- A. Saraswat Co-operative Bank / सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक-
- B. Cosmos Co-operative Bank / कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक-
- C. Shamrao Vithal Co-operative Bank / शमराव विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक-
- D. Abhyudaya Co-operative Bank / अभ्युदया कोऑपरेटिव बैंक-
- E. Punjab & Maharashtra Co-operative Bank / पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Cosmos Co-operative Bank, in partnership with Umunthu System Private Limited, launched 'Cosmos Galgal', India's first youth-focused digital banking app.
- कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक ने- उमुन्थु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत का पहला युवाकेंद्रित डिजिटल बैंकिंग ऐप- 'Cosmos Galgal' लॉन्च किया।
- The app offers integrated video KYC, enabling users to open zero-balance savings accounts within 15 minutes from anywhere.
- यह ऐप वीडियो KYC सुविधा के साथ उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी 15 मिनट में ज़ीरो-बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करता है।
- Established in 1906, Cosmos Co-operative Bank is headquartered at Cosmos Tower, Pune, Maharashtra.
- 1906 में स्थापित, कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय- कॉसमॉस टॉवर, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
- It is among the first co-operative banks in India to implement Core Banking Solution (CBS).

- यह भारत के पहले सहकारी बैंकों में से एक है जिसने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) लागू किया।

Ques: What is the maximum compensation proposed by RBI that the banking ombudsman can award to aggrieved bank customers for consequential loss?
बैंकों के ग्राहकों को हुई परिणामी हानि के लिए बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि क्या प्रस्तावित की गई है?

- A. ₹10 lakh
- B. ₹20 lakh
- C. ₹25 lakh
- D. ₹30 lakh
- E. ₹35 lakh

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has proposed that the banking ombudsman may compensate aggrieved customers up to ₹30 lakh for any consequential loss suffered.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों को हुई परिणामी हानि के लिए अधिकतम ₹30 लाख तक का मुआवजा दे सकता है।
- Additionally, the ombudsman may award up to ₹3 lakh for harassment, mental agony, or time spent in pursuing the grievance.
- इसके अलावा, शिकायत के निपटारे में हुई मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न या समय की हानि के लिए लोकपाल अधिकतम ₹3 लाख तक का मुआवजा दे सकता है।
- Customers of state and central cooperative banks can approach the ombudsman structure from November 1, 2025.
- राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहक 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
- If banks fail to respond within 30 days, customers can escalate their complaints to the RBI.
- यदि बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देते, तो ग्राहक अपनी शिकायतें RBI तक बढ़ा सकते हैं।

Ques: ICICI Bank has launched the Corporate Sapphire Forex Card in collaboration with which global payment network?

आईसीआईसीआई बैंक ने कॉर्पोरेट सैफायरो फॉरेक्स कार्ड किस वैश्विक भुगतान नेटवर्क के सहयोग से लॉन्च किया है?

- A. Mastercard / मास्टरकार्ड
- B. Visa / वीज़ा
- C. American Express / अमेरिकन एक्सप्रेस
- D. RuPay / रुपये
- E. Discover / डिस्कवर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Bank has partnered with Visa to launch the Corporate Sapphire Forex Card — the first prepaid card by any Asian bank powered by Visa Infinite, designed for entrepreneurs and corporate travelers.
 - आईसीआईसीआई बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर कॉर्पोरेट सैफायरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है — जो किसी भी एशियाई बैंक द्वारा वीज़ा इंफिनिट द्वारा संचालित पहला प्रीपेड कार्ड है, जिसे उद्यमियों और कॉर्पोरेट यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - The card offers premium benefits like airport lounge access, travel insurance, global customer assistance, multi-currency loading, and enhanced security for international transactions.
 - यह कार्ड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंस, मल्टी-करेंसी लोडिंग और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उन्नत सुरक्षा जैसी प्रीमियम सुविधाएँ प्रदान करता है।
-

Ques: From which date will State and Central Co-operative Banks come under the ambit of the RBI's Integrated Ombudsman Scheme, 2021?

राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक किस तारीख से RBI की एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के दायरे में आएंगे?

- A. August 15, 2025
- B. October 1, 2025

- C. November 1, 2025
- D. December 31, 2025
- E. January 1, 2026

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI), under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, has issued a notification to include State and Central Co-operative Banks under the Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत अधिसूचना जारी कर राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के दायरे में शामिल किया है।
- This inclusion will be effective from November 1, 2025, expanding the scheme to cover Commercial Banks, RRBs, Co-operative Banks, NBFCs (excluding HFCs) with certain asset thresholds, and Credit Information Companies.
- यह विस्तार योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, तय संपत्ति आकार वाली गैर) बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-HFC को छोड़कर, और क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी शामिल करता है।
- RB-IOS provides a fast, cost-effective, and transparent grievance redressal mechanism for customers of regulated entities.
- RB-IOS ग्राहकों को तेज़, किफायती और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करती है।

Ques: Who has been appointed as Administrator of Irinjalakuda Town Co-operative Bank after RBI superseded its board?

आरबीआई द्वारा इरिंजालकुडा टाउन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भंग करने के बाद - प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A. Mohanan K / मोहनन के
- B. T.A. Mohamed Sageer / टीमोहम्मद सगीर .ए.
- C. Raju S. Nair / राजू एसनायर .
- D. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास

E. V. Vaidyanathan / वीवैद्यनाथन .

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI), under Section 36AAA read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, superseded the board of Irinjalakuda Town Co-operative Bank Ltd. for 12 months due to poor financial condition and governance issues.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक कमियों के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AAA और धारा 56 के तहत इरिंजालकुडा टाउन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बोर्ड को-12 महीनों के लिए भंग कर दिया।
 - Shri Raju S. Nair, former Vice President of Federal Bank, has been appointed as Administrator to manage the bank's affairs during this period.
 - इस अवधि के दौरान बैंक के कार्यों के प्रबंधन के लिए फेडरल बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजू एसयर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
 - A Committee of Advisors, including Shri Mohanan K and Shri T.A. Mohamed Sageer, has also been formed to assist the Administrator.
 - प्रशासक को उनके कर्तव्यों में सहायता करने के लिए श्री मोहनन के और श्री टी .ए. गीर सहित एक सलाहकार समिति भी गठित की गई है। मोहम्मद स
-

Ques: Who launched the pilot linking the FX-Retail platform of Clearcorp with the Bharat Bill Payment System (Bharat Connect)?

किसने Clearcorp के FX-Retail प्लेटफॉर्म को Bharat Bill Payment System (Bharat Connect) से जोड़ने वाला पायलट लॉन्च किया?

- A. T. Rabi Sankar / टीरबी शंकर .
- B. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- C. Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- D. Ajay Tyagi / अजय त्यागी
- E. Rajeev Kumar / राजीव कुमार

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- RBI Deputy Governor T. Rabi Sankar launched a pilot linking the FX-Retail platform of Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd. with the Bharat Bill Payment System (Bharat Connect) at the Global Fintech Fest (GFF) 2025 in Mumbai.
- RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने मुंबई में .Global Fintech Fest (GFF) 2025 में Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd. के FX-Retail प्लेटफॉर्म को Bharat Bill Payment System (Bharat Connect) से जोड़ने वाला पायलट लॉन्च किया।
- The linkage allows customers of Axis Bank, Federal Bank, ICICI Bank, SBI, and Yes Bank to transact on the FX-Retail platform via bank digital channels or Third Party Application Providers (TPAPs).
- इस लिंक से Axis Bank, Federal Bank, ICICI Bank, SBI और Yes Bank के ग्राहक बैंक डिजिटल चैनलों या थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर्स (TPAPs) के माध्यम से FX-Retail प्लेटफॉर्म पर लेनदेन कर सकते हैं।-
- Customers can access FX-Retail through CRED and Mobikwik applications to purchase US Dollars against Indian Rupees on a 'value cash' basis.
- ग्राहक CRED और Mobikwik एप्लिकेशन के माध्यम से FX-Retail का उपयोग करके भारतीय रुपये के बदले अमेरिकी डॉलर 'वैल्यू कैश' आधार पर खरीद सकते हैं।

Ques: What is the initial transaction limit for UPI biometric authentication introduced by the Government of India?

सरकार द्वारा शुरू किए गए UPI बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए प्रारंभिक लेनदेन सीमा क्या है?

- A. ₹1,000
- B. ₹2,500
- C. ₹5,000
- D. ₹10,000
- E. ₹15,000

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India has introduced on-device biometric authentication for UPI payments using face or fingerprint verification, announced by DFS Secretary M. Nagaraju at the Global Fintech Fest.
- भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को तेज़, सुरक्षित और PIN-रहित बनाने के लिए चेहरे और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण आधारित UPI लेनदेन शुरू किया है, जिसकी घोषणा वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एमनागराजु ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में की। .
- Initially, such biometric transactions will be capped at ₹5,000, and the limit will be reviewed later.
- शुरुआत में ऐसे बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन की सीमा ₹5,000 रखी गई है, जिसे बाद में पुनः समीक्षा किया जाएगा।
- Aadhaar-based facial authentication also allows secure setting or resetting of the UPI PIN, while NPCI mandates disabling the feature on device changes or PIN reset and marking users inactive if no transaction occurs within 90 days.
- आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से उपयोगकर्ता अपने UPI PIN को सुरक्षित रूप से सेट या रीसेट कर सकते हैं, और NPCI ने निर्देश दिया है कि डिवाइस बदलने या PIN रीसेट होने पर फीचर को डिसेबल किया जाए तथा 90 दिनों तक कोई ट्रांजैक्शन न होने पर उपयोगकर्ता को निष्क्रिय माना जाए।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a monetary penalty of ₹31.80 lakh on which bank for non-compliance with its directions under the Credit Card and Debit Card - Issuance and Conduct Directions, 2022?

RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण दिशानिर्देश-, 2022 के तहत दिशा निर्देशों का पालन न करने पर-₹31.80 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है?

- A. Citibank N.A. / सिटीबैंक एन.ए.
- B. HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
- C. American Express Banking Corp. / अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.
- D. Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- E. Deutsche Bank / डॉयचे बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of ₹31.80 lakh on American Express Banking Corp. for non-compliance with its Credit Card and Debit Card - Issuance and Conduct Directions, 2022.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण दिशा-निर्देश, 2022 का पालन नहीं किया।
- The penalty was imposed under Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c) के साथ धारा 46(4)(i) के तहत लगाया गया।
- The penalty followed the findings of Inspection for Supervisory Evaluation (ISE 2024), which revealed lapses in reversing credit balances for certain cardholders arising from refunds, failed, or reversed transactions.
- यह जुर्माना ISE 2024 निरीक्षण के निष्कर्षों के बाद लगाया गया, जिसमें रिफंड, असफल या रिवर्स लेनदेन से उत्पन्न कुछ कार्डधारकों के क्रेडिट बैलेंस को वापस न करने की कमियाँ पाई गईं।
- RBI clarified that the action targets regulatory compliance deficiencies and does not affect the validity of any transactions or agreements between the bank and its customers.
- RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन की कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी लेनदेन या समझौते की वैधता - को प्रभावित करना नहीं है।

**Ques: Which Indian payments system has been announced as the first partner onboarded on PayPal World, PayPal's global payments platform?
किस भारतीय भुगतान प्रणाली को PayPal World, PayPal के वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म पर पहले पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है?**

- A. BharatQR / भारतQR
- B. UPI / यूपीआई
- C. Paytm / पेटीएम
- D. Google Pay / गूगल पे
- E. PhonePe / फोनपे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- PayPal CEO Alex Chriss announced that India's Unified Payments Interface (UPI) is the first payments-system partner to be onboarded on PayPal World, the newly launched global payments platform.
 - PayPal के CEO एलेक्स क्रिस ने घोषणा की कि भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को PayPal World, नए लॉन्च किए गए वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म पर पहला भुगतान प्रणाली पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है।
 - PayPal World enables cross-border transactions by allowing users to use local payment systems and digital wallets for international commerce.
 - PayPal World सीमापार लेनदेन को सक्षम बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थानीय भुगतान प्रणाली और डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं।
 - Other partner wallets already associated with PayPal World include Mercado Pago (Latin America), Tenpay Global (China), and Venmo (USA).
 - PayPal World से पहले जुड़े अन्य पार्टनर वॉलेट्स में Mercado Pago (लैटिन अमेरिका), Tenpay Global (चीन), और Venmo (यूएसए शामिल हैं। (
-

**Ques: Which company recently rebranded its insurance businesses as Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance after acquiring full ownership?
किस कंपनी ने हाल ही में अपनी बीमा कंपनियों का नाम बदलकर Bajaj General Insurance और Bajaj Life Insurance रखा, पूर्ण स्वामित्व हासिल करने के बाद?**

- A. ICICI Lombard / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड
- B. HDFC ERGO / एचडीएफसी एर्गो
- C. Tata AIG / टाटा एआईजी
- D. SBI General Insurance / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस
- E. Bajaj Finserv / बजाज फिनसर्व

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Bajaj Finserv Limited has rebranded its insurance businesses as Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance, dropping the Allianz branding.
- बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने अपनी बीमा कंपनियों का नाम बदलकर Bajaj General Insurance और Bajaj Life Insurance रखा, और Allianz ब्रांडिंग हटा दी।
- Earlier in 2025, Bajaj Finserv acquired Allianz SE's 26% stake in its two insurance joint ventures for ₹24,180 crore, gaining full ownership.
- इस वर्ष के शुरू में, बजाज फिनसर्व ने अपनी दो बीमा जॉइंट वेंचर में Allianz SE के 26% शेयर ₹24,180 करोड़ में खरीदे, और पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया।
- The rebranding campaign is supported by the tagline: "100% Bajaj. Made in India. Made for India. Made by India."
- इस रिब्रांडिंग अभियान का समर्थन टैगलाइन के साथ किया गया है : "100% Bajaj. Made in India. Made for India. Made by India."

Ques: What is the purpose of RBI's proposed Expected Credit Loss (ECL) framework?

RBI द्वारा प्रस्तावित ECL ढांचे का उद्देश्य क्या है?

- A. To reduce CRR and SLR for banks / बैंकों के लिए CRR और SLR कम करना
- B. To replace the RTGS payment system / RTGS भुगतान प्रणाली को बदलना
- C. To align India's banking norms with global standards and improve credit risk assessment / भारत के बैंकिंग मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप करना और क्रेडिट जोखिम आकलन में सुधार करना
- D. To promote digital payment systems / डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देना
- E. To merge all public sector banks into one / सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The RBI's proposed Expected Credit Loss (ECL) framework aims to align Indian banking regulations with international accounting and risk management

standards.

- RBI द्वारा प्रस्तावित अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ECL) ढांचा भारतीय बैंकिंग नियमों को अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और जोखिम प्रबंधन मानकों के अनुरूप बनाने का उद्देश्य रखता है।
- It replaces the incurred-loss model, requiring banks to classify loans based on credit risk and set aside provisions for potential losses in advance.
- यह पुराने 'incurred-loss' मॉडल की जगह लेता है, बैंकों को ऋणों को क्रेडिट जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करने और संभावित नुकसान के लिए अग्रिम प्रावधान अलग रखने की आवश्यकता होती है।
- The framework will come into effect from April 1, 2027, enhancing the banking system's stability and transparency.
- यह ढांचा 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

Ques: Which Urban Cooperative Bank's licence has been cancelled by the Reserve Bank of India (RBI) in October 2025?

अक्टूबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस - रद्द कर दिया है?

- A. Jijamata Sahakari Bank, Satara / जीजामाता सहकारी बैंक, सतारा
- B. Saraswat Co-operative Bank, Mumbai / सारस्वत सहकारी बैंक, मुंबई
- C. Rupee Co-operative Bank, Pune / रुपया सहकारी बैंक, पुणे
- D. Punjab & Maharashtra Co-operative Bank, Mumbai / पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक, मुंबई
- E. Abhyudaya Co-operative Bank, Mumbai / अभ्युदय सहकारी बैंक, मुंबई

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Jijamata Sahakari Bank, an Urban Cooperative Bank (UCB) based in Satara, Maharashtra.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के सतारा स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक-
जिजामाता सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
- The licence was cancelled due to the bank's poor financial condition and

failure to comply with the regulatory norms under the Banking Regulation Act, 1949.

- यह कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत नियामक मानकों का पालन न करने के कारण की गई है।
- Following the cancellation, the bank has been barred from conducting any banking business effective from the close of business on October 7, 2025.
- लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक को 7 अक्टूबर 2025 से किसी भी बैंकिंग गतिविधि को संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- Notably, the bank's licence was earlier cancelled in 2016 but later restored in 2019 after an appeal made by the bank.
- उल्लेखनीय है कि इस बैंक का लाइसेंस पहले 2016 में रद्द किया गया था, जिसे 2019 में बैंक की अपील पर बहाल कर दिया गया था।

Ques: Which initiative has the Reserve Bank of India (RBI) launched to allow fintech companies to develop and test use cases under the e-Rupee pilot?

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने किस पहल को शुरू किया है ताकि फिनटेक कंपनियाँ ई-रुपया पायलट के तहत उपयोग के मामलों और समाधान विकसित और परीक्षण कर सकें?

- A. Digital Rupee Sandbox / डिजिटल रुपया सैंडबॉक्स
- B. Fintech Innovation Hub / फिनटेक इनोवेशन हब
- C. E-Payments Pilot Program / ईभुगतान पायलट प्रोग्राम-
- D. Retail Banking Sandbox / रिटेल बैंकिंग सैंडबॉक्स
- E. Digital Finance Lab / डिजिटल फाइनेंस लैब

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has launched a retail sandbox for its Central Bank Digital Currency (CBDC) to allow fintech companies to develop and test use cases under the ongoing e-Rupee pilot.
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, ताकि फिनटेक कंपनियाँ चल रहे ईरुपया पायलट के तहत - क्षण कर सकें। उपयोग के मामलों और समाधान विकसित और परी
- The e-Rupee retail pilot, first launched on December 1, 2022, now provides a

platform for innovative product deployment.

- दिसंबर 1, 2022 को शुरू हुए ईरुपया रिटेल पायलट के तहत अब नवाचारी उत्पादों को - कंपनियों को मिलेगा। विकसित और लागू करने का अवसर फिनटेक
- The initiative is led by Suvendu Pati.
- इस पहल का नेतृत्व सुवेंदु पाटी कर रहे हैं।

Ques: The Reserve Bank of India has launched the 71st round of which quarterly survey for the reference period July – September 2025?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई – सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए किस तिमाही सर्वेक्षण का 71वां चरण शुरू किया है?

- A. Industrial Outlook Survey (IOS) / औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण
- B. Consumer Confidence Survey (CCS) / उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
- C. Order Books, Inventories and Capacity Utilisation Survey (OBICUS) / ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
- D. Inflation Expectations Survey (IES) / मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण
- E. Services Sector Utilisation Survey / सेवा क्षेत्र उपयोग सर्वेक्षण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The RBI launched the 71st round of its Order Books, Inventories and Capacity Utilisation Survey (OBICUS) for July–September 2025 (Q2: 2025-26).
- RBI ने जुलाई–सितंबर 2025 (Q2: 2025-26) की अवधि के लिए ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (OBICUS) का 71वां चरण शुरू किया है।
- This survey, conducted quarterly since 2008, tracks manufacturing sector performance in terms of new orders, inventories, production levels, and capacity utilisation.
- यह सर्वेक्षण 2008 से तिमाही आधार पर किया जा रहा है ताकि विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों को समझा जा सके।
- Data collected helps the RBI in monetary policy formulation, while company-level data remains confidential and is not publicly disclosed.
- एकत्र किए गए डेटा से RBI को मौद्रिक नीति निर्माण में मदद मिलती है, और कंपनी स्तर के डेटा को गोपनीय रखा जाता है तथा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता।

Ques: RBI imposed a monetary penalty of ₹4.20 lakh on which NBFC for non-compliance with KYC Directions, 2016?

आरबीआई ने KYC निर्देश, 2016 के अनुपालन में विफल रहने पर किस एनबीएफसी पर ₹4.20 लाख का जुर्माना लगाया?

- A. Bajaj Finance Ltd / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
- B. HDB Financial Services Ltd / एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
- C. Tata Capital Financial Services / टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज
- D. Muthoot Finance / मुथूट फाइनेंस
- E. Shriram Finance / श्रीराम फाइनेंस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI), exercising powers under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the RBI Act, 1934, imposed a monetary penalty of ₹4.20 lakh on HDB Financial Services Ltd for non-compliance with certain provisions of the KYC Directions, 2016.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) और धारा 58B(5)(aa) के तहत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर KYC निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ₹4.20 लाख का जुर्माना लगाया।
- The penalty follows a statutory inspection referencing the company's financial position as on March 31, 2024, which revealed deficiencies in obtaining PAN/Form 60 in certain loan accounts for FY 2023–24.
- यह जुर्माना कंपनी की 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद लगाया गया, जिसमें FY 2023–24 के कुछ ऋण खातों में PAN/फॉर्म 60 प्राप्त करने में कमियां पाई गईं।
- RBI clarified that this action targets regulatory compliance lapses and does not question the validity of any transactions undertaken by the company.
- RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा किए गए किसी लेनदेन की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।-

Ques: Which organization launched its 2nd verified WhatsApp channel for public awareness under the 'RBI Kehta Hai' initiative?

'RBI कहता है' पहल के तहत जन जागरूकता के लिए दूसरा सत्यापित-व्हाट्सएप चैनल किस संगठन ने शुरू किया है?

- A. SEBI / सेबी
- B. IRDAI / आईआरडीएआई
- C. RBI / आरबीआई
- D. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E. NABARD / NABARD

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) launched its second verified WhatsApp channel in October 2025 under its 'RBI Kehta Hai' initiative.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2025 में अपनी 'RBI कहता है' पहल के तहत दूसरा सत्यापित व्हाट्सएप चैनल शुरू किया।
- The initiative aims to make financial information easily accessible to the public in a simple, direct, and effective manner, thereby enhancing trust and financial literacy.
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय जानकारी को सरल, सीधा और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँचाना है, जिससे विश्वास और वित्तीय साक्षरता बढ़े।
- The first verified WhatsApp number (+91 99990 41935) was launched in April 2025, and the second verified number (+91 99309 91935) has now been added.
- पहला सत्यापित व्हाट्सएप नंबर (+91 99990 41935) अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था, और अब दूसरा नंबर (+91 99309 91935) जोड़ा गया है।
- Citizens can now receive official updates, alerts, and public awareness messages directly from RBI on WhatsApp.
- अब नागरिक व्हाट्सएप पर RBI से सीधे आधिकारिक अपडेट, अलर्ट और जनजागरूकता - कर सकते हैं। संदेश प्राप्त
- RBI has advised users to follow only verified accounts with the blue tick to avoid fraud.
- RBI ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे केवल ब्लू टिक वाले सत्यापित खातों को ही फॉलो करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।

Ques: As per the latest amendment to the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, how much will vehicles be charged if they pay toll fees via UPI without a valid FASTag?

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (दर निर्धारण और संग्रह), 2008 में हालिया संशोधन के अनुसार, यदि वाहन वैध फास्टैग के बिना यूपीआई के माध्यम से टोल शुल्क का भुगतान करते हैं, तो उनसे कितना शुल्क लिया जाएगा?

- A. Equal to applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क के बराबर
- B. 1.25 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 1.25 गुना
- C. 1.5 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 1.5 गुना
- D. 2 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 2 गुना
- E. 3 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 3 गुना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India has amended the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (दर निर्धारण और संग्रह), 2008 में संशोधन किया है।
- As per the new rule, vehicles entering a fee plaza without a valid, functional FASTag will be charged **twice** the applicable user fee if payment is made in cash.
- नए नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन वैध फास्टैग के बिना नकद भुगतान करता है, तो उससे लागू शुल्क का **दोगुना** लिया जाएगा।
- However, such users opting to pay the fee via Unified Payment Interface (UPI) will be charged **1.25 times** the applicable user fee for that category of vehicle.
- जबकि ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान करते हैं, उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू शुल्क का **1.25 गुना** लिया जाएगा।
- For example, if a vehicle needs to pay ₹100 via valid FASTag, the fee will be ₹200 if paid in cash and ₹125 if paid via UPI.
- उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग से ₹100 का भुगतान करना है, तो नकद भुगतान करने पर ₹200 और यूपीआई से भुगतान करने पर ₹125 देना होगा।
- This amendment aims to strengthen the fee collection process, enhance transparency in toll collection, and promote ease of commuting for National

Highway users.

- यह संशोधन शुल्क संग्रह प्रक्रिया को मजबूत करने, टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने का लक्ष्य रखता है।
- The notification will come into effect from November 15, 2025.
- यह अधिसूचना 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।

Ques: Which bank in India has become the first to act as a UPI-ICD Acquirer, allowing UPI-based interoperable cash deposits?

भारत में कौन सा बैंक पहला बन गया है जो UPI-ICD Acquirer के रूप में कार्य करेगा, और UPI-आधारित इंटरऑपरेबल नकद जमा स्वीकार करेगा?

- A. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B. Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- C. TJSB Sahakari Bank / टीजेएसबी सहकारी बैंक
- D. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- TJSB Sahakari Bank has gone live as the first bank in India to act as a UPI-ICD Acquirer, meaning it can accept UPI-based interoperable cash deposits.
- टीजेएसबी सहकारी बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जो UPI-ICD Acquirer के रूप में कार्य करेगा, यानी यह UPI-आधारित इंटरऑपरेबल नकद जमा स्वीकार कर सकता है।
- The rollout uses TJSB's **Android Cash Recycler Machine (CRM)**, which accepts cash deposits via a UPI QR code and may recycle cash for withdrawals.
- यह सुविधा टीजेएसबी की **एंड्रॉइड कैश रीसायकलर मशीन (CRM)** के माध्यम से उपलब्ध है, जो UPI QR कोड से नकद जमा स्वीकार करती है और निकासी के लिए नकद पुनः उपयोग कर सकती है।

How it works (in simple terms):

- Go to any bank's cash deposit machine (CDM) supporting UPI-ICD.
- Select the **UPI-ICD option**.

- Enter your **UPI ID**.
- Machine shows your bank name and account details.
- Insert cash → amount credited instantly via UPI rails.
- Receive a **UPI transaction receipt**, similar to any UPI payment.

सरल शब्दों में काम करने का तरीका:

- किसी भी बैंक की UPI-ICD समर्थित नकद जमा मशीन पर जाएँ।
 - **UPI-ICD** विकल्प चुनें।
 - अपना **UPI ID** दर्ज करें।
 - मशीन आपके बैंक का नाम और खाता विवरण दिखाएगी।
 - नकद डालें → राशि तुरंत UPI के माध्यम से आपके खाते में जमा हो जाएगी।
 - आपको **UPI लेनदेन रसीद** प्राप्त होगी, जैसे किसी भी UPI भुगतान में मिलती है।
-
- As per NPCI circular, the limit is **up to ₹50,000 per transaction**.
 - NPCI सर्कुलर के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन की सीमा **₹50,000** तक है।
 - Union Bank of India had earlier introduced a **pilot UPI-ICD product** in cash recycler machines.
 - इससे पहले, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नकद रीसायकलर मशीनों में **पायलट UPI-ICD** उत्पाद शुरू किया था।

Ques: What is the maximum withdrawal limit imposed by RBI on The Baghat Urban Co-operative Bank Ltd., Solan?

आरबीआई द्वारा द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड-, सोलन पर अधिकतम निकासी सीमा कितनी तय की गई है?

- A. ₹5,000
- B. ₹10,000
- C. ₹25,000
- D. ₹50,000
- E. ₹1,00,000

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has imposed several restrictions on The Baghat Urban Co-operative Bank Ltd., Solan under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, effective from October 8, 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड-, सोलन पर 8 अक्टूबर 2025 से कई प्रतिबंध लगाए हैं।
- As per RBI's directive, depositors are allowed to withdraw **up to ₹10,000** only from the total balance held in all their accounts (savings or current) with the bank.
- RBI के निर्देशानुसार, जमाकर्ताओं को अपने सभी खातों वलसे के (बचत या चालू) **₹10,000 तक** निकासी की अनुमति है।
- These restrictions have been imposed due to the bank's poor liquidity position and to protect the interest of depositors.
- ये प्रतिबंध बैंक की कमजोर तरलता स्थिति और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
- Eligible depositors can claim up to ₹5,00,000 from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) as per the DICGC Act, 1961.
- योग्य जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के अनुसार जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि पर **₹5,00,000 तक** का दावा कर सकते हैं।

Ques: The recently launched Foreign Currency Settlement System (FCSS) at GIFT City currently supports transactions in which currency?

हाल ही में गिफ्ट सिटी में शुरू की गई विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) वर्तमान में किस मुद्रा में लेनदेन का समर्थन करती है?

- A. Euro / यूरो
- B. Pound / पाउंड
- C. US Dollar / अमेरिकी डॉलर
- D. Yen / येन
- E. Rupee / रुपया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Foreign Currency Settlement System (FCSS), launched at GIFT City during the Global Fintech Fest 2025, currently supports only US dollar transactions with Standard Chartered Bank as the settlement partner.
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान शुरू की गई विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) फिलहाल केवल अमेरिकी डॉलर लेनदेन का समर्थन करती है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक निपटान भागीदार है।
- The system enables near real-time settlements without traditional banking intermediaries, currently limited to IFSC Banking Units (IBUs) within GIFT City, Gujarat.
- यह प्रणाली पारंपरिक बैंकिंग माध्यमों के बिना लगभग वास्तविक समय में लेनदेन का निपटान सक्षम बनाती है और फिलहाल गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स (IBUs) तक सीमित है।
- The upcoming expansion will include Euro and British Pound to make GIFT City a global currency settlement hub.
- आगामी विस्तार में यूरो और ब्रिटिश पाउंड को शामिल किया जाएगा ताकि गिफ्ट सिटी को वैश्विक मुद्रा निपटान केंद्र बनाया जा सके।

Ques: Which organization has launched its new tech subsidiary 'NPCI Tech Solutions Limited (NTSL)' to promote innovation and research in the fintech sector?

किस संगठन ने फिनटेक क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई तकनीकी सहायक कंपनी 'एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (NTSL)' लॉन्च की है?

- A. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B. SIDBI / भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- C. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D. NITI Aayog / नीति आयोग
- E. National Payments Corporation of India / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- National Payments Corporation of India (NPCI) launched its new tech subsidiary 'NPCI Tech Solutions Limited (NTSL)' aimed at promoting experimentation and breakthrough innovations in the financial technology (fintech) sector.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में (फिनटेक) प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी नई तकनीकी सहायक कंपनी 'एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (NTSL)' शुरू की है।
- The announcement was made at the Global Fintech Fest 2025 held in Mumbai.
- इसकी घोषणा मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान की गई।
- The subsidiary will focus on innovation, research, and development in areas such as AI-based fraud detection, real-time payments infrastructure, and cross-border payment systems.
- यह सहायक कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित धोखाधड़ी पहचान, रियलटाइम - पार भुगतान प्रणालियों जैसे क्षेत्र-भुगतान अवसंरचना और सीमाओं में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होगी।
- With this, NTSL joins the list of existing subsidiaries of NPCI — NPCI BHIM Services Limited (NBSL), NPCI International Payments Limited (NIPL), and NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL).
- इसके साथ ही, NTSL अब NPCI की मौजूदा सहायक कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है — एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL)।
- NTSL commenced operations with an authorized capital of Rs. 1.00 million and a paid-up capital of Rs. 0.50 million.
- NTSL ने 1.00 मिलियन रुपये की अधिकृत पूंजी और 0.50 मिलियन रुपये की चुकता पूंजी के साथ अपना संचालन शुरू किया।
- Key Directors include Ajay Kumar Choudhary, Dilip Asbe Pratap, Krishnamurthy Viswanath, and Nitin Mishra.
- इसके प्रमुख निदेशकों में अजय कुमार चौधरी, दिलीप अस्बे प्रताप, कृष्णमूर्ति विश्वनाथ और नितिन मिश्रा शामिल हैं।

Ques: What is the rate of interest on the Government of India Floating Rate Bond 2028 (GOI FRB 2028) for the period October 4, 2025 – April 3, 2026?

भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 (GOI FRB 2028) पर 4 अक्टूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 की अवधि के लिए ब्याज दर क्या है?

- A. 6.10%
- B. 6.22%
- C. 6.35%
- D. 6.50%
- E. 6.75%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced that the rate of interest on the Government of India Floating Rate Bond (FRB) 2028 for the half-year period from October 4, 2025 to April 3, 2026 will be 6.22% per annum.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 पर 4 अक्टूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 तक की छमाही अवधि के लिए 6.22% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।
- The FRB 2028 carries a floating coupon rate, which changes periodically based on the Weighted Average Yield (WAY) of 182-day Treasury Bills (T-Bills).
- FRB 2028 पर फ्लोटिंग कूपन दर लागू होती है, जो 182-दिवसीय ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) की भारित औसत प्रतिफल दर (WAY) पर आधारित है।
- The base rate for FRB 2028 is equivalent to the average of the last three T-Bill auctions, plus a fixed spread of 0.64%.
- FRB 2028 की आधार दर पिछली तीन T-Bill नीलामियों के औसत के बराबर होती है, जिसमें 0.64% का निश्चित स्प्रेड जोड़ा जाता है।
- The rate revision is done every six months based on the latest T-Bill yields to ensure market-linked returns.
- यह दर हर छह महीने में नवीनतम T-Bill प्रतिफल के आधार पर संशोधित की जाती है ताकि बाजार से जुड़ा रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके।
- This announcement was made by Ajit Prasad, Deputy General Manager (Communications), RBI, on October 3, 2025.
- यह घोषणा अजीत प्रसाद, उप महाप्रबंधक(संचार), RBI द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को की गई।

Ques: Which bank has officially launched Innovation Banking in India with a USD 1 billion non-dilutive debt capital allocation for startups?

किस बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की गैर-घटती ऋण पूंजी आवंटन के साथ 'इनोवेशन बैंकिंग' आधिकारिक रूप से शुरू की है?

- A. HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
- B. Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- C. Citibank / सिटीबैंक
- D. DBS Bank / डीबीएस बैंक
- E. Barclays Bank / बार्कलेज बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- HSBC has officially launched Innovation Banking in India — a focused proposition tailored for the startup and venture ecosystem.
- एचएसबीसी ने भारत में इनोवेशन बैंकिंग आधिकारिक रूप से शुरू की है — जो स्टार्टअप और वेंचर इकोसिस्टम के लिए विशेष रूप से तैयार पहल है।
- The bank will allocate USD 1 billion in non-dilutive debt capital for Indian startups. “Non-dilutive” means this is lending (debt), not equity — so startups can scale without giving away ownership.
- बैंक भारतीय स्टार्टअप्स के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की गैरघटती ऋण पूंजी - आवंटित करेगा। “गैरघटती-” का अर्थ है कि यह ऋण है, इक्विटी नहीं — यानी स्टार्टअप्स को अपनी हिस्सेदारी बेचे बिना विस्तार करने की सुविधा मिलेगी।
- The initiative will support companies from early- to late-stage growth, up to IPO.
- यह पहल कंपनियों को प्रारंभिक से लेकर आईपीओ तक के विकास चरणों में सहायता प्रदान करेगी।
- The India team is led by Dilip Gopinath, Head of HSBC Innovation Banking India.
- भारत में इस पहल का नेतृत्व दिलीप गोपीनाथ, प्रमुख, एचएसबीसी इनोवेशन बैंकिंग इंडिया, कर रहे हैं।
- Earlier, HSBC had committed USD 600 million in lending support for tech-led high-growth startups in India, up from USD 250 million earlier.
- इससे पहले, एचएसबीसी ने भारत में प्रौद्योगिकीआधारित तेजी से बढ़ते स्टार-टअप्स के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता का वादा किया था, जो पहले 250

मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाई गई थी।

About HSBC :

- Established : 1865
- HQ : London, England, United Kingdom
- CEO : Georges Elhedery

Ques: What is the new minimum threshold for block deals as per SEBI's latest revision?

सेबी के हालिया संशोधन के अनुसार ब्लॉक डील की नई न्यूनतम सीमा क्या है?

- A. ₹5 crore
- B. ₹10 crore
- C. ₹15 crore
- D. ₹25 crore
- E. ₹50 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) raised the minimum block deal limit from ₹10 crore to ₹25 crore to enhance market liquidity and transparency.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ब्लॉक डील की न्यूनतम सीमा ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹25 करोड़ कर दी है ताकि बाजार की तरलता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
- SEBI also expanded the **price band** for executing block trades, aiming to improve price discovery and reduce speculative trades.
- सेबी ने ब्लॉक ट्रेड्स के लिए मूल्य सीमा का विस्तार भी किया है (प्राइस बैंड), ताकि मूल्य खोज में सुधार और सट्टा व्यापार में कमी लाई जा सके।
- The step will lead to better liquidity in normal trades and smoother price movements, benefiting overall market stability.
- यह कदम सामान्य ट्रेडिंग में बेहतर तरलता और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करेगा, जिससे कुल मिलाकर बाजार की स्थिरता मजबूत होगी।

Ques: SEBI is working with which two institutions to enable remote KYC access for NRIs?

SEBI किस दो संस्थाओं के साथ मिलकर एनआरआई के लिए दूरस्थ KYC सुविधा ला रहा है?

- A. RBI and UIDAI / आरबीआई और यूआईडीएआई
- B. NPCI and RBI / एनपीसीआई और आरबीआई
- C. UIDAI and Finance Ministry / यूआईडीएआई और वित्त मंत्रालय
- D. RBI and IRDAI / आरबीआई और IRDAI
- E. None of These / इनमें से कोई नहीं

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- SEBI is collaborating with RBI and UIDAI to allow Non-Resident Indians (NRIs) to complete KYC remotely without visiting India.
- SEBI आरबीआई और UIDAI के साथ मिलकर एनआरआई को भारत आए बिना ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से KYC पूरा करने की सुविधा देगा।
- This initiative is in the testing phase and aims to simplify investment and account opening for NRIs in Indian financial markets.
- यह पहल परीक्षण चरण में है और इसका उद्देश्य एनआरआई के लिए भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश और खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- Once launched, NRIs will be able to verify their identity and invest in India remotely, boosting their participation in the financial system.
- लॉन्च होने के बाद, एनआरआई अपनी पहचान दूरस्थ रूप से सत्यापित करके भारत में निवेश कर सकेंगे, जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

Ques: What new feature did NPCI unveil at the Global Fintech Festival 2025 for UPI transactions?

NPCI ने Global Fintech Festival 2025 में यूपीआई लेनसी नई सुविधा -देन के लिए कौन-की घोषणा की?

- A. UPI transactions via cryptocurrency / क्रिप्टोकॉरेन्सी के माध्यम से यूपीआई लेनदेन-
- B. On-device biometric authentication, UPI Lite for smart glasses, Aadhaar-based face authentication, and Multi-Signatory UPI / डिवाइसआधारित -

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट ग्लास के लिए यूपीआई लाइट, आधारआधारित फेस - ऑथेंटिकेशन और मल्टीसिग्रेचरी यूपीआई-

C. UPI only through debit cards / केवल डेबिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई

D. UPI PIN removal for all transactions / सभी लेनदेन के लिए यूपीआई पिन हटाना-

E. QR code payments disabled / क्यूआर कोड भुगतान बंद करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- At the Global Fintech Festival 2025, NPCI (with support from RBI/DFS) introduced several enhancements to UPI authentication.
- Global Fintech Festival 2025 में, NPCI (RBI/DFS के सहयोग से) ने यूपीआई (ऑथेंटिकेशन में कई नई सुविधाओं की घोषणा की।
- On-device biometric authentication allows fingerprint or facial recognition for transactions up to ₹5,000, avoiding the need to enter UPI PIN.
- डिवाइसआधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के तहत, 5,000 रुपये तक के लेनदेन में - फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती।
- UPI Lite for wearable smart glasses enables small-value, hands-free payments via voice command and QR code scanning.
- स्मार्ट ग्लास के लिए यूपीआई लाइट छोटे मूल्य वाले हाथ देन की सुविधा देता-मुक्त लेन- है, जिसमें वॉयस कमांड और क्यूआर कोड स्कैनिंग शामिल है।
- Aadhaar-based Face Authentication now allows setting or resetting UPI PINs quickly and inclusively, especially for first-time users and senior citizens.
- आधाररीसेट करने की प्रक्रिया को तेज़ / आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अब यूपीआई पिन से- और अधिक समावेशी बनाता है, विशेष रूप से नए उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
- Multi-Signatory UPI feature permits joint or multi-signatory accounts to approve payments through UPI smoothly.
- मल्टीसिग्रेचरी खातों को यूपीआई के -विधा से संयुक्त या मल्टीसिग्रेचरी यूपीआई सु- माध्यम से भुगतान को मंजूरी देने की सुविधा मिलती है।

Ques: Which bank received a 'Letter of Caution' from RBI for non-compliance with KYC norms?

RBI ने KYC मानदंडों का पालन न करने पर किस बैंक को 'चेतावनी पत्र' जारी किया?

- A. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D. Yes Bank / यस बैंक
- E. Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued a 'Letter of Caution' to Axis Bank for non-compliance with Know Your Customer (KYC) norms.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने KYC (अपने ग्राहक को जानिएमानदंडों का पालन न करने () पर एक्सिस बैंक Axis Bank) को 'चेतावनी पत्र' जारी किया है।
- The action came after RBI's review of Axis Bank's KYC compliance and internal systems.
- यह कार्रवाई RBI द्वारा Axis Bank की KYC अनुपालन और आंतरिक प्रणाली की समीक्षा के बाद की गई।
- Although the bank had taken corrective steps, RBI found it necessary to issue the caution to ensure strict adherence to its KYC instructions.
- बैंक द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बावजूद, RBI ने अपने KYC निर्देशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी देना आवश्यक समझा।
- The letter advises Axis Bank to exercise greater caution and diligence to prevent recurrence of such issues.
- यह पत्र Axis Bank को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह देता है।
- KYC norms play a crucial role in preventing money laundering and fraud within the banking system.
- KYC नियम बैंकिंग प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Ques: The Government of India has allowed candidates from which sector to apply for top management roles in public sector banks including SBI?

भारत सरकार ने किस क्षेत्र के उम्मीदवारों को एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है?

- A. Defence Sector / रक्षा क्षेत्र
- B. Education Sector / शिक्षा क्षेत्र
- C. Private Sector / निजी क्षेत्र
- D. Cooperative Sector / सहकारी क्षेत्र
- E. Agriculture Sector / कृषि क्षेत्र

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India has opened top management positions in public sector banks (PSBs), including SBI, for private sector candidates.
- भारत सरकार ने एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए शीर्ष प्रबंधन पद खोले हैं।
- One of the four Managing Director positions in SBI is now available to candidates from the private sector or those working in public sector financial institutions.
- एसबीआई में प्रबंध निदेशक के चार पदों में से एक पद निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए खोला गया है।
- This reform aims to enhance transparency, competition, and merit-based hiring in top PSB roles.
- यह सुधार पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और योग्यताआधारित भर्ती को बढ़ावा देने का उद्देश्य - रखता है।

Ques: Which bank launched the 'My Business QR' initiative to provide small merchants with digital profiles and mini online stores?

किस बैंक ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्रोफाइल और मिनी ऑनलाइन स्टोर प्रदान करने के लिए 'My Business QR' पहल शुरू की है?

- A. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

- B. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D. State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- E. Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- HDFC Bank launched the 'My Business QR' initiative, developed by the startup Vyaparify, to help small merchants create simple, scalable digital identities.
- एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप Vyaparify के सहयोग से 'My Business QR' पहल शुरू की, ताकि छोटे व्यापारियों को सरल और स्केलेबल डिजिटल पहचान बनाने में मदद मिल सके।
- When customers scan the QR, they can not only make payments but also view the shop's digital profile including name, address, phone number, and products.
- ग्राहक जब QR स्कैन करते हैं, तो वे केवल भुगतान नहीं कर सकते, बल्कि दुकान की डिजिटल प्रोफाइल जैसे नाम, पता, फोन नंबर और उत्पाद भी देख सकते हैं।
- The shop profile also functions as a mini online store where customers can browse products, place orders, and make payments online.
- यह डिजिटल प्रोफाइल मिनी ऑनलाइन स्टोर के रूप में भी काम करती है, जहाँ ग्राहक उत्पाद देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
- The initiative is part of HDFC Bank's 'Pitch for Business' program, supporting startups and innovators in presenting fintech solutions.
- यह पहल एचडीएफसी बैंक के 'Pitch for Business' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो स्टार्टअप और नवप्रवर्तकों को फिनटेक समाधान प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करता है।

About HDFC Bank :

- Established : August 1994
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Sashidhar Jagdishan
- Tagline : We Understand Your World

Ques: How much loan amount has SBI provided to MSMEs through the SME Digital Business Loans platform in the last 15 months?

प्रश्न एसबीआई ने पिछले :15 महीनों में SME डिजिटल बिजनेस लोन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई को कितनी राशि के ऋण प्रदान किए हैं?

- A. ₹54,000 crore
- B. ₹60,200 crore
- C. ₹74,434 crore
- D. ₹82,000 crore
- E. ₹90,000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) provided loans worth ₹74,434 crore to 2.25 lakh MSMEs via its SME Digital Business Loans platform in the last 15 months.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पिछले 15 महीनों में अपनी SME डिजिटल बिजनेस लोन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.25 लाख एमएसएमई को ₹74,434 करोड़ के ऋण प्रदान किए।
- The loans were sanctioned in less than one hour, highlighting SBI's focus on quick digital lending.
- ऋण को एक घंटे से कम समय में मंजूर किया गया, जो एसबीआई की डिजिटल लेंडिंग और त्वरित वितरण पर फोकस को दर्शाता है।
- Launched in June 2024, the platform allows MSME entrepreneurs to apply online for loans up to ₹5 crore.
- जून 2024 में लॉन्च किए गए इस प्लेटफॉर्म से एमएसएमई उद्यमी ₹5 करोड़ तक के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Ques: RBI will consolidate how many circulars into 238 Master Directions by October 2025?

RBI अक्टूबर 2025 तक कितने परिपत्रों को 238 मास्टर डायरेक्शंस में समाहित करेगा?

- A. 5,000
- B. 7,500
- C. 9,000
- D. 10,000

E. 3,500

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) will consolidate around 9,000 regulatory circulars issued by the Department of Regulation into 238 Master Directions.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विनियमन विभाग द्वारा जारी लगभग 9,000 परिपत्रों को 238 मास्टर डायरेक्शंस में समाहित करेगा।
 - These Master Directions will cover 11 types of regulated entities and 30 functional areas, simplifying the regulatory framework.
 - ये मास्टर डायरेक्शंस 11 प्रकार के नियामित संस्थानों और 30 कार्य क्षेत्रों को कवर करेंगे, जिससे नियामक ढांचा सरल बनेगा।
 - The move aims to reduce compliance burden, enhance clarity, and improve accessibility of rules for regulated entities.
 - इस कदम का उद्देश्य अनुपालन बोझ घटाना, स्पष्टता बढ़ाना, और नियामित संस्थानों के लिए नियमों की पहुंच बेहतर बनाना है।
 - RBI has also invited public feedback on these drafts till November 10, 2025.
 - RBI ने इन ड्राफ्ट्स पर सार्वजनिक सुझाव 10 नवंबर 2025 तक मांगे हैं।
-

Ques: Who has been appointed as the Executive Director of the Reserve Bank of India (RBI)?

किसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया है?

- A. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- B. Urjit Patel / उर्जित पटेल
- C. Viral Acharya / विरल अचार्य
- D. Raghuram Rajan / रघुराम राजन
- E. Sanjay Kumar Hansda / संजय कुमार हंसदा

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Sanjay Kumar Hansda has been appointed as the Executive Director (ED) of the Reserve Bank of India (RBI).
- संजय कुमार हंसदा को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया है।
- His appointment follows the completion of his deputation as Senior Adviser to ED (India) at the International Monetary Fund (IMF).
- उनकी नियुक्ति उनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में ED (India) के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ड्यूटी पूरी करने के बाद हुई है।
- As ED, Sanjay Hansda will oversee the Department of Economic and Policy Research (DEPR) of RBI.
- ED के रूप में, संजय हंसदा RBI के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) का संचालन करेंगे।

Ques: As per the RBI's new rule, for how long can exporters keep their foreign exchange proceeds in a Foreign Currency Account at IFSC?
RBI के नए नियम के अनुसार, निर्यातक अपने विदेशी मुद्रा आय को IFSC में विदेशी मुद्रा खाते में कितने समय तक रख सकते हैं?

- A. 1 month
- B. 2 months
- C. 3 months
- D. 6 months
- E. 12 months

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has allowed exporters to retain their foreign exchange proceeds in a Foreign Currency Account (FCA) at an International Financial Services Centre (IFSC) for up to 3 months.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में विदेशी मुद्रा खाते (FCA) में अपनी फॉरेक्स प्राप्तियों को 3 महीने तक रखने की अनुमति दी है।
- For accounts opened in any other jurisdiction, the time limit remains one month.

- अन्य किसी भी क्षेत्राधिकार में खोले गए खातों के लिए समय सीमा एक महीना ही रहेगी।
- This change was made by amending the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2015.
- यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) विनियम, 2015 में संशोधन करके किया गया है।
- The move aims to provide greater flexibility to exporters, especially those in high-value industries such as gems and jewellery.
- यह कदम निर्यातकों, विशेष रूप से रत्न और आभूषण जैसे उच्चमूल्य क्षेत्रों को अधिक - लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- Experts believe this will help reduce conversion costs, improve hedging, and minimize currency volatility risks.
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह संशोधन मुद्रा परिवर्तन लागत को कम, हेजिंग में सुधार, और मुद्रा उतारचढ़ाव के जोखिमों को घटाने में मदद करेगा।-

Ques: Which initiative has RBI launched to expand public awareness through WhatsApp?

आरबीआई ने WhatsApp के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कौनशुरू सी पहल-की है?

- A. RBI Digital Banking App / आरबीआई डिजिटल बैंकिंग ऐप
- B. RBI Kehta Hai verified WhatsApp channel / 'RBI कहता है' सत्यापित WhatsApp चैनल
- C. RBI SMS Alerts only / केवल आरबीआई एसएमएस अलर्ट
- D. RBI YouTube Awareness Campaign / आरबीआई यूट्यूब जागरूकता अभियान
- E. RBI Email Newsletter / आरबीआई ईमेल न्यूज़लेटर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has been running the 'RBI Kehta Hai' campaign across print, TV, radio, digital platforms, and SMS to spread public awareness.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 'RBI कहता है' अभियान के माध्यम से प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और SMS पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है।

- In April 2025, RBI launched its verified WhatsApp channel to share official updates and awareness messages with citizens.
- अप्रैल 2025 में, RBI ने नागरिकों तक आधिकारिक अपडेट और जागरूकता संदेश पहुंचाने के लिए अपना सत्यापित WhatsApp चैनल लॉन्च किया।
- Citizens can now receive official messages from RBI via verified WhatsApp accounts — 99309 91935 (new) and 99990 41935 (existing).
- अब नागरिक सत्यापित WhatsApp अकाउंट्स — 99309 91935 (नया और (99990 41935 (पहले से उपयोग में के माध्यम से (RBI से आधिकारिक संदेश प्राप्त कर सकते हैं।

Ques: Which organizations have launched the pilot for AI-driven UPI payments on ChatGPT in India?

भारत में ChatGPT पर AI-ड्रिवन UPI पेमेंट्स के लिए पायलट किसने शुरू किया है?

- A. RBI / आरबीआई
- B. NPCI and Razorpay / NPCI और Razorpay
- C. Paytm / पेटीएम
- D. SBI / एसबीआई
- E. Google Pay / गूगल पे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The National Payments Corporation of India (NPCI) and Razorpay, in collaboration with Microsoft-backed OpenAI, have launched a pilot for AI-driven e-commerce payments using ChatGPT.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और Razorpay ने Microsoft समर्थित OpenAI के साथ मिलकर ChatGPT पर AI-आधारित ईकॉमर्स भुगतान के लिए एक - पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
- The pilot allows users to make UPI-based payments and shop online directly through ChatGPT.
- यह पायलट यूज़र्स को ChatGPT के माध्यम से सीधे UPI पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा देता है।
- BigBasket is one of the first merchants onboarded, while Axis Bank and Airtel Payments Bank are banking partners.

- BigBasket पहला मर्चेट पार्टनर है, जबकि Axis Bank और Airtel Payments Bank बैंकिंग पार्टनर हैं।
- The initiative showcases how AI agents can securely complete user-controlled transactions using biometric and PIN-based authentication.
- यह पहल दिखाती है कि AI एजेंट्स बायोमेट्रिक और PIN सत्यापन के माध्यम से सुरक्षित और यूज़रते हैं। नियंत्रित भुगतान कर सक-

Ques: What is the target percentage of female workforce SBI aims to achieve by 2030?

एसबीआई का 2030 तक महिला कार्यबल का लक्ष्य कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का है?

- A. 25%
- B. 27%
- C. 30%
- D. 33%
- E. 35%

Answer: C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) has set a target to increase its female workforce to 30% by 2030 as part of its gender diversity initiative.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी लैंगिक विविधता पहल के तहत 2030 तक महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
- Currently, women constitute 27% of SBI's total workforce, with around 33% representation in frontline roles.
- वर्तमान में एसबीआई के कुल कर्मचारियों में 27% महिलाएं हैं, जबकि फ्रंटलाइन पदों पर यह संख्या लगभग 33% है।
- The initiative aims to promote inclusivity, gender balance, and equal opportunities across all levels of the organization.
- यह पहल संगठन में समावेशिता, लैंगिक संतुलन और सभी स्तरों पर समान अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

Ques: Jio Payments Bank has won the MLFF project to implement FASTag-based ANPR system between which two cities?

जियो पेमेंट्स बैंक को FASTag आधारित ANPR सिस्टम लागू करने का MLFF प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच मिला है?

- A. Delhi and Agra / दिल्ली और आगरा
- B. Mumbai and Pune / मुंबई और पुणे
- C. Gurugram and Jaipur / गुरुग्राम और जयपुर
- D. Bengaluru and Mysuru / बेंगलुरु और मैसूरु
- E. Hyderabad and Vijayawada / हैदराबाद और विजयवाड़ा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Jio Payments Bank, a subsidiary of Jio Financial Services, has secured a contract to implement the FASTag-based Automatic Number Plate Recognition (ANPR) system under the Multi-Lane Free Flow (MLFF) toll collection project.
- जियो पेमेंट्स बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी, को FASTag आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली लागू करने का MLFF टोल कलेक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
- The MLFF system will be operational at two toll plazas between Gurugram and Jaipur, enabling automatic toll deduction from FASTag-linked accounts without physical toll booths.
- यह MLFF प्रणाली गुरुग्राम और जयपुर के बीच दो टोल प्लाज़ा पर लागू होगी, जो FASTag से जुड़े खातों से स्वतः टोल राशि काटने की सुविधा प्रदान करेगी और भौतिक टोल बूथों की आवश्यकता को समाप्त करेगी।

Ques: What are the key changes introduced in the Reserve Bank of India's bank locker rules for 2025?

भारतीय रिज़र्व बैंक के 2025 के बैंक लॉकर नियमों में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

- A. Mandatory revised agreement and digital copy for customers / ग्राहकों के लिए अनिवार्य संशोधित अनुबंध और डिजिटल कॉपी
- B. Biometric access, 24x7 CCTV, and alerts on locker access / बायोमेट्रिक एक्सेस,

24x7 CCTV, और लॉकर खोलने पर सूचनाएँ

C. Compensation up to 100 times annual rent if the bank is at fault / बैंक की गलती पर वार्षिक किराए का 100 गुना मुआवजा

D. Updated indicative annual rent based on locker size and city / लॉकर के आकार और शहर के अनुसार अद्यतन वार्षिक किराया

E. All of the above / ऊपर के सभी

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- RBI is introducing new bank locker rules in 2025 that are designed to be safe, transparent, and customer-friendly.
- RBI 2025 में ऐसे नए बैंक लॉकर नियम लागू कर रहा है जो सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहकअनुकूल होंगे।-

Key changes in Bank Locker Rules 2025 / 2025 के बैंक लॉकर नियमों में प्रमुख बदलाव:

Locker Agreement / लॉकर अनुबंध

- Mandatory revised agreement for all users.
- Banks will provide a copy of the agreement physically or digitally.
- Agreement will clearly detail the rights and obligations of both parties.
- सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य संशोधित अनुबंध।
- बैंक अनुबंध की प्रति भौतिक या डिजिटल रूप में प्रदान करेंगे।
- अनुबंध में दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे।

Security Measures / सुरक्षा उपाय

- Biometric access, 24x7 CCTV, and alerts whenever the locker is opened.
- CCTV footage will be stored for at least 180 days.
- Customers will get instant SMS/email notifications on locker access.
- बायोमेट्रिक एक्सेस, 24x7 CCTV, और लॉकर खोलने पर सूचनाएँ।
- CCTV फुटेज कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रहेगा।
- लॉकर खोलने पर ग्राहकों को तुरंत SMS/email द्वारा सूचित किया जाएगा।

Compensation for Loss / नुकसान के लिए मुआवजा

- Bank will pay up to 100 times the annual rent if found at fault.
- बैंक की गलती होने पर वार्षिक किराए का 100 गुना मुआवजा।

Annual Rent / वार्षिक किराया

- Updated indicative rent ranges from ₹2,000 to ₹10,000 depending on locker size and city.
- लॉकर के आकार और शहर के अनुसार ₹2,000 – ₹10,000 वार्षिक किराया।

Prohibited Items / प्रतिबंधित वस्तुएँ

- Customers can store jewelry, property papers, insurance policies, and confidential documents.
- Cash, arms, explosives, or hazardous items are strictly prohibited.
- ग्राहक आभूषण, संपत्ति दस्तावेज़, बीमा पॉलिसी और गोपनीय दस्तावेज़ रख सकते हैं।
- नकद, हथियार, विस्फोटक और हानिकारक वस्तुओं पर प्रतिबंध।

Ques: According to CBDT data, India's net direct tax collection grew by what percentage to ₹11.89 lakh crore during April–October 2025?

CBDT के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर ₹11.89 लाख करोड़ हुआ?

- A. 4.8%
- B. 5.5%
- C. 6.3%
- D. 7.2%
- E. 8.1%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As per CBDT, India's net direct tax collection rose 6.33% to ₹11.89 lakh crore in April–October 2025, driven by strong non-corporate tax receipts and a drop

in refunds.

- CDBT के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर 2025 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.33% बढ़कर ₹11.89 लाख करोड़ हुआ, जो गैरकारपोरेट कर संग्रह में वृद्धि और रिफंड में कमी के कारण - संभव हुआ।
- Non-corporate taxpayers (individuals, HUFs, firms, associations, local authorities, artificial juridical persons) contributed ₹6.56 lakh crore, while corporate tax collection stood at ₹5.02 lakh crore.
- गैरव्यक्ति) कारपोरेट करदाताओं-, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, संघ, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का योगदान (₹6.56 लाख करोड़ रहा, जबकि कॉरपोरेट कर संग्रह ₹5.02 लाख करोड़ रहा।
- Refund issuances dropped by 16% to ₹2.03 lakh crore, helping boost net collections.
- रिफंड जारी करने में 16% की गिरावट रही और यह ₹2.03 लाख करोड़ रहा, जिससे शुद्ध संग्रह में वृद्धि हुई।

Ques: Which city has launched India's first QR code-based kiosk for traffic challan payments?

भारत का पहला QR कोडआधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क किस शहर में लॉन्च - किया गया है?

- A. Mumbai / मुंबई
- B. Gurugram / गुरुग्राम
- C. Bengaluru / बेंगलुरु
- D. Hyderabad / हैदराबाद
- E. Pune / पुणे

Answer: B

Explanation / व्याख्या:

- Gurugram has become the first city in India to introduce a QR code-based digital kiosk for paying traffic challans.
- गुरुग्राम देश का पहला शहर बन गया है जिसने QR कोडआधारित डिजिटल कियोस्क के - माध्यम से ट्रैफिक चालान भुगतान की सुविधा शुरू की है।
- The kiosk was developed jointly by Gurugram Police and the Gurugram

Metropolitan Development Authority (GMDA) to make challan payments faster, simpler, and cashless.

- इस कियोस्क को गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने मिलकर विकसित किया है, ताकि चालान भुगतान तेज़, सरल और कैशलेस हो सके।
- The project is part of a Corporate Social Responsibility (CSR) initiative and is expected to be expanded to more high-footfall locations across the city to promote digital governance and public convenience.
- यह परियोजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल का हिस्सा है और इसे नागरिक सुविधा और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए शहर के अन्य व्यस्त क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है।

Ques: The Government of India has revised guidelines to allow candidates from which sector to apply for top leadership roles like Managing Director (MD) in SBI and Executive Director (ED) in Public Sector Banks (PSBs)?

भारत सरकार ने किस क्षेत्र के उम्मीदवारों को SBI में प्रबंध निदेशक (MD) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में कार्यकारी निदेशक (ED) जैसे शीर्ष पदों के लिए आवेदन की अनुमति देने हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया है-?

- A. Defence Sector / रक्षा क्षेत्र
- B. Private Sector / निजी क्षेत्र
- C. Cooperative Sector / सहकारी क्षेत्र
- D. Public Enterprises / सार्वजनिक उपक्रम
- E. Non-Banking Financial Companies (NBFC) Sector / गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The government has revised the rules so that key senior leadership positions in Public Sector Banks (PSBs)—such as Managing Director (MD) roles in SBI and Executive Director (ED) roles across PSBs—are now open to private sector (external) candidates.
- सरकार ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में वरिष्ठ नेतृत्व पद — जैसे SBI में प्रबंध निदेशक (MD) और अन्य PSBs में कार्यकारी निदेशक (ED) — निजी क्षेत्र (बाहरी उम्मीदवारों) के लिए भी खुले होंगे।

- Earlier, these top posts were typically filled by officers already working within PSBs. Under the new rules, at least one MD post in SBI (out of multiple MD positions) will be open to external applicants.
- पहले ये शीर्ष पद केवल PSB के आंतरिक अधिकारियों द्वारा ही भरे जाते थे। नए नियमों के तहत, SBI के कई MD पदों में से कमकम एक पद-से- अब बाहरी उम्मीदवारों के लिए खुला रहेगा।
- Officers from PSBs at General Manager (GM) or Chief General Manager (CGM) level may also qualify under specific conditions.
- PSB के महाप्रबंधक (GM) या मुख्य महाप्रबंधक (CGM) स्तर के अधिकारी भी कुछ शर्तों के तहत पात्र होंगे।
- Candidates serving as Chief Vigilance Officers (CVOs) are not eligible for these top positions.
- मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में कार्यरत उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।
- The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) will conduct the selection process, including behavioural and competency assessments.
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) चयन प्रक्रिया संचालित करेगा, जिसमें व्यवहारिक और क्षमता मूल्यांकन शामिल होगा।

Eligibility for private sector candidates / निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए पात्रता:

- SBI MD : 21 years total experience (including 15 years in banking) / कुल 21 वर्ष का अनुभव जिसमें 15 वर्ष बैंकिंग में (. Must have served either 2 years at Board level or 3 years at one level below Board / बोर्ड स्तर पर 2 वर्ष या बोर्ड से नीचे एक स्तर पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक
- ED in Nationalised Banks : 18 years total experience (including 12 years in banking) / कुल 18 वर्ष का अनुभव जिसमें 12 वर्ष बैंकिंग में (. Must have served 3 years at the highest level below Board / बोर्ड से नीचे उच्चतम स्तर पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक

Ques: What was India's retail inflation rate in September 2025 — the lowest in 8 years?

सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर, जो 8 साल में सबसे कम रही, कितनी थी?

- A. 2.6%
- B. 1.8%
- C. 1.54%
- D. 1.46%
- E. 3.1%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's retail inflation (CPI) fell sharply to 1.54% in September 2025, the lowest since June 2017, due to a decline in food and fuel prices.
- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर 1.54% पर आ गई, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है, इसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में कमी रहा।
- Core inflation, excluding food and fuel, inched up slightly to 4.43% due to rising precious metal prices.
- कोर मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर (भोजन और ईंधन को छोड़कर) 4.43% पर पहुंच गई, कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण।
- The Consumer Food Price Index (CFPI) remained at -2.28%, reflecting cheaper food items.
- खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) -2.28% पर रहा, जो भोजन की वस्तुओं के सस्ते होने को दर्शाता है।
- The rate is below RBI's lower tolerance band of 2%, signaling potential for monetary easing in December.
- यह दर RBI के 2% के निचले सहनशीलता बैंड से नीचे है, जिससे दिसंबर में मौद्रिक राहत की संभावना बढ़ गई है।

Ques: Which institution launched four new digital payment initiatives — including IoT-based UPI Payments and UPI Reserve Pay — at the Global Fintech Fest 2025?

किस संस्था ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में IoT-आधारित UPI भुगतान और UPI रिजर्व पे सहित चार नई डिजिटल भुगतान पहल शुरू कीं?

- A. National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- B. Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक

- C. State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- D. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E. NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) launched four digital payment initiatives aimed at improving customer convenience and innovation in the fintech ecosystem during the Global Fintech Fest 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में ग्राहक सुविधा और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चार नई डिजिटल भुगतान पहलें शुरू कीं।

Here are the four initiatives / चार प्रमुख पहलें:

IoT-based UPI Payments / IoT-आधारित UPI भुगतान

- Enables UPI transactions through connected smart devices (like smart cars, TVs, or wearables).
- स्मार्ट कार, टीवी, या वियरेबल जैसे स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से स्वचालित रूप से UPI लेनदेन की सुविधा देता है।

**Banking Connect (Interoperable Net Banking) / बैंकिंग कनेक्ट संचालनीय -अंतर)
(नेट बैंकिंग)**

- Provides a single interface for merchants and payment aggregators to connect with multiple banks — eliminating the need for multiple integrations.
- व्यापारियों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म से कई बैंकों से जुड़ने की सुविधा देता है, जिससे बारबार इंटीग्रेशन की आवश्यकता समाप्त होती है।-

UPI Reserve Pay / UPI रिज़र्व पे

- Allows users to reserve a part of their credit card or pre-approved credit line for UPI payments, simplifying repeat transactions.
- उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडिट कार्ड या पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन का एक हिस्सा-UPI भुगतान के लिए आरक्षित करने की सुविधा देता है।

AI-based UPI HELP / एआई आधारित-UPI हेल्प

- An AI-powered helper (developed using NPCI's small language model) that assists users with payments, mandates, dispute resolution, and status tracking.
- NPCI के स्मॉल लैंग्वेज मॉडल द्वारा संचालित एआई सहायक जो भुगतान, मैंडेट, विवाद निवारण और स्थिति जांच में उपयोगकर्ताओं की सहायता करता है।

Ques: What is the Flipkart Bharat Yatra Card, and which payment network powers it?

फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड क्या है, और इसे किस भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है?

- A. A credit card powered by Visa / वीज़ा द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड
- B. A debit card powered by Mastercard / मास्टरकार्ड द्वारा संचालित डेबिट कार्ड
- C. A prepaid transit card powered by RuPay / रूपे पे संचालित प्रीपेड ट्रांज़िट कार्ड
- D. A loyalty card powered by American Express / अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा संचालित लॉयल्टी कार्ड
- E. A gift card powered by UPI / यूपीआई द्वारा संचालित गिफ्ट कार्ड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Flipkart Bharat Yatra Card is a prepaid transit card that enables seamless cashless travel across metros, buses, and other public transport networks supporting the National Common Mobility Card (NCMC) standard.
- फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड एक प्रीपेड ट्रांज़िट कार्ड है जो मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में बिना नकद भुगतान के यात्रा की सुविधा प्रदान करता है और यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) मानक का समर्थन करता है।
- It is powered by the RuPay payment network and is available in cities including New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, and Ahmedabad.
- यह रूपे भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित है और नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद में उपलब्ध है।
- The card can be used for offline transactions up to a balance of ₹2,000.
- इस कार्ड का उपयोग ऑफ़लाइन लेन-देन के लिए ₹2,000 तक के बैलेंस तक किया जा

सकता है।

Ques: What is the main purpose of RBI's Digital Payments Intelligence Platform (DPIP)?

आरबीआई के डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A. Boost UPI transaction limits / यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाना
- B. Detect and prevent payment frauds in real time / भुगतान धोखाधड़ी की रियल-टाइम पहचान और रोकथाम
- C. Promote credit card usage / क्रेडिट कार्ड उपयोग को बढ़ावा देना
- D. Enable offline digital payments / ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना
- E. Create a digital rupee monitoring system / डिजिटल रुपये की निगरानी प्रणाली बनाना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Digital Payments Intelligence Platform (DPIP) is an AI-driven initiative by RBI aimed at detecting and preventing payment frauds in real time.
- डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) भारतीय रिज़र्व बैंक की एआईआधारित - पहल है, जिसका उद्देश्य भुगतान धोखाधड़ी की रियलटाइम पहचान और रोकथाम करना - है।
- Phase 1 involves a negative registry integrating data from banks, telecom operators, and the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C).
- पहले चरण में नेगेटिव रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसमें बैंकों, टेलीकॉम ऑपरेटरों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) का डेटा जोड़ा गया है।
- Phase 2 will enable real-time sharing of fraud-related data among banks to allow preventive actions like verification or temporary debit freezes.
- दूसरे चरण में बैंक धोखाधड़ी से संबंधित डेटा रियलटाइम में साझा करेंगे-, ताकि पूर्व-निवारक कार्रवाई जैसे सत्यापन या अस्थायी डेबिट फ्रीज की जा सके।
- AI-based models alert banks instantly about potential fraud transactions, enhancing payment security.
- एआई मॉडल संभावित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में तुरंत बैंकों को अलर्ट करेंगे, जिससे भुगतान सुरक्षा बढ़ेगी।

Ques: Which bank signed an MoU with the BSF under the Rakshak Salary Package to enhance financial benefits for personnel and veterans?

कौन सा बैंक BSF के साथ रक्षक सैलरी पैकेज के तहत कर्मियों और वेटरन्स के लिए वित्तीय लाभ बढ़ाने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किया?

- A. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B. Bank of India / बैंक ऑफ इंडिया
- C. Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- D. Canara Bank / केनरा बैंक
- E. HDFC Bank / HDFC बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Bank of India signed a Memorandum of Understanding with the Border Security Force (BSF) under the Rakshak Salary Package to provide enhanced financial benefits to BSF personnel and veterans.
- बैंक ऑफ इंडिया ने BSF कर्मियों और वेटरन्स को बेहतर वित्तीय लाभ देने के लिए रक्षक सैलरी पैकेज के तहत सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- Enhanced Personal Accident Insurance: Complimentary coverage up to ₹1 crore
- व्यक्तिगतरूप से दुर्घटना बीमा बढ़ाया : ₹1 करोड़ तक निशुल्क कवरेज:
- Air Accident Coverage: Coverage up to ₹2 crore
- हवाई दुर्घटना कवरेज : ₹2 करोड़ तक कवरेज

About Bank of India :

- Established : 7 September 1906
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Rajneesh Karnatak
- Tagline : Relationship beyond Banking

Ques: Which company has partnered with NPCI to launch India's first wearable payments ecosystem?

भारत का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए NPCI ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A. PhonePe / फोनपे
- B. Paytm / पेटीएम
- C. Muse Wearables / म्यूज़ वेयरेबल्स
- D. Pine Labs / पाइन लैब्स
- E. Razorpay / रेज़रपे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Muse Wearables, an IIT-Madras-incubated startup, has partnered with NPCI to launch India's first wearable payments ecosystem using smart rings called "Ring One."
- IIT-मद्रास से शुरू हुआ स्टार्टअप Muse Wearables ने NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें "Ring One" स्मार्ट रिंग का उपयोग किया जाता है।
- The ecosystem uses Muse Wallet and the RuPay network, enabling secure, contactless payments without a phone, card, or wallet.
- यह प्रणाली Muse Wallet और RuPay नेटवर्क पर आधारित है, जिससे उपयोगकर्ता बिना फोन, कार्ड या वॉलेट के सुरक्षित और कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं।
- Muse Wallet also serves as India's first secure element tokenisation platform, converting card details into secure digital tokens for safer transactions.
- Muse Wallet भारत का पहला सुरक्षित टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है, जो कार्ड की जानकारी को डिजिटल टोकन में बदलकर भुगतान को और सुरक्षित बनाता है।

Ques: What are the key changes introduced by RBI in 2025 regarding CIBIL scores for bank customers?

2025 में बैंक ग्राहकों के लिए CIBIL स्कोर के संबंध में RBI द्वारा कौनख बदलाव कौन से प्रमु-किए गए हैं?

- A. CIBIL scores will now be updated twice a month / CIBIL स्कोर अब महीने में दो

बार अपडेट होंगे

B. Customers will be informed whenever their score is checked / जब भी ग्राहक का स्कोर देखा जाएगा, उन्हें सूचित किया जाएगा

C. Banks cannot reject requests secretly; reasons must be communicated / बैंक गुप्त रूप से अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकते; कारण बताना अनिवार्य है

D. Customers get one free full credit report per year / ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी

E. All of the above / ऊपर के सभी

Answer: Options E

Explanation / व्याख्या:

• RBI has introduced six rules to improve transparency and customer benefits related to CIBIL scores:

• RBI ने CIBIL स्कोर से संबंधित पारदर्शिता और ग्राहक लाभ बढ़ाने के लिए छह नियम लागू किए हैं:

- **Faster updates:** CIBIL scores will now be updated every 15 days.

तेज़ अपडेट: CIBIL स्कोर अब हर 15 दिन में अपडेट होंगे।

- **Customer notification:** Customers must be informed whenever their score is checked.

ग्राहक को सूचना: जब भी बैंक ग्राहक का स्कोर देखे, ग्राहक को सूचित करना अनिवार्य है।

- **No secret rejections:** Banks cannot reject requests secretly; reasons must be communicated.

गुप्त अस्वीकृति नहीं: बैंक गुप्त रूप से अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकते; कारण बताना अनिवार्य है।

- **Free annual report:** Credit companies must provide one free full credit report per year.

वार्षिक मुफ्त रिपोर्ट: क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में प्रदान करनी होगी।

- **Default notifications:** Customers must be informed if reported as defaulters.

डिफॉल्ट की सूचना: यदि ग्राहक को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किया जाए, तो उन्हें सूचित करना अनिवार्य है।

- **Resolution timeline:** Issues must be resolved within 30 days; banks and

credit companies have defined timelines with penalties for delays.

- Once a bank informs a credit information company about an error, the company must address it within 9 days. Similarly, banks must resolve customer complaints within 21 days.
- If they fail to do so, the responsible party will face a penalty of ₹100 per day for the delay.

समाधान की समय सीमा: समस्याओं को 30 दिनों में हल करना अनिवार्य है; विलंब होने पर ₹100 प्रति दिन का जुर्माना लागू होगा।

जब कोई बैंक किसी क्रेडिट सूचना कंपनी को किसी त्रुटि की सूचना देता है, तो कंपनी को 9 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। इसी प्रकार, बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 21 दिनों के भीतर करना होगा।

यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष को प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना देना होगा।

Ques: Under the new EPFO withdrawal rules, what percentage of the Provident Fund balance can members now withdraw?

EPFO के नए नियमों के तहत सदस्य अब अपने भविष्य निधि (PF) बैलेंस का कितना प्रतिशत निकाल सकते हैं?

- A. 50%
- B. 75%
- C. 90%
- D. 100%
- E. 25%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The EPFO has approved liberalised withdrawal rules, merging 13 old provisions into a single streamlined framework, allowing members to withdraw up to 100% of their EPF balance.
- EPFO ने 13 पुराने प्रावधानों को मिलाकर सरल ढांचा बनाया है, जिससे सदस्य अब अपने EPF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं।
- Withdrawals are categorised into Essential Needs (illness, education, marriage), Housing Needs, and Special Circumstances.

- निकासी को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है — मूलभूत आवश्यकताएँ (बीमारी), शिक्षा, विवाह(, आवास संबंधी आवश्यकताएँ और विशेष परिस्थितियाँ।
- Minimum service requirement reduced to 12 months, and 25% of contributions will remain as a mandatory balance.
- न्यूनतम सेवा अवधि 12 माह कर दी गई है, और 25% योगदान खाते में न्यूनतम शेष राशि के रूप में रखा जाएगा।
- No documentation or specific reason is required, simplifying access for over 7 crore subscribers.
- अब किसी दस्तावेज़ या कारण की आवश्यकता नहीं है, जिससे 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए प्रक्रिया आसान हो गई है।

Ques: NPCI International Payments Ltd (NIPL) has signed an MoU with which company for UPI acceptance in Japan?

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने जापान में UPI स्वीकार्यता के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है?

- A. Sony Japan / सोनी जापान
- B. NTT DATA Japan / एनटीटी डाटा जापान
- C. Rakuten Payments / राकुटेन पेमेंट्स
- D. SoftBank Pay / सॉफ्टबैंक पे
- E. Mitsubishi Finance / मित्सुबिशी फाइनेंस

Answer : Option B

Explanation / व्याख्या:

- NIPL (NPCI International Payments Ltd) has signed a pact with NTT DATA Japan to enable UPI-based payments in the Japanese market.
- एनआईपीएल ने एनटीटी डाटा जापान के (एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) साथ एक समझौता किया है ताकि जापानी बाजार में यूपीआईआधारित भुगतान संभव हो सके।
- NTT DATA Japan operates CAFIS®, Japan's largest card payment network, which will facilitate UPI QR-based transactions.
- एनटीटी डाटा जापान CAFIS®, जो जापान का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क है, का संचालन करती है, जो UPI QR आधारित लेनदेन को सक्षम बनाएगा।

- This move aims to promote India's digital payment ecosystem globally and improve cross-border transaction convenience.
- यह कदम भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और सीमा-पार लेनदेन की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Ques: What is the extended deadline for the 16th Finance Commission to submit its report?

16वीं वित्त आयोग की अपनी रिपोर्ट जमा करने की बढ़ाई गई समयसीमा क्या है?

- A. October 31, 2025
- B. November 30, 2025
- C. December 31, 2025
- D. January 31, 2026
- E. February 28, 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India has extended the tenure of the 16th Finance Commission by one month, moving the report submission deadline from October 31 to November 30, 2025.
- भारत सरकार ने 16वीं वित्त आयोग की कार्यकाल अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक बढ़ गई है।
- The Commission is chaired by Arvind Panagariya and is responsible for recommending the distribution of tax revenues between the Centre and states for the 2026–2031 period.
- आयोग की अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया कर रहे हैं और इसका कार्य 2026–2031 अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण की सिफारिश करना है।
- Constituted on December 31, 2023, the 16th Finance Commission is a constitutional body providing guidance on Centre-State fiscal relations.
- 16वीं वित्त आयोग की स्थापना 31 दिसंबर 2023 को हुई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

About the finance commission:

- Constituted by : President of India under Article 280 of Indian constitution in Every fifth year
- Total member : 5 (1 Chairman)
- 1st commission formed : 22 November 1951
- 16th Commission period : April 1, 2026 to March 31, 2031 (Chairman : Dr Arvind Panagariya)
- Full-time member of 16th Finance Commission : Annie George Mathew – Retired bureaucrat , Manoj Panda – Economist
- 16th Commission Secretary : Ritvik Ranjanam Pandey

Ques: When was the RBI Retail Direct Scheme (RDS) launched to allow individual investors to invest directly in Government Securities (G-Secs)?
व्यक्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों)G-Secs) में सीधे निवेश की अनुमति देने के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम)RDS) कब शुरू की गई थी?

- A) January 2020
- B) November 2021
- C) March 2022
- D) July 2023
- E) April 2024

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) launched the Retail Direct Scheme (RDS) in November 2021 as a one-stop platform for individual investors to invest directly in Government Securities (G-Secs).
- भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने नवंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम)RDS) लॉन्च की, जो व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों)G-Secs) में सीधे निवेश करने का वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।
- Under this scheme, investors can open a Retail Direct Gilt (RDG) Account free of cost, and invest in T-Bills, G-Secs, State Development Loans (SDLs), and Sovereign Gold Bonds (SGBs).

- इस योजना के तहत निवेशक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) अकाउंट निशुल्क खोल सकते हैं और T-Bills, G-Secs, राज्य विकास ऋण (SDLs) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs) में निवेश कर सकते हैं।
- The scheme has witnessed strong growth, with RDG accounts rising 82.5% YoY to 3,12,618 and secondary market trading volume increasing 6.43 times to ₹5,293 crore in 2025.
- इस योजना ने तेज़ी से वृद्धि देखी है, RDS के तहत खुले खाते 82.5% साल साल बढ़कर-दर-3,12,618 हो गए और 2025 में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम 6.43 गुना बढ़कर ₹5,293 करोड़ हो गया।
- The scheme aims to provide safer fixed-income investment options amid falling bank deposit rates and volatile stock markets.
- योजना का उद्देश्य बैंक जमा दरों में गिरावट और अस्थिर शेयर बाजार के बीच सुरक्षित फिक्स्ड-इनकम निवेश विकल्प प्रदान करना है।-

Ques: Under which fund did NABARD recently announce its investment at the Global Fintech Festival 2025?

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में नाबार्ड ने किस फंड के तहत निवेश की घोषणा की?

- A. AgriVikas Fund / एग्रीविकास फंड
- B. AgriSURE Fund / एग्रीश्योर फंड
- C. RuralTech Fund / रूरलटेक फंड
- D. Kisan Innovation Fund / किसान इनोवेशन फंड
- E. FinAgri Fund / फिनएग्री फंड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- NABARD announced its investment under the AgriSURE Fund, jointly promoted by the Union Agriculture Ministry and NABARD, at the Global Fintech Festival (GFF) 2025.
- नाबार्ड ने एग्रीश्योर फंड के तहत निवेश की घोषणा की, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) 2025 में।
- Fambo Innovation Pvt Ltd, a startup revolutionising the agri-food supply chain, became the first investee startup under the fund.

- फैंबो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो एग्रीचेन में नवाचार कर रहा है फूड सप्लाई-, एग्रीशोर फंड के तहत पहला निवेश प्राप्त करने वाला स्टार्टअप बना।
- Other supported entities include Kuberjee Tech Pvt Ltd (tech-driven financial solutions), NAVADHAN Capital (credit support for small farmers and rural entrepreneurs), and SLO Technologies (Advarisk) offering real-time collateral management.
- अन्य समर्थित इकाइयों में क्यूबरजी टेक प्राआधारित वित्तीय समाधा-तकनीक) .लि .न(, नवधान कैपिटल (छोटे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए ऋण सहायता), और एसएलओ टेक्नोलॉजीज शामिल हैं (स्कएडवारि), जो रियलटाइम कोलेट्रल मैनेजमेंट - प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं।
- NABARD emphasized that integrating FinTech and AgriTech innovations can enhance rural credit systems, transparency, and outreach to remote communities.
- नाबार्ड ने कहा कि फिनटेक और एग्रीटेक नवाचारों का एकीकरण ग्रामीण ऋण प्रणाली, पारदर्शिता और दूरस्थ समुदायों तक पहुंच को मजबूत कर सकता है।

Ques: How many UPI transactions were processed in September 2025?
सितंबर 2025 में कितने UPI लेनदेन संसाधित किए गए-?

- A. 20.01 billion
- B. 19.63 billion
- C. 18.75 billion
- D. 21.5 billion
- E. 22.0 billion

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Unified Payments Interface (UPI), operated by NPCI, processed 19.63 billion transactions in September 2025, down from 20.01 billion in August.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित UPI ने सितंबर 2025 में 19.63 अरब लेनदेन संसाधित किए-, जो अगस्त के 20.01 अरब लेन देन से-कम हैं।
- Despite the slight decline in transaction volume, the total transaction value increased marginally to ₹24.90 lakh crore from ₹24.85 lakh crore in the previous month.

- लेनदेन की संख्या में मामूली गिरावट के बावजूद-, कुल लेनदेन का मूल्य पिछले महीने के ₹24.85 लाख करोड़ से बढ़कर ₹24.90 लाख करोड़ हो गया।
- Daily transactions increased to 654 million from 645 million, and the daily transaction value rose to ₹82,991 crore from ₹80,177 crore.
- दैनिक लेन देन-645 मिलियन से बढ़कर 654 मिलियन हो गया, और दैनिक लेनदेन का - मूल्य ₹80,177 करोड़ से बढ़कर ₹82,991 करोड़ हो गया।

Ques: Who will inaugurate four farmers' training and agro-processing centres in Koppal, Raichur, Ballari, and Vijayanagara districts of Karnataka?

कर्नाटक के कोप्पल, रायचूर, बल्लारी और विजयनगर जिलों में चार किसान प्रशिक्षण और एग्रोप्रोसेसिंग केंद्रों का उद्घाटन कौन करेंगे-?

- A. Narendra Singh Tomar / नरेंद्र सिंह तोमर
- B. Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- C. Amit Shah / अमित शाह
- D. Piyush Goyal / पीयूष गोयल
- E. Rajnath Singh / राजनाथ सिंह

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Finance Minister Nirmala Sitharaman will inaugurate four farmers' training and agro-processing centres in Koppal, Raichur, Ballari, and Vijayanagara districts of Kalyana Karnataka.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक के कोप्पल, रायचूर, बल्लारी और विजयनगर जिलों में चार किसान प्रशिक्षण और एग्रोकेंद्रों का उद्घाटन करेंगी। प्रोसेसिंग-
- The centres are being established with MPLADS funds and in collaboration with NABARD.
- ये केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत और नाबार्ड (NABARD) के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं।
- The initiative aims to strengthen the agricultural value chain, increase farmers' income, generate rural employment, and promote self-reliance among farming communities.
- इस पहल का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना,

ग्रामीण रोजगार सृजन करना और किसान समुदायों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

- Each centre will focus on modern processing infrastructure, training facilities, and market linkages tailored to the agricultural strengths of each district, anchored by Farmer Producer Organisations (FPOs) with NABARD support.
- प्रत्येक केंद्र को आधुनिक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण सुविधाओं और मार्केट लिंकिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रत्येक जिले की कृषि क्षमता के अनुरूप होगा, और इसे किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा नाबार्ड के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

Ques: From October 1, 2025, what are the key rules and restrictions imposed by RBI on gold loans?

1 अक्टूबर 2025 से आरबीआई द्वारा सोने के ऋण पर कौनकौन से प्रमुख नियम और - प्रतिबंध लगाए गए हैं?

- A. Gold loans can be used to purchase jewelry and ETFs / सोने के ऋण का उपयोग आभूषण और ETF खरीदने के लिए किया जा सकता है
- B. Loans cannot be taken to purchase gold or silver in any form / किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदने के लिए ऋण नहीं लिया जा सकता
- C. Gold loans are available without repayment limits / सोने के ऋण पर कोई पुनर्भुगतान सीमा नहीं है
- D. Only gold coins are restricted / केवल सोने के सिक्कों पर प्रतिबंध है
- E. Gold loans are now interest-free / सोने के ऋण अब बिना ब्याज के हैं

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- From October 1, 2025, RBI rules restrict borrowers from taking loans from banks or NBFCs to purchase gold or silver in any form, including jewelry, coins, ETFs, or mutual funds.
- किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदने के लिए ऋण लेने पर 1 अक्टूबर 2025 से RBI ने रोक लगा दी है, इसमें आभूषण, सिक्के, ETF और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
- Loans against unprocessed/raw gold or silver are also prohibited.
- कच्चे या अपप्रोसेस्ड सोनेचांदी के खिलाफ ऋण लेना भी अनुमति नहीं है।/
- Eligible borrowers include individuals pledging gold for personal loans and jewelry manufacturers using gold/silver as raw material.
- योग्य उधारकर्ताओं में व्यक्तिगत ऋण के लिए सोना गिरवी रखने वाले लोग और

सोनाचांदी का कच्चा माल उपयोग करने वाले आभूषण निर्माता शामिल हैं।/

- Small Urban Cooperative Banks in Tier 3 & 4 cities are now allowed to provide gold/silver loans.
- अब छोटे शहरी सहकारी बैंक (टीयर)3 और 4 शहरों में चांदी के ऋण प्रदान कर /भी सोने (सकते हैं।
- Repayment period for manufacturers extended to 270 days (from 180 days).
- आभूषण निर्माताओं के लिए ऋण की पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाकर 270 दिन की गई है (पहले)180 दिन।(

New Loan-to-Value (LTV) rules effective April 1, 2026:

- Up to ₹2 lakh → 85%
- ₹2.5–5 lakh → 80%
- Above ₹5 lakh → 75%
- नए LTV नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे : ₹2 लाख तक 85%, ₹2.5–5 लाख 80%, ₹5 लाख से अधिक 75%।

- Borrowers must repay principal and interest within 12 months (bullet repayment). Earlier, only interest payment & loan renewal was allowed.
- अब उधारकर्ता को मूलधन और ब्याज 12 महीने के भीतर चुकाना होगा। पहले केवल ब्याज भुगतान और ऋण नवीनीकरण की अनुमति थी।
- Lenders must return pledged gold within 7 working days after full repayment; penalty ₹5,000/day for delay.
- ऋणदाता को ऋण चुकाने के बाद 7 कार्यदिवस में गिरवी रखे सोने को वापस करना होगा; विलंब पर ₹5,000 प्रति दिन का जुर्माना।
- Loan agreements must be transparent, specifying gold valuation, repayment schedule, auction rules, and return timelines.
- ऋण समझौते पारदर्शी होने चाहिए, जिसमें सोने का मूल्यांकन, पुनर्भुगतान समय, नीलामी नियम और वापसी समय शामिल हों।
- Gold valuation for loans will be the lower of average price over last 30 days or previous day's rate.
- ऋण के लिए सोने का मूल्य निर्धारण पिछले 30 दिनों के औसत मूल्य या पिछले दिन की दर में से कम मूल्य के अनुसार होगा।
- Before auctioning pledged gold, lenders must give proper notice; reserve price set at 90% of market value, can be reduced to 85% if two auctions fail; surplus returned within 7 days.
- गिरवी सोने की नीलामी से पहले ऋणदाता को उचित सूचना देनी होगी; आरक्षित मूल्य बाजार मूल्य का 90% तय होगा, यदि दो नीलामी विफल हों तो इसे 85% तक घटाया जा सकता है; नीलामी से बची राशि 7 दिन में वापस करनी होगी।

- The rules apply to lending institutions from October 1, 2025, and to borrowers from April 1, 2026.
- ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से ऋण देने वाले संस्थानों पर और 1 अप्रैल 2026 से उधारकर्ताओं पर लागू होंगे।

Ques: As per the latest IMF World Economic Outlook, what is India's projected GDP growth rate for FY 2025–26?

IMF की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, FY 2025–26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है?

- A. 6.2%
- B. 6.4%
- C. 6.6%
- D. 6.8%
- E. 6.9%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The International Monetary Fund (IMF) has raised India's GDP growth forecast for FY 2025–26 (FY26) to 6.6%, up by 20 basis points, citing strong performance in the April–June 2025 quarter.
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की FY26 की वृद्धि दर का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो अप्रैल–जून 2025 तिमाही के मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है।
- For FY 2026–27, the IMF revised India's growth projection downward to 6.2% due to increased tariffs.
- हालांकि, बढ़े हुए टैरिफ के प्रभाव के कारण, FY27 का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया गया है।
- IMF's FY26 estimate (6.6%) is higher than S&P (6.5%) and ADB (6.5%), but lower than Fitch (6.9%), RBI (6.8%), and OECD (6.7%).
- IMF का FY26 का नवीनतम अनुमान S&P (6.5%) और ADB (6.5%) से अधिक, लेकिन Fitch (6.9%), RBI (6.8%) और OECD (6.7%) से कम है।
- Strong domestic growth in Q1 (April–June) has helped offset the impact of US tariffs and global uncertainty.
- अप्रैल–जून तिमाही में मजबूत घरेलू वृद्धि ने अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता के

प्रभाव को संतुलित किया है।

- The World Bank has also revised India's FY26 growth forecast to 6.5%, citing better agricultural output and rural wage growth.
- विश्व बैंक ने भी हाल ही में भारत की FY26 वृद्धि दर 6.5% तक संशोधित की है, बेहतर कृषि उत्पादन और ग्रामीण मजदूरी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए।

Ques: What is the name of the scheme launched by UIDAI to foster innovation and collaboration in the digital identity domain?

डिजिटल पहचान क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च की गई योजना का नाम क्या है?

- A. DigiTech India / डिजिटिक इंडिया
- B. Innovation with Aadhaar (IWA) / नवाचार विद आधार
- C. Digital Identity Innovation Program / डिजिटल आइडेंटिटी इनोवेशन प्रोग्राम
- D. Aadhaar Innovation Hub / आधार इनोवेशन हब
- E. Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar (SITAA) / आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has launched the Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar (SITAA) to foster innovation and collaboration in the digital identity domain.
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डिजिटल पहचान क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना (SITAA) लॉन्च की है।
- The initiative aims to strengthen India's ID Tech ecosystem by enabling startups, academia, and industry to work closely with UIDAI. SITAA seeks to drive innovation, promote indigenization, and co-develop advanced and future-ready identity technologies.
- यह पहल स्टार्टअप्स, अकादमिक संस्थानों और उद्योग को UIDAI के साथ मिलकर काम करने के अवसर प्रदान करके भारत के ID Tech इकोसिस्टम को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। SITAA नवाचार को बढ़ावा देने, स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने और उन्नत और

भविष्यविकास करने का प्रयास करती है।-तैयार पहचान तकनीकों का सह-

- The SITAA scheme emphasizes India's commitment to building a secure, inclusive, and self-reliant digital identity ecosystem, creating new opportunities for innovators and researchers, and reinforcing trust in digital services.

- SITAA योजना भारत की एक सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल पहचान इकोसिस्टम बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, नवप्रवर्तकों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर पैदा करती है और डिजिटल सेवाओं में विश्वास को मजबूत करती है।

- MeitY Startup Hub and NASSCOM have signed MoUs with UIDAI and will act as strategic partners for SITAA, providing technical mentoring, incubation, industry connections, global outreach, and entrepreneurial support.

- MeitY स्टार्टअप हब और NASSCOM ने UIDAI के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं और SITAA उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक भागीदार के रूप में काम करेंगे, तकनीकी मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन, उद्योग संबंध, वैश्विक पहुँच और उद्यमिता समर्थन प्रदान करेंगे।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director & CEO of Suryoday Small Finance Bank, with tenure extended until January 22, 2029?

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिनकी अवधि 22 जनवरी, 2029 तक बढ़ा दी गई है?

- A. Umesh Revankar / उमेश रेवनकर
- B. Baskar Babu Ramachandran / बास्कर बाबू रामचंद्रन
- C. Vishal Kapoor / विशाल कपूर
- D. Ramesh Iyer / रमेश अय्यर
- E. Arvind Sharma / अरविंद शर्मा

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Baskar Babu Ramachandran has been appointed as Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) of Suryoday Small Finance Bank, with his tenure extended for an additional three years from January 23, 2026, to January 22, 2029.

- बास्कर बाबू रामचंद्रन को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनकी अवधि 23

जनवरी, 2026 से 22 जनवरी, 2029 तक अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है।

- He has been serving as MD & CEO since January 23, 2017.
- वे 23 जनवरी, 2017 से MD & CEO के रूप में कार्यरत हैं।

About Suryoday Small Finance Bank:

- Established : 2017
- HQ : Navi Mumbai
- Tagline : "A bank of smiles"

Ques: Which company has launched India's first business-specific e-RUPI (Digital e-Rupee) voucher issuance platform?

किस कंपनी ने भारत का पहला व्यवसायवाउचर जारी (रुपया-डिजिटल ई) रूपी-विशिष्ट ई-करने का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?

- A. CotoPay (Cotodel Technologies Pvt. Ltd.) / कोटोपे (.लि .टेक्नोलॉजीज प्रा कोटोडेल)
- B. PhonePe / फोनपे
- C. Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक
- D. Razorpay / रेज़रपे
- E. BharatPe / भारतपे

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• CotoPay, a brand of Cotodel Technologies Private Limited, has launched the first business-specific e-RUPI (Digital e-Rupee) voucher issuance platform to help businesses manage their expenses using the existing Unified Payments Interface (UPI) ecosystem.

• कोटोपे, जो कोटोडेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है, ने व्यवसायों को अपने खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए मौजूदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इकोसिस्टम का उपयोग करते हुए पहला व्यवसाय (रुपया-डिजिटल ई) रूपी-विशिष्ट ई-वाउचर जारी करने वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

• Businesses can instantly issue UPI vouchers, which employees can redeem at over 65 million UPI-enabled merchants across India.

- व्यवसाय तुरंत UPI वाउचर जारी कर सकते हैं, जिन्हें कर्मचारी पूरे भारत में 6.5 करोड़ से अधिक UPI-सक्षम व्यापारियों पर रिडीम कर सकते हैं।
- Vouchers can be restricted to specific categories or merchants, ensuring appropriate spending of funds.
- वाउचर को विशिष्ट श्रेणियों या व्यापारियों तक सीमित किया जा सकता है, जिससे धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित होता है।
- Employees can use existing UPI apps like BHIM, Google Pay, and bob इ Pay without the need for any new application.
- कर्मचारी BHIM, Google Pay और bob इ Pay जैसे मौजूदा UPI ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं, किसी नए ऐप की आवश्यकता नहीं होती।
- The platform eliminates the need for individual KYC, making onboarding quick and hassle-free.
- यह प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत KYC की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तेज़ और सरल हो जाती है।

Ques: Which company has partnered with PayU Finance to offer credit solutions to restaurant partners?

किस कंपनी ने अपने रेस्तरां साझेदारों को क्रेडिट समाधान प्रदान करने के लिए PayU Finance के साथ साझेदारी की है?

- A. Swiggy / स्विगी
- B. Zomato / जोमैटो
- C. Dunzo / डन्ज़ो
- D. BigBasket / बिगबास्केट
- E. FoodPanda / फूडपांडा

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Swiggy has partnered with PayU Finance, the NBFC arm of PayU, to offer credit solutions to its restaurant partners starting from the next financial year.
- स्विगी ने अगले वित्तीय वर्ष से अपने रेस्तरां साझेदारों को क्रेडिट समाधान प्रदान करने के लिए PayU के NBFC शाखा PayU Finance के साथ साझेदारी की है।
- The partnership aims for annualised credit disbursement of ₹300 crore in the

next fiscal year and ₹1,000 crore over three years.

- इस साझेदारी का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपये और तीन वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का वार्षिक क्रेडिट वितरण करना है।
- PayU Finance will provide customised unsecured loans of up to ₹25 lakh with flexible repayment through an Equated Weekly Instalment (EWI).
- PayU Finance 25 लाख रुपये तक के अनसिक्योर्ड लोन प्रदान करेगा, जिसे समान साप्ताहिक किस्तों (EWI) के माध्यम से लचीले तरीके से चुकाया जा सकेगा।
- The loans will carry an interest rate starting at 18% per annum and have zero foreclosure penalties.
- इन लोन पर वार्षिक 18% से शुरू होने वाली ब्याज दर होगी और किसी भी समय पूरी राशि चुका देने पर कोई फोरक्लोज़र शुल्क नहीं लगेगा।

About PayU :

- Established : 2002
- HQ : Amsterdam, Netherlands
- CEO : Anirban Mukherjee

Ques: What is the current cap on deposit insurance premium per ₹100 of deposits as per RBI policy?

आरबीआई नीति के अनुसार प्रति ₹100 जमा पर जमा बीमा प्रीमियम की वर्तमान सीमा क्या है?

- A. 10 paise
- B. 12 paise
- C. 15 paise
- D. 20 paise
- E. 25 paise

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) may retain the current cap of 12 paise per ₹100 on deposit insurance premiums under the new Risk-Based Premium

(RBP) model.

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल-RBP) के तहत ₹100 पर 12 पैसे की मौजूदा सीमा को बनाए रखने का संकेत दिया है।
- Currently, all banks pay this uniform premium to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) to insure customer deposits.
- वर्तमान में सभी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) को यह प्रीमियम देते हैं, ताकि जमाकर्ताओं की जमा राशि बीमित रहे।
- Under the RBP framework, well-managed banks may pay lower premiums, while cooperative and weaker banks will continue paying at or below the 12 paise rate.
- RBP ढांचे के तहत अच्छे प्रबंधन वाले बैंक कम प्रीमियम देंगे, जबकि सहकारी और कमजोर बैंक 12 पैसे की सीमा तक भुगतान जारी रखेंगे।

Ques: What is the name of India's first UPI platform exclusively for women, launched by Lxme?

भारत का पहला महिलाओं के लिए विशेष UPI प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है, जिसे Lxme ने शुरू किया?

- A) Lxmepay / Lxmepay
- B) ShePay / शीपे
- C) WomenPay / वुमनपे
- D) FemmePay / फेमपे
- E) LadyUPI / लेडी यूपीआई

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Lxmepay is India's first UPI platform exclusively designed for women, launched by Lxme, a leading financial platform for women.
- Lxmepay भारत का पहला महिलाओं के लिए विशेष UPI प्लेटफॉर्म है, जिसे महिलाओं के लिए अग्रणी वित्तीय प्लेटफॉर्म Lxme ने लॉन्च किया है।
- The platform offers features like expense tracking, bill payments, and deals on women-centric brands, providing a seamless and intuitive interface.
- इस प्लेटफॉर्म में खर्च ट्रैकिंग, बिल भुगतान और महिलाओं के ब्रांडों पर डील जैसी

सुविधाएँ शामिल हैं, जो उपयोग में सहज और सहज इंटरफेस प्रदान करती हैं।

**Ques: Zepto recently raised \$450 million funding at what valuation?
ज़ेप्टो ने हाल ही में 450 मिलियन डॉलर की फंडिंग किस मूल्यांकन पर जुटाई है?**

- A) \$3 billion
- B) \$5 billion
- C) \$6 billion
- D) \$7 billion
- E) \$8 billion

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Zepto, a leading quick commerce platform, has raised \$450 million in its latest funding round led by CalPERS, valuing the company at \$7 billion.
 - ज़ेप्टो, एक प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ने अपनी नवीनतम फंडिंग राउंड में CalPERS के नेतृत्व में 450 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 7 अरब डॉलर हो गया।
 - The funding will support expansion of Zepto's "dark store" network across India and plans for a future IPO.
 - यह फंडिंग ज़ेप्टो के "डार्क स्टोर" नेटवर्क के भारतभर विस्तार और भविष्य में IPO लाने के प्रयासों में मदद करेगी।
 - Zepto's valuation increased from \$5 billion in 2023 to \$7 billion in 2025, reflecting rapid growth in India's quick commerce sector.
 - ज़ेप्टो का मूल्यांकन 2023 में 5 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 7 अरब डॉलर हो गया, जो भारत के क्विक कॉमर्स सेक्टर में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है।
-

Ques: The Government of India plans to launch a new credit guarantee scheme for MSME exporters for loans up to what amount?

भारत सरकार MSME निर्यातकों के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना कितनी राशि तक के ऋणों के लिए लाने की योजना बना रही है?

A. ₹50 crore

- B. ₹75 crore
- C. ₹100 crore
- D. ₹125 crore
- E. ₹150 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Centre plans to launch a credit guarantee cover for MSME exporters for loans up to ₹100 crore, similar to the Mutual Credit Guarantee Scheme (MCGS) introduced earlier in 2025.
 - केंद्र सरकार MSME निर्यातकों के लिए ₹100 करोड़ तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी कवर लाने की योजना बना रही है, जो पहले शुरू की गई MCGS योजना के समान होगी।
 - The initiative aims to help exporters mitigate the impact of high US tariffs, ensure easier credit access, and strengthen India's export competitiveness.
 - इस योजना का उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना, निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता आसान बनाना, और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है।
 - Under the proposed scheme, exporters can get collateral-free loans through banks and financial institutions, with reduced lending risks.
 - प्रस्तावित योजना के तहत निर्यातक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बिना गिरवी के ऋण प्राप्त कर सकेंगे और ऋण देने के जोखिम को कम किया जाएगा।
-

Ques: Which finance company is set to be classified as an Upper-Layer NBFC (NBFC-UL) under the RBI's scale-based regulation framework?

RBI के स्केल आधारित विनियमन ढांचे के तहत किस वित्त कंपनी को-Upper-Layer NBFC (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला है?

- A) Bajaj Finance / बजाज फाइनेंस
- B) Axis Finance / एक्सिस फाइनेंस
- C) Mahindra Finance / महिंद्रा फाइनेंस
- D) HDFC Ltd. / HDFC लिमिटेड
- E) ICICI Finance / ICICI फाइनेंस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Axis Finance is set to be classified as an Upper-Layer NBFC (NBFC-UL) under the Reserve Bank of India's scale-based regulation (SBR) framework.
- RBI के स्केल) आधारित विनियमन-SBR) ढांचे के तहत Axis Finance को Upper-Layer NBFC (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- Once classified as NBFC-UL, the company must list its shares on a recognized stock exchange within three years.
- NBFC-UL के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, कंपनी को तीन साल के भीतर अपने शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना अनिवार्य होगा।
- As of October 2025, there are 16 NBFCs in the Upper-Layer category under RBI's SBR framework.
- अक्टूबर 2025 तक, RBI के SBR ढांचे के तहत Upper-Layer श्रेणी में कुल 16 NBFCs हैं।

Different layers of NBFC :

- Base Layer : NBFC-ND with assets less than Rs 1000 cr
आधार परत: 1000 करोड़ रुपये से कम की संपत्ति वाली एनबीएफसी-एनडी
- Middle Layer : NBFC-D and NBFC-ND greater than Rs 1000 cr
मध्य परत: 1000 करोड़ रुपये से अधिक की एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी
- Upper Layer : NBFCs monitored by RBI based on a set of parameters and scoring methodology. Currently 16 NBFCs are part of this list
ऊपरी परत: कुछ मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर आरबीआई द्वारा निगरानी की जाने वाली एनबीएफसी। वर्तमान में 16 एनबीएफसी इस सूची का हिस्सा हैं।
- Top Layer : NBFCs which entail systemic risk. Ideally to remain empty
शीर्ष परत: वे एनबीएफसी जिनमें प्रणालीगत जोखिम होता है। आदर्श रूप से खाली रहना चाहिए।

Ques: State Bank of India (SBI) is likely to raise how much amount via 10-year Tier II Bonds?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 10-वर्षीय टियर-II बॉन्ड्स के माध्यम से कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है?

- A) ₹5,000 crore
- B) ₹6,000 crore
- C) ₹7,500 crore
- D) ₹10,000 crore
- E) ₹12,000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI is set to raise ₹7,500 crore through the issuance of 10-year Tier II bonds, marking its first such issue this financial year.
- SBI इस वर्ष 10-वर्षीय टियर-II बॉन्ड्स के माध्यम से ₹7,500 करोड़ जुटाने जा रहा है, जो इसका पहला ऐसा इश्यू होगा।
- The bonds are expected to carry a coupon rate above 7%, and the issue comprises a base size of ₹5,000 crore with a green shoe option of ₹2,500 crore.
- इन बॉन्ड्स का कूपन रेट 7% से अधिक होगा और इसमें ₹5,000 करोड़ का बेस साइज तथा ₹2,500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है।
- The funds raised will help SBI strengthen its capital adequacy ratio and support future lending growth.
- जुटाई गई राशि से SBI को कैपिटल एडिक्वैसी रेशियो मजबूत करने और भविष्य के ऋण विस्तार में सहायता मिलेगी।

Ques : Getepay has partnered with which bank for the deployment of its next-generation payment switch 'Vega'?

गेटेपे ने अपने नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच-'वेगा' की तैनाती के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

- A) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) ESAF Small Finance Bank / ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक

- D) Jana Small Finance Bank / जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
E) Suryoday Small Finance Bank / सूर्यदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या :

- Getepay announced its partnership with ESAF Small Finance Bank for the deployment of its next-generation payment switch named 'Vega'.
 - गेटेपे ने अपने नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच-‘वेगा’ की तैनाती के लिए ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की।
 - Vega is a future-ready, high-performance payment switch designed to enable banks and financial institutions to process real-time transactions efficiently and ensure automated reconciliation.
 - वेगा एक भविष्यउन्मुख-, उच्च प्रदर्शन वाला पेमेंट स्विच है, जिसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रियलटाइम लेनदेन प्रोसेसिंग और स्वचालित मिलान की सुविधा देने के लिए - तैयार किया गया है।
 - This partnership aims to strengthen digital payments infrastructure and enhance transaction reliability across the banking ecosystem.
 - यह साझेदारी डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने और बैंकिंग प्रणाली में लेनदेन की विश्वसनीयता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
-

Ques: LIC recently increased its stake in Dr. Reddy's Laboratories to what percentage as of October 15, 2025?

एलआईसी ने 15 अक्टूबर 2025 तक डॉरेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़ में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई है?

- A. 8.21%
B. 9.50%
C. 10.26%
D. 11.00%
E. 12.10%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Life Insurance Corporation of India (LIC) increased its shareholding in Dr. Reddy's Laboratories from 8.21% in June 2025 to 10.26% as of October 15, 2025 by purchasing 1.71 crore shares through open market transactions.
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने जून 2025 में 8.21% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 तक 10.26% कर दी, जो 1.71 करोड़ शेयरों की खुले बाजार से खरीद के माध्यम से संभव हुआ।
- This represents an additional 2% equity increase, reinforcing LIC's position as one of the largest institutional investors in India's pharmaceutical sector.
- यह 2% की अतिरिक्त हिस्सेदारी वृद्धि LIC की भारत के फार्मा क्षेत्र में सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक के रूप में स्थिति को मजबूत करती है।

Ques: According to RBI, which digital currency should be promoted over stablecoins for cross-border payments?

आरबीआई के अनुसार, सीमा पार भुगतान के लिए स्टेबलकॉइन के स्थान पर किस डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए?

- A. Bitcoin / बिटकॉइन
- B. Ethereum / एथीरियम
- C. CBDC (Central Bank Digital Currency) / केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)
- D. e-RUPI / ईपीरू-
- E. Libra / लाइब्रा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI Governor Sanjay Malhotra urged central banks globally to promote CBDCs instead of stablecoins during the IMF–World Bank Annual Meet in Washington, DC.
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वॉशिंगटन डी में .सी. IMF–विश्व बैंक वार्षिक बैठक में स्टेबलकॉइन के बजाय CBDC को अपनाने की सलाह दी।
- CBDCs are fiat-backed, tokenizable, and ensure the integrity and safety of monetary systems, unlike private stablecoins.

- CBDC एक वैध मुद्रा आधारित डिजिटल रूप है, जिसे टोकनाइज़ किया जा सकता है और यह वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो निजी स्टेबलकॉइन्स में संभव नहीं है।
- RBI is currently piloting Retail CBDC (e₹-R) for public use and Wholesale CBDC (e₹-W) for institutional interbank settlements.
- आरबीआई वर्तमान में रिटेल e₹ (e₹-R) आम जनता के लिए और होलसेल e₹ (e₹-W) वित्तीय संस्थानों के बीच बड़ी लेनदेन के लिए परीक्षण कर रहा है।

Ques: RBI's gold reserves recently crossed which milestone for the first time?
आरबीआई के स्वर्ण भंडार ने हाल ही में पहली बार कौनसा मील का पत्थर पार किया है-?

- A) \$50 billion
- B) \$75 billion
- C) \$90 billion
- D) \$100 billion
- E) \$120 billion

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India's gold reserves crossed the \$100 billion mark for the first time, as per RBI's latest forex data for the week ending October 10, 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के ताज़ा विदेशी मुद्रा भंडार आँकड़ों के अनुसार, भारत के स्वर्ण भंडार पहली बार \$100 बिलियन के पार पहुँचे हैं।
- RBI's gold holdings rose by \$3.595 billion to \$102.365 billion, even as total forex reserves declined to \$697.784 billion.
- आरबीआई के स्वर्ण भंडार \$3.595 बिलियन बढ़कर \$102.365 बिलियन हो गए, जबकि कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर \$697.784 बिलियन रह गया।
- The share of gold in total reserves increased to 14.7%, the highest since 1996–97, due to rising global gold prices (~65% surge in 2025).
- कुल भंडार में स्वर्ण का हिस्सा बढ़कर 14.7% हो गया, जो 1996–97 के बाद सबसे अधिक है, क्योंकि 2025 में स्वर्ण की कीमतों में लगभग 65% की वृद्धि हुई।
- Global central banks, including India, are buying gold to reduce dependence on the US dollar amid geopolitical tensions and de-dollarization trends.
- भारत सहित विश्व के केंद्रीय बैंक भूराजनीतिक तनाव और डीडॉलराइजेशन के बीच -

स्वर्ण भंडार बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए

- India remains the world's second-largest gold consumer, where gold buying is deeply rooted in culture and tradition.
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है, जहाँ स्वर्ण खरीदारी संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई है।

Ques: By how much did unclaimed money in mutual funds increase in 2024–25 compared to 2023–24?

2024–25 में म्यूचुअल फंड में बिना क्लेम की गई राशि 2023–24 की तुलना में कितनी बढ़ी?

- A) 21%
- B) 15%
- C) 10 %
- D) 25%
- E) 30%

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Unclaimed money in mutual funds rose by 21%, from ₹2,862 crore in 2023–24 to ₹3,452 crore in 2024–25, driven mainly by unclaimed dividends (up 26.5%) and redemptions (up 10.1%).
- म्यूचुअल फंड में बिना क्लेम की गई राशि 2023–24 में ₹2,862 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹3,452 करोड़ हो गई, यानी 21% की वृद्धि, जिसमें मुख्य रूप से बिना क्लेम किए गए डिविडेंड्स (26.5% वृद्धि) और रिडेम्प्शन (10.1% वृद्धिशामिल हैं)।
- To help investors track and claim these amounts, SEBI and AMFI launched the MITRA platform.
- निवेशकों को यह राशि ट्रैक और क्लेम करने में मदद करने के लिए SEBI और AMFI ने MITRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

Important figures :

महत्वपूर्ण आँकड़े:

- Unclaimed deposits (bank deposits) transferred to

Reserve Bank of India's Depositor Education & Awareness Fund : over ~ ₹ 75,000 crore (as of August 2025) from deposits

- भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में हस्तांतरित दावारहित जमाराशियाँ (बैंक जमा): जमाराशियों से लगभग ₹75,000 करोड़ से अधिक (अगस्त 2025 तक)
- Unclaimed insurance proceeds: over ~ ₹ 13,800 crore.
- दावारहित बीमा राशि: लगभग ₹13,800 करोड़ से अधिक
- Unclaimed mutual fund balances: about ~ ₹ 3,000 crore.
- दावारहित म्यूचुअल फंड शेष: लगभग ₹3,000 करोड़
- Total unclaimed financial assets (across banks & regulators) ≈ ₹ 1.84 lakh crore.
- कुल दावारहित वित्तीय संपत्तियाँ (बैंकों और नियामकों में) लगभग ₹1.84 लाख करोड़
- Unpaid dividends: more than ~ ₹ 9,000 crore
- अवैतनिक लाभांश: लगभग ₹9,000 करोड़ से अधिक

Ques: According to the amended IFSCA listing norms, what is the new maximum age limit for financial information in the offer document?

संशोधित IFSCA सूचीकरण मानदंडों के अनुसार, ऑफर दस्तावेज़ में वित्तीय जानकारी की नई अधिकतम आयु सीमा क्या है?

- A. 90 days
- B. 120 days
- C. 135 days
- D. 180 days
- E. 200 days

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Under the revised IFSCA listing norms, financial information in the offer document must not be older than 180 days, up from the previous limit of 135 days.
- संशोधित IFSCA सूचीकरण मानदंडों के अनुसार, ऑफर दस्तावेज़ में वित्तीय जानकारी 180 दिनों से पुरानी नहीं हो सकती, जो पहले 135 दिनों की सीमा थी।

- This amendment provides issuers and investors more accurate and up-to-date financial data, enhancing transparency and confidence.
- यह संशोधन जारीकर्ताओं और निवेशकों को अधिक सटीक और अद्यतन वित्तीय जानकारी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

Ques: Which bank is set to acquire a ~60% stake in RBL Bank via preferential share issuance?

कौन सा बैंक RBL बैंक में ~60% हिस्सेदारी प्राथमिक शेयर जारीकरण के माध्यम से हासिल करने जा रहा है?

- A) Emirates NBD Bank / एमिरेट्स एनबीडी बैंक
- B) ICICI Bank / ICICI बैंक
- C) HDFC Bank / HDFC बैंक
- D) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Emirates NBD Bank is acquiring approximately 60% stake in RBL Bank through preferential share issuance, valued at around USD 3 billion (~₹26,850 crore).
- एमिरेट्स एनबीडी बैंक RBL बैंक में लगभग 60% हिस्सेदारी प्राथमिक शेयर जारीकरण के माध्यम से हासिल कर रहा है, जिसका मूल्य लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर)~₹26,850 करोड़ है। (
- Following SEBI takeover regulations, ENBD will also make a mandatory open offer to acquire up to an additional ~26% of RBL Bank's share capital.
- SEBI अधिग्रहण नियमों के अनुसार, ENBD RBL बैंक की अतिरिक्त ~26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अनिवार्य ओपन ऑफ़र भी करेगा।

Ques: Which bank launched the short film “Making Cancer Care Accessible” to promote affordable cancer care during Breast Cancer Awareness Month?

ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के दौरान किफायती कैंसर देखभाल को बढ़ावा देने के लिए “मेकिंग कैंसर केयर एक्सेसेबल” शॉर्ट फिल्म किस बैंक ने लॉन्च की?

- A) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Suryoday Small Finance Bank / सूर्यदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) ESAF Small Finance Bank / ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Equitas Small Finance Bank launched the short film “Making Cancer Care Accessible” in collaboration with Sringeri Sharada Equitas Cancer & Multi-Specialty Hospital.
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने श्रींगेरी शारदा इक्विटास कैंसर एंड मल्टीस्पेशियलिटी - हॉस्पिटल के सहयोग से “मेकिंग कैंसर केयर एक्सेसेबल” शॉर्ट फिल्म लॉन्च की।
- The film, released during Breast Cancer Awareness Month (October), aims to raise awareness about making advanced cancer care accessible and affordable for underprivileged women.
- यह फिल्म ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के दौरान जारी की गई, जिसका उद्देश्य कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए कैंसर उपचार को सुलभ और किफायती बनाना है।
- The initiative, led by Equitas Healthcare Foundation, highlights the bank’s commitment to inclusive healthcare and social responsibility.
- इक्विटास हेल्थकेयर फाउंडेशन की यह पहल समावेशी स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Ques: RBL Bank recently launched the ‘Humsafar’ RuPay prepaid card in collaboration with which organization?

आरबीएल बैंक ने हाल ही में ‘हमसफर’ रुपे प्रीपेड कार्ड किस संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया है?

- A. SBI / एसबीआई

- B. RBI / आरबीआई
- C. NPCI / एनपीसीआई
- D. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E. NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBL Bank launched the 'Humsafar' RuPay prepaid card in collaboration with the National Payments Corporation of India (NPCI).
 - आरबीएल बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सहयोग से 'हमसफर' रुपये प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है।
 - The card comes with National Common Mobility Card (NCMC) enablement, allowing customers to make digital payments for travel, shopping, fuel, entertainment, and more.
 - इस कार्ड में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सुविधा है, जिससे ग्राहक यात्रा, खरीदारी, ईंधन और मनोरंजन जैसी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
 - The initiative supports the Digital India mission by promoting secure, cashless, and interoperable payment solutions.
 - यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सुरक्षित, कैशलेस और एकीकृत भुगतान समाधान को बढ़ावा देती है।
-

Ques: Which innovative feature did Bajaj Finserv AMC recently launch to link mutual fund investments with daily payments?

बजाज फिनसर्व AMC ने हाल ही में कौन सा नवीन फीचर लॉन्च किया जो म्यूचुअल फंड निवेश को दैनिक भुगतान से जोड़ता है?

- A) Invest & Spend Wallet / इन्वेस्ट एंड स्पेंड वॉलेट
- B) Pay with Mutual Fund / पे विथ म्यूचुअल फंड
- C) Instant Fund Transfer / इंस्टेंट फंड ट्रांसफर
- D) Mutual Fund Cashback / म्यूचुअल फंड कैशबैक
- E) UPI Redemption Link / यूपीआई रिडेम्पशन लिंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Bajaj Finserv AMC, in collaboration with fintech firm Curie Money, launched the 'Pay with Mutual Fund' feature, allowing investors to use their mutual fund units for UPI transactions.
- बजाज फिनसर्व AMC ने फिनटेक कंपनी Curie Money के साथ मिलकर 'पे विथ म्यूचुअल फंड' फीचर लॉन्च किया, जिससे निवेशक अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स का उपयोग UPI लेनदेन के लिए कर सकते हैं।
- Investors can scan any UPI QR code and make payments directly using mutual fund investments, blending asset growth with real-time spending.
- इस फीचर के जरिए निवेशक किसी भी UPI QR को स्कैन करके सीधे म्यूचुअल फंड निवेश का उपयोग कर भुगतान कर सकते हैं, जिससे संपत्ति वृद्धि और वास्तविक समय खर्च जुड़ जाता है।
- The facility uses the Instant Redemption mechanism, allowing redemption of up to ₹50,000 or 90% of investment, whichever is lower, instantly.
- यह सुविधा इंस्टेंट रिडेम्पशन मैकेनिज्म पर आधारित है, जो निवेशक को तुरंत ₹50,000 या उनके निवेश का 90% (जो भी कम होरिडीम करने की अनुमति देती है। (

Ques: Which bank has partnered with Hitachi Payment Services to launch "Express Banking", India's first Digital Banking Point?

"एक्सप्रेस बैंकिंग" – भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग पॉइंट लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी की है?

- A) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) IndusInd Bank / इंडसइंड बैंक
- E) Yes Bank / यस बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank, one of India's largest private sector banks, has partnered with Hitachi Payment Services to launch "Express Banking", the country's first Digital Banking Point.
- एक्सिस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर "एक्सप्रेस बैंकिंग" – देश का पहला डिजिटल बैंकिंग पॉइंट लॉन्च किया है।
- These self-service digital banking hubs will allow customers to carry out services like cash withdrawal, deposit, fund transfer, and other essential transactions.
- यह पहल अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में-24x7 डिजिटल बैंकिंग पहुंच को आसान बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- Hitachi Payment Services will manage the infrastructure, while Axis Bank will handle banking operations and customer interaction.
- यह पहल Digital India और Financial Inclusion मिशनों के अनुरूप है, जो कैशलाइट - अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान के विस्तार को प्रोत्साहित करती है।

Ques: What were India's total exports (merchandise + services) for April–September 2025 and their growth over the same period in 2024?

अप्रैल–सितंबर 2025 के लिए भारत का कुल निर्यात क्या रहा और (सेवाएँ + मर्चेडाइज) 2024 के समान अवधि के मुकाबले इसका विकास कितना हुआ?

- A) US\$ 400.00 billion / 4.00% growth
- B) US\$ 413.30 billion / 4.45% growth
- C) US\$ 420.50 billion / 5.00% growth
- D) US\$ 430.00 billion / 4.80% growth
- E) US\$ 450.00 billion / 5.50% growth

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- India's total exports for April–September 2025 are estimated at US\$ 413.30 billion, showing a 4.45% growth over the same period in 2024.
- अप्रैल–सितंबर 2025 के लिए भारत का कुल निर्यात लगभग US\$ 413.30 बिलियन है, जो 2024 की समान अवधि की तुलना में 4.45% अधिक है।

- Merchandise exports rose by 3.02% to US\$ 220.12 billion, while non-petroleum exports increased by 7.04%, indicating growth beyond traditional sectors.
- मर्चेडाइज निर्यात 3.02% बढ़कर US\$ 220.12 बिलियन हुआ, जबकि गैरपेट्रोलियम - निर्यात 7.04% बढ़ा, जो पारंपरिक क्षेत्रों से परे व्यापक विकास को दर्शाता है।
- Total exports in September 2025 stood at US\$ 67.20 billion against imports of US\$ 83.82 billion, resulting in a monthly trade deficit of US\$ 16.61 billion.
- सितंबर 2025 में कुल निर्यात US\$ 67.20 बिलियन और आयात US\$ 83.82 बिलियन रहे, जिससे मासिक व्यापार घाटा US\$ 16.61 बिलियन हुआ।
- Services exports during April–September 2025 were estimated at US\$ 193.18 billion.
- अप्रैल–सितंबर 2025 में सेवा क्षेत्र का निर्यात लगभग US\$ 193.18 बिलियन रहा।
- Top export destinations showing strong growth: UAE, USA, China, Spain, and Bangladesh.
- शीर्ष निर्यात गंतव्य जो मजबूत वृद्धि दिखा रहे हैं : संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, चीन, स्पेन और बांग्लादेश।
- Top import sources with sharp increases: Switzerland, UAE, China, Saudi Arabia, and Nigeria.
- आयात में तेज वृद्धि दिखाने वाले प्रमुख स्रोत : स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सऊदी अरब और नाइजीरिया।

Ques: LIC Bima Lakshmi (881) Plan has been launched exclusively for which group?

LIC बीमा लक्ष्मी)881) योजना विशेष रूप से किस वर्ग के लिए शुरू की गई है?

- A) Senior Citizens / वरिष्ठ नागरिक
- B) Farmers / किसान
- C) Females / महिलाएँ
- D) Government Employees / सरकारी कर्मचारी
- E) Students / विद्यार्थी

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- LIC launched Jan Suraksha (880) for lower income groups and Bima Lakshmi (881) exclusively for females, under the new next-gen GST regime.
- LIC ने जन सुरक्षा (880) योजना कम आय वर्ग के लोगों के लिए और बीमा लक्ष्मी (881) योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए नई नेक्स्ट जेनरेशन GST प्रणाली के तहत लॉन्च की है।

LIC Jan Suraksha Plan (880) :

- A life micro insurance plan designed for lower income group people.
- यह कम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई एक माइक्रो जीवन बीमा योजना है।
- Entry age: Minimum 18 years and Maximum 55 years.
- प्रवेश आयु न्यूनतम :18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष।
- Policy term: 12 to 20 years; Premium paying term: Policy term minus 5 years.
- पॉलिसी अवधि :12 से 20 वर्ष; प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि से :5 वर्ष कम।
- Sum Assured: Minimum ₹1 lakh and Maximum ₹2 lakh (in multiples of ₹5,000).
- बीमित राशि न्यूनतम :₹1 लाख और अधिकतम ₹2 लाख)₹5,000 के गुणकों में।(

LIC Bima Lakshmi Plan (881) :

- A non-linked life insurance plan exclusively for females offering life cover and periodic fixed money back benefits.
- यह महिलाओं के लिए विशेष गैरलिंक्ड बीमा योजना है, जो जीवन सुरक्षा और नियत अंतराल पर धनवापसी का लाभ प्रदान करती है।
- Entry age: Minimum 18 years and Maximum 50 years.
- प्रवेश आयु न्यूनतम :18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष।
- Sum Assured: Minimum ₹2 lakh, no maximum limit (subject to underwriting policy).
- बीमित राशि न्यूनतम :₹2 लाख, अधिकतम सीमा नहीं (अंडरराइटिंग)नीति के अनुसार।(
- Money Back: Fixed returns after 2–4 years or after premium payment ceases.
- मनी बैक :2–4 वर्षों के बाद या प्रीमियम भुगतान समाप्त होने के बाद निश्चित धनवापसी।

Ques: Which two multilateral development banks recently signed a US \$3 billion Sovereign Exposure Exchange Agreement (EEA) to enhance lending capacity for developing countries?

कौन से दो बहुपक्षीय विकास बैंकों ने हाल ही में विकासशील देशों के लिए ऋण देने की क्षमता बढ़ाने हेतु 3 अरब अमेरिकी डॉलर का सॉवरेन एक्सपोज़र एक्सचेंज एग्रीमेंट (EEA) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) ADB and IMF / एडीबी और आईएमएफ
- B) ADB and World Bank / एडीबी और विश्व बैंक
- C) World Bank and AIIB / विश्व बैंक और एआईआईबी
- D) ADB and NDB / एडीबी और एनडीबी
- E) AIIB and IMF / एआईआईबी और आईएमएफ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) and the World Bank have signed a US \$3 billion Sovereign Exposure Exchange Agreement (EEA) to expand ADB's lending capacity for developing-member countries.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक ने विकासशील सदस्य देशों के लिए एडीबी की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने हेतु 3 अरब अमेरिकी डॉलर का सॉवरेन एक्सपोज़र एक्सचेंज एग्रीमेंट (EEA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- This marks the first such EEA between ADB and the World Bank, and the sixth EEA signed by ADB since 2020.
- यह एडीबी और विश्व बैंक के बीच पहला EEA है, और 2020 के बाद से एडीबी द्वारा हस्ताक्षरित छठा EEA है।
- The cumulative amount of exposure exchange deals by ADB with other multilateral development banks now stands at approximately US \$9 billion.
- अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ एडीबी के एक्सपोज़र एक्सचेंज समझौतों की कुल राशि अब लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है।
- Under an EEA, two multilateral development banks exchange credit risk associated with sovereign loans or exposures.
- EEA के तहत, दो बहुपक्षीय विकास बैंक संप्रभु ऋण या एक्सपोज़र से संबंधित क्रेडिट जोखिम का आदानप्रदान करते हैं।-

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda

About World Bank :

- Established : 1944
- HQ : Washington DC
- Members : 189
- World Bank Group : 5 (IBRD, IDA, IFC, MIGA and ICSID)
- President : Ajay Banga
- MD & CFO : Anshula Kant
- Chief Economist : Indermit Gill

Ques: Which banks provided the \$215 million term loan to AI Fleet Services IFSC for financing six Boeing 777-300 ER aircraft for Air India?

कौन से बैंकों ने एयर इंडिया के लिए छह बोइंग 777-300 ER विमानों के वित्तपोषण हेतु AI Fleet Services IFSC को \$215 मिलियन का टर्म लोन दिया?

- A) Standard Chartered and Bank of India / स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया
- B) State Bank of India and Axis Bank / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक
- C) HDFC Bank and ICICI Bank / एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक
- D) Citibank and Kotak Mahindra Bank / सिटीबैंक और कोटक महिंद्रा बैंक
- E) Punjab National Bank and IDBI Bank / पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- A \$215 million term loan was provided to AI Fleet Services IFSC (AIFS), the leasing subsidiary of Tata Group-owned Air India, based in GIFT City, for financing six Boeing 777-300 ER aircraft to be leased to Air India.

- \$215 मिलियन का टर्म लोन AI Fleet Services IFSC (Tata Group-owned Air India की लीजिंग सहायक कंपनी को (GIFT सिटी में स्थित, छह बोइंग 777-300 ER विमानों के वित्तपोषण के लिए दिया गया।
- The loan was jointly given by Standard Chartered and Bank of India (BoI), with Standard Chartered acting as the lead structuring bank.
- यह लोन स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड लीड स्ट्रक्चरिंग बैंक के रूप में कार्य कर रहा था।
- Both banks also served as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners for the transaction.
- दोनों बैंकों ने इस लेनदेन के लिए मंडेटेड लीड अरेंजर और बुकरनर के रूप में भी काम किया।
- The financing will enable Air India to expand its fleet and support its operational and leasing plans.
- यह वित्तपोषण एयर इंडिया को अपने विमान बेड़े का विस्तार करने और परिचालन एवं लीजिंग योजनाओं का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा।

About Standard Chartered Bank :

- Established : 1969
- HQ : Mumbai
- Group CEO : Bill Winters
- Tagline : Here for good

Ques: ICICI Bank has partnered with which institution to construct a new cancer care centre in Maharashtra?

महाराष्ट्र में नया कैंसर केयर सेंटर बनाने के लिए ICICI बैंक ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है?

- A) AIIMS Delhi / एम्स दिल्ली
- B) Tata Memorial Centre (TMC) / टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी)
- C) Apollo Hospitals / अपोलो हॉस्पिटल्स
- D) Fortis Healthcare / फोर्टिस हेल्थकेयर
- E) Medanta Hospital / मेदांता हॉस्पिटल

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Bank has partnered with the Tata Memorial Centre (TMC) to build a new cancer care building named 'ICICI Foundation Block for Radiation Oncology' at ACTREC, Navi Mumbai, Maharashtra.
- ICICI बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) के साथ मिलकर नवी मुंबई, महाराष्ट्र स्थित ACTREC परिसर में 'ICICI फाउंडेशन ब्लॉक फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी' नामक नए कैंसर केयर भवन के निर्माण की शुरुआत की है।
- The ₹625 crore project is funded through ICICI Bank's CSR contribution and will include advanced radiation therapy centres equipped with cutting-edge technologies.
- यह ₹625 करोड़ की परियोजना ICICI बैंक के CSR योगदान से वित्तपोषित है और इसमें अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी सुविधाएं शामिल होंगी।
- The initiative is part of ICICI Bank's ₹1,800 crore commitment to TMC for constructing three cancer care buildings — in Navi Mumbai (Maharashtra), Mullanpur (Punjab), and Visakhapatnam (Andhra Pradesh).
- यह पहल ICICI बैंक की ₹1,800 करोड़ की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत तीन अत्याधुनिक कैंसर केयर भवन नवी मुंबई, मुल्लनपुर और विशाखापट्टनम में बनाए जा रहे हैं।
- The new facility is expected to be completed by 2027.
- इस नई सुविधा को 2027 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

Ques: As per the Notaries (Amendment) Rules, 2025, what is the new maximum number of Notaries allowed to be appointed in Gujarat?

नोटरी नियम (संशोधन), 2025 के अनुसार गुजरात में नियुक्त किए जाने वाले नोटरी की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है?

- A) 2,900
- B) 4,000
- C) 5,000
- D) 6,000
- E) 7,000

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Legal Affairs notified the Notaries (Amendment) Rules, 2025 through G.S.R. 763(E) published in the Extraordinary Gazette of India, exercising powers under Section 15 of the Notaries Act, 1952.
- विधि कार्य विभाग ने नोटरी नियम (संशोधन), 2025 को भारत के राजपत्र)G.S.R. 763(E)) में अधिसूचित किया, जो नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया।
- The amendment revised the maximum number of Notaries to be appointed by certain State Governments under the Notaries Rules, 1956.
- इस संशोधन के तहत कुछ राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले नोटरी की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है।

Updated limits under Notaries (Amendment) Rules, 2025:

Gujarat: 2,900 → 6,000

Tamil Nadu: 2,500 → 3,500

Rajasthan: 2,000 → 3,000

Nagaland: 200 → 400

- A Notary is a public official authorized to verify, authenticate, and certify legal documents, witness signatures, and administer oaths.
- नोटरी एक सार्वजनिक अधिकारी होता है जो कानूनी दस्तावेजों को सत्यापित, प्रमाणित और हस्ताक्षरित करने का कार्य करता है तथा शपथ और घोषणाएं दिलाने के लिए अधिकृत होता है।

Ques: According to RBI data, by how much did India's outward remittances for education fall in August 2025 (year-on-year)?

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, अगस्त 2025 में शिक्षा हेतु विदेश भेजी गई राशि में वर्ष-वर्ष कितनी गिरावट आई-दर?

- A) 12%
- B) 19%
- C) 23.8%
- D) 28%
- E) 17.7%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As per RBI's August 2025 data, India's outward remittances for education abroad fell 23.8% year-on-year to \$0.32 billion, down from \$0.42 billion in August 2024.
 - आरबीआई के अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार, विदेश में शिक्षा हेतु भेजी गई राशि वर्षवर्ष-दर- 23.8% घटकर \$0.32 बिलियन रह गई, जो अगस्त 2024 में \$0.42 बिलियन थी।
 - This is the lowest monthly figure since August 2017.
 - यह अगस्त 2017 के बाद सबसे कम मासिक प्रेषण राशि है।
 - Travel-related remittances also declined by 19%, due to tighter immigration and visa norms in countries like the US, UK, and Europe.
 - यात्रा संबंधी प्रेषण में भी-19% की गिरावट आई, जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देशों में कड़े आत्रजन और वीजा नियमों के कारण हुई।
-

Ques: What proposal has the SEBI working group headed by R.S. Gandhi recently made regarding clearing corporations?

हाल ही में R.S. गांधी के नेतृत्व वाले SEBI कार्य समूह ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संबंध में क्या प्रस्ताव रखा है?

- A) Decrease transaction charges / लेनदेन शुल्क घटाना-
- B) Merge clearing corporations / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स का विलय करना
- C) Abolish transaction charges / लेनदेन शुल्क समाप्त करना-
- D) Keep broker charges higher / ब्रोकर शुल्क बढ़ाना
- E) Increase transaction charges / लेनदेन शुल्क बढ़ाना-

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- A SEBI-constituted working group, headed by Rama Subramaniam (R.S) Gandhi, former Deputy Governor of RBI, has proposed increasing transaction charges for clearing corporations such as NSE Clearing Limited.

- SEBI द्वारा गठित कार्य समूह, जिनका नेतृत्व पूर्व आरबीआई उप-गवर्नर रामा सुब्रमण्यम (R.S) गांधी कर रहे हैं, ने NSE Clearing Limited जैसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों के लिए लेनदेन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
- SEBI clarified that broker charges will remain unchanged.
- SEBI ने स्पष्ट किया कि ब्रोकर्स के शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा।
- The move aims to strengthen the financial independence and balance sheets of these clearing corporations.
- इस कदम का उद्देश्य इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों की वित्तीय स्वतंत्रता और बैलेंस शीट को मजबूत करना है।
- Currently, NSE Clearing receives about 5%–6% of the fees collected by NSE from members, and the revision is expected to raise their share to around 25% or slightly higher.
- वर्तमान में, NSE Clearing को NSE द्वारा सदस्यों से वसूले जाने वाले शुल्क का लगभग 5%–6% मिलता है, और प्रस्तावित संशोधन से यह हिस्सा लगभग 25% या उससे थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है।

Ques: What recent change has the Reserve Bank of India (RBI) made regarding the ₹10,000 crore ceiling on bank loans to a single corporate entity?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को दिए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सीमा के संबंध में क्या बदलाव किया है?

- A) Ceiling reduced to ₹5,000 crore / सीमा 5,000 करोड़ रुपये कर दी गई
- B) Ceiling removed entirely / सीमा पूरी तरह हटा दी गई
- C) Ceiling increased to ₹15,000 crore / सीमा 15,000 करोड़ रुपये कर दी गई
- D) No change to existing ceiling / मौजूदा सीमा में कोई बदलाव नहीं
- E) Ceiling replaced by exposure ratio / सीमा को एक्सपोजर रेशियो से बदल दिया गया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has removed the ₹10,000 crore ceiling on bank loans to a single corporate entity, effective from 1 April 2026, giving banks greater lending

flexibility.

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को दिए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सीमा हटा दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जिससे बैंकों को अधिक ऋण देने की स्वतंत्रता मिलेगी।
- Earlier guidelines (2016) limited concentration risk and encouraged corporates to diversify funding, requiring higher provisions and risk weights if the cap was breached.
- पहले 2016 के दिशानिर्देशों ने सांद्रण जोखिम को सीमित किया और कॉर्पोरेट्स को वित्त पोषण विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया, और यदि सीमा पार होती तो अधिक प्रावधान और जोखिम भार लागू करना पड़ता।
- Going forward, the Large Exposures Framework (LEF) will manage concentration risk at the bank level, while systemic risk will be monitored through macroprudential tools.
- अब Large Exposures Framework (LEF) बैंक स्तर पर सांद्रण जोखिम को नियंत्रित करेगा, जबकि प्रणालीगत जोखिम को मैक्रोप्रूडेंशियल टूल्स से मॉनिटर किया जाएगा।
- Under LEF, total exposure to a single borrower cannot exceed 20% of Tier 1 capital, and 25% in case of a corporate group.
- LEF के तहत किसी एक उधारकर्ता के लिए कुल एक्सपोज़र Tier 1 कैपिटल का 20% से अधिक नहीं हो सकता, और कॉर्पोरेट समूह के लिए यह सीमा 25% है।

Ques: What is the theme of HaRBInger 2025, the innovation challenge organised by RBI?

RBI द्वारा आयोजित HaRBInger 2025 नवाचार चुनौती का विषय क्या है?

- A) Digital Payments and Fintech / डिजिटल भुगतान और फिनटेक
- B) Secure Banking: Powered by Identity, Integrity and Inclusivity / सुरक्षित बैंकिंग पहचान ;, ईमानदारी और समावेशिता द्वारा संचालित
- C) Blockchain and Cryptocurrency / ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकॉइन्स
- D) Financial Literacy for All / सभी के लिए वित्तीय साक्षरता
- E) AI in Banking / बैंकिंग में एआई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- HaRBInger 2025 – Innovation for Transformation is the 4th edition organised by the Reserve Bank of India.
- HaRBInger 2025 – इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित चौथा संस्करण है।
- The theme of this edition is Secure Banking: Powered by Identity, Integrity and Inclusivity.
- इस संस्करण का विषय है सुरक्षित बैंकिंगपहचान ;, ईमानदारी और समावेशिता द्वारा संचालित।
- The event is conducted by the Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) and focuses on problem statements like Tokenised KYC, Offline CBDC (e₹), and Enhancing trust.
- इस कार्यक्रम का संचालन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) करता है और यह Tokenised KYC, Offline CBDC (e₹), और भरोसे को बढ़ाने जैसी समस्याओं पर केंद्रित है।

Prize of HaRBInger 2025:

- Winner across each problem statement : ₹40 lakh
- Runner-up across each problem statement : ₹20 lakh
- Special prize to the best 'all woman team' (a team comprising of only woman members'), across all the three problem statements : ₹20 lakh
- Stipend for each team shortlisted for solution development phase (for meeting the cost of development of prototype) : ₹5 lakh

Ques: What was the average daily transaction value of UPI in October 2025 according to NPCI data?

NPCI के अनुसार अक्टूबर 2025 में UPI का औसत दैनिक लेनदेन मूल्य कितना था?

- A) ₹75,000 crore
- B) ₹84,000 crore
- C) ₹94,000 crore
- D) ₹1 lakh crore
- E) ₹64,000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- According to NPCI, UPI recorded an average daily transaction value of ₹94,000 crore in October 2025, a 13% rise over September.
- NPCI के अनुसार, अक्टूबर 2025 में UPI ने औसत दैनिक लेनदेन मूल्य ₹94,000 करोड़ दर्ज किया, जो सितंबर की तुलना में 13% अधिक है।
- UPI also hit a record 740 million transactions in a single day during Diwali, highlighting India's growing digital payment adoption.
- दीवाली के दिन UPI ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 740 मिलियन लेनदेन दर्ज किए, जो भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।
- Experts expect total monthly UPI transactions to cross ₹28 lakh crore, marking an all-time high.
- विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुल मासिक UPI लेनदेन मूल्य ₹28 लाख करोड़ को पार कर सकता है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर होगा।

Ques: Which bank has signed an MoU with DPIIT to provide enhanced support for startups in India?

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT ने भारत में स्टार्टअप्स को बेहतर समर्थन देने के लिए किस बैंक के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) HDFC Bank / HDFC बैंक
- B) ICICI Bank / ICICI बैंक
- C) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), under the Ministry of Commerce and Industry, signed an MoU with Kotak Mahindra Bank Ltd. to enhance financial and non-financial support for startups across India.

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT ने भारत में स्टार्टअप्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Under this MoU, Kotak Mahindra Bank will offer zero-balance current accounts, working capital and term loans, API-based banking platforms, digital payment solutions, and specialized startup cards to DPIIT-recognised startups.
- इस MoU के तहत कोटक महिंद्रा बैंक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को शून्य-शेष चालू खाते, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन, API आधारित बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान समाधान और विशेष स्टार्टअप कार्ड प्रदान करेगा।
- The bank will also facilitate access to mentorship, investment advisory, incubation support, and networking platforms, aiding startups from ideation to scaling their business.
- बैंक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, निवेश सलाह, इनक्यूबेशन समर्थन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी प्रदान करेगा, जिससे वे विचार से अपने व्यवसाय को बढ़ाने तक प्रगति कर सकेंगे।

Ques: Which bank received the titles of 'World's Best Consumer Bank 2025' and 'Best Bank in India 2025'?

किस बैंक को 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025' और 'भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025' का खिताब मिला?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- E) Bank of Baroda / बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) received two prestigious awards from Global Finance, New York during the World Bank/IMF Annual Meetings 2025.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को ग्लोबल फाइनेंस, न्यूयॉर्क से विश्व बैंकआईएमएफ वार्षिक / बैठक 2025 के दौरान दो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले।

- SBI won the titles of 'World's Best Consumer Bank 2025' and 'Best Bank in India 2025', recognizing its strong performance and customer-focused digital initiatives.
- एसबीआई को 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025' और 'भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025' का खिताब मिला, जो इसके मजबूत प्रदर्शन और ग्राहककेंद्रित डिजिटल पहलों को दर्शाता है।

Ques: What is the total value of Phase-I of the Amaravati Capital City Development Project in Andhra Pradesh?

आंध्र प्रदेश में अमरावती राजधानी शहर विकास परियोजना के फेज-I का कुल मूल्य क्या है?

- A) ₹10,000 crore
- B) ₹12,500 crore
- C) ₹15,000 crore
- D) ₹16,500 crore
- E) ₹18,000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Phase-I of the Amaravati Capital City Development Project in Andhra Pradesh has a total project value of ₹15,000 crore.
- आंध्र प्रदेश में अमरावती राजधानी शहर विकास परियोजना का फेज-I का कुल मूल्य ₹15,000 करोड़ है।
- The implementing agency for the project is the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority (APCRDA).
- इस परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) है।
- Funding for Phase-I comes from the Government of India (₹1,400 crore), the World Bank (IBRD, USD 800 million), and the Asian Development Bank (ADB, USD 800 million).
- फेज-I के लिए वित्तपोषण भारत सरकार (₹1,400 करोड़), वर्ल्ड बैंक (IBRD, USD 800 मिलियन) ट बैंक और एशियन डेवलपमेंट (ADB, USD 800 मिलियन) से प्राप्त होता है।
- The first tranche from the World Bank, USD 207 million (≈ ₹1,800 crore), was released in March 2025, with the next contribution of USD 200 million

expected by December 2025.

- वर्ल्ड बैंक की पहली किश्त USD 207 मिलियन)≈ ₹1,800 करोड़ मार्च (2025 में जारी की गई थी, और अगली योगदान राशि USD 200 मिलियन दिसंबर 2025 तक अपेक्षित है।
- In total, the World Bank and ADB together are contributing USD 1,600 million (≈ ₹13,600 crore) for Phase-I.
- कुल मिलाकर, वर्ल्ड बैंक और ADB फेज-I के लिए मिलकर USD 1,600 मिलियन)≈ ₹13,600 करोड़का योगदान दे रहे हैं। (

Ques: Which new feature has the Reserve Bank of India (RBI) launched to enable digital rupee payments without Internet or telecom connectivity?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बिना इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी के डिजिटल रुपये से भुगतान करने के लिए कौनसी नई सुविधा शुरू की है-?

- (a) e₹ Connect
- (b) e₹ Smart Pay
- (c) Offline Digital Rupee
- (d) UPI Lite+
- (e) BharatPay e₹

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has introduced an offline digital rupee feature allowing users to make payments even without Internet or telecom connectivity.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑफ़लाइन डिजिटल रुपया सुविधा शुरू की है, जिससे उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी के भी भुगतान कर सकते हैं।
- The feature was announced at the Global Fintech Fest 2025 held in Mumbai in October 2025.
- यह सुविधा अक्टूबर 2025 में मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में घोषित की गई थी।
- The offline e₹ works on two technologies — Near Field Communication (NFC) for tap-based transfers and telecom-assisted payments for low-signal areas.

- ऑफ़लाइन e₹ दो तकनीकों पर कार्य करता है — निकट क्षेत्र संचार (NFC) और टेलीकॉम-सहायता प्राप्त भुगतान, जो कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी काम करता है।
- Unlike UPI, which needs an online connection, the Digital Rupee allows direct wallet-to-wallet transfers without requiring a bank account.
- UPI के विपरीत, डिजिटल रुपया वॉलेटवॉलेट सीधे हस्तांतरण की सुविधा देता है-दू-, जिसमें बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती।
- The digital wallet can be downloaded via official apps from 15 participating banks, including SBI, HDFC Bank, and ICICI Bank.
- डिजिटल वॉलेट को 15 भागीदार बैंकों (जैसे) SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक के (किया जा सकता है। आधिकारिक ऐप्स से डाउनलोड
- Wallets have no minimum balance requirement, with a daily cap of ₹50,000 or 20 transactions, and a maximum wallet balance of ₹1 lakh.
- वॉलेट में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, जबकि दैनिक सीमा ₹50,000 या 20 लेनदेन की है और अधिकतम शेष ₹1 लाख से अधिक नहीं हो सकता।

Ques: As of September 2025, what was the total value of RBI's gold reserves?
सितंबर 2025 तक RBI के स्वर्ण भंडार का कुल मूल्य कितना था?

- A) \$85 billion
- B) \$90 billion
- C) \$95 billion
- D) \$100 billion
- E) \$105 billion

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As per the latest data, the Reserve Bank of India (RBI)'s gold reserves crossed 880 metric tonnes in the first half of FY 2025-26.
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन पार कर गए।
- The central bank added 0.2 metric tonnes of gold in the last week of September 2025.
- केंद्रीय बैंक ने सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में 0.2 मीट्रिक टन सोना जोड़ा।
- The total value of RBI's gold holdings stood at \$95 billion as of September 26,

2025, reflecting continued growth and diversification of foreign exchange assets.

- 26 सितंबर 2025 तक RBI के स्वर्ण भंडार का कुल मूल्य \$95 बिलियन था, जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के विविधीकरण और निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), what percentage of total payment transaction volume in India was conducted through digital modes in the first half of 2025?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में भारत में कुल भुगतान लेनदेन की मात्रा का कितना प्रतिशत डिजिटल माध्यमों से किया गया-?

- A) 96.7%
- B) 97.7%
- C) 99.8%
- D) 95.5%
- E) 98.6%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The payments ecosystem in India has seen remarkable growth, with digital payments accounting for 99.8% of total payment transaction volume in the first half of 2025.
- भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जहाँ डिजिटल भुगतान 2025 की पहली छमाही में कुल लेन देन की मात्रा का-99.8% हिस्सा रहे।
- In terms of value, digital payments contributed 97.7% of total payment transactions during this period, as per data released by the *Reserve Bank of India (RBI)*.
- मूल्य के दृष्टिकोण से, *भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)* के अनुसार, इस अवधि में डिजिटल भुगतानों का योगदान कुल लेनदेन का- 97.7% रहा।
- Total payment transactions stood at ₹1,572 lakh crore, out of which ₹1,536 lakh crore were made digitally.
- कुल भुगतान लेन देन-₹1,572 लाख करोड़ रहे, जिनमें से ₹1,536 लाख करोड़ डिजिटल माध्यमों से किए गए।
- UPI accounted for 85% of total transactions by volume and 9% by value,

while RTGS had the *highest value share (69%)* despite contributing just *0.1%* of the total volume.

- यूपीआई ने कुल लेन में देन की मात्रा-85% और मूल्य में 9% हिस्सेदारी रखी, जबकि आरटीजीएसने मूल्य के आधार पर 69% की सर्वाधिक हिस्सेदारी दर्ज की, भले ही उसका वॉल्यूम हिस्सा केवल 0.1% रहा।

- In the first half of 2025, UPI processed 10,637 crore transactions worth ₹143.3 lakh crore, whereas RTGS handled 16.1 crore transactions valued at ₹1,079.2 lakh crore.

- 2025 की पहली छमाही में यूपीआईने 10,637 करोड़ लेनदेन- ₹143.3 लाख करोड़ के मूल्य के साथ किए, जबकि आरटीजीएसने 16.1 करोड़ लेनदेन- ₹1,079.2 लाख करोड़ के मूल्य के साथ किए।

- Over the last five years, India's digital payments have increased 6.6 times in volume and 1.6 times in value.

- पिछले पाँच वर्षों में, भारत में डिजिटल भुगतानों में मात्रा के आधार पर 6.6 गुना और मूल्य के आधार पर 1.6 गुना वृद्धि हुई है।

Ques: Which investment options have been extended to Central Government employees under NPS and UPS?

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS और UPS के तहत कौनकौन से निवेश विकल्प - बढ़ाए गए हैं?

- A) LC25, LC50, LC75 / LC25, LC50, LC75
- B) Default option, Scheme G / डिफॉल्ट विकल्प, योजना G
- C) BLC (Balanced Life Cycle) / BLC (संतुलित जीवन चक्र)
- D) All of the above / उपरोक्त सभी
- E) None of the above / इनमें से कोई नहीं

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India has approved the extension of LC75 and BLC investment options to Central Government employees under both the National Pension System (NPS) and the Unified Pension Scheme (UPS).
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के

तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए LC75 और BLC निवेश विकल्प बढ़ाने को मंजूरी दी है।

- Under NPS and UPS, employees can choose from a range of options: Default option (as defined by PFRDA), Scheme G (100% in government securities), LC25, LC50, LC75, and BLC.
- NPS और UPS के तहत कर्मचारियों के पास विभिन्न विकल्प चुनने की सुविधा हैडिफ़ॉल्ट :) विकल्पPFRDA द्वारा परिभाषित(, योजना G (100% सरकारी प्रतिभूतियों में(, LC25, LC50, LC75 और BLC।
- LC75 allows maximum 75% equity allocation tapering gradually from age 35 to 55, LC50 allows 50%, LC25 allows 25%, while BLC is a modified LC50 tapering from age 45 for equity.
- LC75 अधिकतम 75% इक्विटी आवंटन की अनुमति देता है, जो 35 से 55 वर्ष की आयु तक धीरेधीरे घटती है-; LC50 में 50%, LC25 में 25% की अनुमति है, जबकि BLC एक संशोधित LC50 है जिसमें 45 वर्ष की आयु से इक्विटी घटती है।
- These options give employees flexibility to choose risk-return profiles suited to their investment goals and retirement planning.
- ये विकल्प कर्मचारियों को उनके निवेश लक्ष्यों और सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार जोखिमइल चुनने में लचीलापन प्रदान करते हैं।रिटर्न प्रोफ़ा-

Ques: According to the RBI's Payment Systems Report, how did credit and debit card transactions in India change between 2019 and 2024?

RBI के पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन में क्या बदलाव हुआ?

- A) Both credit and debit card transactions increased / क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन दोनों बढ़े
- B) Credit card transactions increased, debit card transactions decreased / क्रेडिट कार्ड लेनदेन बढ़े, डेबिट कार्ड लेनदेन घटे
- C) Credit card transactions decreased, debit card transactions increased / क्रेडिट कार्ड लेनदेन घटे, डेबिट कार्ड लेनदेन बढ़े
- D) Both credit and debit card transactions decreased / क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन दोनों घटे
- E) No significant change in either / दोनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI's Payment Systems Report highlighted that between 2019 and 2024, credit card transactions in India doubled in volume (from 2,087 million to 4,472 million) and nearly tripled in value (from Rs 7.1 trillion to Rs 20.4 trillion).
- RBI की पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 से 2024 के बीच भारत में क्रेडिट कार्ड लेनदेन मात्रा में दोगुना (2,087 मिलियन से 4,472 मिलियन और मूल्य में लगभग () तीन गुना ₹7.1 ट्रिलियन से ₹20.4 ट्रिलियन बढ़ा। (
- In contrast, debit card transactions declined in both volume (4,953 million to 1,738 million) and value (Rs 6.83 trillion to Rs 5.15 trillion) during the same period.
- इसके विपरीत, डेबिट कार्ड लेनदेन मात्रा में () 4,953 मिलियन से 1,738 मिलियन और () मूल्य में ₹6.83 ट्रिलियन से ₹5.15 ट्रिलियन घटा। (
- Private sector banks dominate the credit card segment, with their market share rising from 65.8% in June 2020 to 70.8% in June 2025. Public sector banks' share also increased slightly from 22.5% to 24.1% during the same period.
- निजी क्षेत्र के बैंक क्रेडिट कार्ड खंड में प्रमुख हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी जून 2020 में 65.8% से बढ़कर जून 2025 में 70.8% हो गई। इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शेयर भी 22.5% से 24.1% तक बढ़ा।

Ques: As per the Union Ministry of Cooperation, which cooperative societies will now serve as Bank Mitras of District Central and State Cooperative Banks?

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, अब कौनसी सहकारी समितियाँ जिला केंद्रीय और राज्य - बैंक मित्र के रूप में कार्य करेंगी सहकारी बैंकों की?

- (a) Agricultural and Credit Cooperative Societies / कृषि और ऋण सहकारी समितियाँ
- (b) Dairy and Fisheries Cooperative Societies / डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ
- (c) Women Self-Help Groups / महिला स्वसहायता समूह-
- (d) Rural Development Cooperatives / ग्रामीण विकास सहकारी समितियाँ
- (e) Housing Cooperative Societies / आवास सहकारी समितियाँ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Union Ministry of Cooperation announced that, under the vision of “Sahkar Se Samridhi,” dairy and fisheries cooperative societies will act as Bank Mitras of District Central Cooperative Banks (DCCBs) and State Cooperative Banks (STCBs).
- सहकारिता मंत्रालय ने “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण के तहत घोषणा की कि डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) और राज्य सहकारी बैंक (STCB) की बैंक मित्र के रूप में कार्य करेंगी।
- With the support of NABARD, the Ministry has initiated efforts to connect cooperative societies with cooperative banks.
- NABARD के सहयोग से मंत्रालय ने सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से जोड़ने की पहल शुरू की है।
- A pilot programme in Gujarat (Banaskantha & Panchmahal) enabled cooperatives to open deposit accounts and issue RuPay Kisan Credit Cards (KCCs).
- गुजरात में एक पायलट कार्यक्रम के तहत सहकारी समितियों (बनासकांठा और पंचमहाल) ने जमा खाते खोले और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए।
- So far, 12,580 Micro-ATMs have been distributed to Bank Mitra Cooperative Societies in Gujarat.
- अब तक गुजरात में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 12,580 माइक्रोएटीएम वितरित - किए जा चुके हैं।

Ques: From which date will the key provisions relating to nomination under the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 come into effect?

2025 के बैंकिंग कानून किस अधिनियम में नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान (संशोधन) तिथि से लागू होंगे?

- A) 15th April 2025
- B) 1st October 2025
- C) 1st November 2025
- D) 1st December 2025
- E) 15th November 2025

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Banking Laws (Amendment) Act, 2025 was notified on 15th April 2025, containing 19 amendments across five legislations including RBI Act, Banking Regulation Act, SBI Act, and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts of 1970 & 1980.
 - बैंकिंग कानून अधिनियम (संशोधन), 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें आरबीआई अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम, एसबीआई अधिनियम और 1970 एवं 1980 के बैंकिंग कंपनियों अधि (अधिग्रहण और हस्तांतरण)नियम सहित पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन शामिल हैं।
 - The Central Government has notified that Sections 10, 11, 12, and 13, related to nomination facilities for deposit accounts, safe custody articles, and locker contents, will come into force from 1st November 2025.
 - केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है कि धारा 10, 11, 12 और 13, जो जमा खातों, सुरक्षित भंडारण की वस्तुओं और लॉकर सामग्री के लिए नामांकन सुविधाओं से संबंधित हैं, 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी।
 - Key features include multiple nominations (up to four persons simultaneously or successively), specifying shares for simultaneous nominations, and ensuring successive nominees become operative only upon the death of the prior nominee.
 - मुख्य विशेषताओं में एक से अधिक नामांकनों की अनुमति एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्ति, एक साथ नामांकनों के लिए शेयर निर्दिष्ट करना और क्रमिक नामांकनों में अगले नामांकित केवल पूर्व नामांकित की मृत्यु पर सक्रिय होना शामिल है।
 - These provisions aim to simplify claim settlement and ensure clarity and continuity in succession for deposits and bank locker contents.
 - ये प्रावधान दावों के निपटान को सरल बनाने और जमा और बैंक लॉकर सामग्री के उत्तराधिकार में स्पष्टता और निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं।
-

Ques: Which new entity is being established to strengthen real-time fraud detection and risk management in India's banking system?

भारत में बैंकिंग प्रणाली में वास्तविक समय धोखाधड़ी पहचान और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कौन सी नई संस्था स्थापित की जा रही है?

- A) Indian Banking Fraud Authority / भारतीय बैंकिंग फ्रॉड अथॉरिटी
- B) Indian Digital Payment Intelligence Corporation / भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन
- C) National Financial Risk Bureau / राष्ट्रीय वित्तीय जोखिम ब्यूरो
- D) Fraud Monitoring & Analytics Centre / फ्रॉड मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स सेंटर
- E) Digital Banking Security Agency / डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा एजेंसी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC) is being established to enhance real-time fraud detection and strengthen risk management across India's financial system.
- भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (IDPIC) को भारत की वित्तीय प्रणाली में वास्तविक समय धोखाधड़ी पहचान और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
- The initiative is led by the State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda (BoB), with support from other public sector banks.
- यह पहल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (BoB) द्वारा नेतृत्व की जा रही है, जिसमें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समर्थन भी शामिल है।
- IDPIC has been approved by the RBI as a Section 8 not-for-profit company, with an authorized capital of ₹500 crore and paid-up capital of ₹200 crore. SBI has committed ₹10 crore as initial funding, which Bank of Baroda is expected to match.
- RBI ने IDPIC को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में अनुमोदित किया है, जिसका अधिकृत पूंजी ₹500 करोड़ और भरी हुई पूंजी ₹200 करोड़ है। संचालन शुरू करने के लिए SBI ने ₹10 करोड़ का प्रारंभिक योगदान दिया है, जिसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा से मिलान करने की उम्मीद है।
- Bank frauds have nearly tripled in FY25, with the total amount rising from ₹12,230 crore in the previous year to ₹36,014 crore.
- FY25 में बैंक धोखाधड़ी लगभग तीन गुना बढ़ गई, कुल राशि पिछले वर्ष ₹12,230 करोड़ से बढ़कर ₹36,014 करोड़ हो गई।

Ques: Which organization launched the AI-powered digital assistant 'UPI Help' to simplify grievance redressal and transaction tracking?

किस संगठन ने शिकायत निवारण और लेनदेन ट्रैकिंग को सरल बनाने के लिए AI-पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट 'UPI Help' लॉन्च किया?

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Paytm / पेटीएम
- C) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) National Payments Corporation of India (NPCI) / राष्ट्रीय भुगतान निगम

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The National Payments Corporation of India (NPCI) launched 'UPI Help', an AI-powered digital assistant designed to simplify grievance redressal and transaction tracking on the Unified Payments Interface (UPI).
- राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने 'UPI Help' लॉन्च किया, जो AI-पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर शिकायत निवारण और लेनदेन - ए डिज़ाइन किया गया है। ट्रैकिंग को सरल बनाने के लिए
- The assistant is integrated with the UPI Dispute Resolution (UDIR) system, standardizing complaint handling across banks and payment service providers.
- यह असिस्टेंट UPI डिस्प्यूट रेज़ॉल्यूशन (UDIR) सिस्टम के साथ एकीकृत है, जो बैंकों और पेमेंट सेवा प्रदाताओं के बीच शिकायत निवारण को मानकीकृत करता है।
- Initially launched as a pilot, 'UPI Help' will be available via member banks' portals, DigiSaathi chatbot, and websites for select users.
- शुरू में पायलट के रूप में लॉन्च किए गए 'UPI Help' को चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए सदस्य बैंकों के पोर्टल, DigiSaathi चैटबोट और वेबसाइट्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

Ques: Which global investment firm announced plans to acquire a 9.99% stake in Federal Bank Limited?

कौन सी वैश्विक निवेश फर्म ने Federal Bank Limited में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की?

- A) KKR / केकेआर
- B) TPG Capital / टीपीजी कैपिटल
- C) Carlyle Group / कार्लाइल ग्रुप
- D) Bain Capital / बैन कैपिटल
- E) Blackstone Inc. / ब्लैकस्टोन इंक.

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Blackstone Inc. announced plans to acquire a minority stake of 9.99% in Federal Bank Limited for Rs 6,196.51 crore.
 - ब्लैकस्टोन इंक ने Federal Bank Limited में 9.99% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की, जिसकी कीमत ₹6,196.51 करोड़ है।
 - As part of the deal, Federal Bank will issue 27.29 crore warrants to Blackstone's affiliate, Asia II Topco XIII Private Limited, at Rs 227 per warrant.
 - इस सौदे के तहत, Federal Bank 27.29 करोड़ वॉरंट्स ब्लैकस्टोन की सहायक कंपनी Asia II Topco XIII Private Limited को ₹227 प्रति वॉरंट के हिसाब से जारी करेगा।
 - These warrants give Blackstone the right to buy shares at a fixed price within 18 months; if not converted, the initial payment is forfeited.
 - ये वॉरंट्स ब्लैकस्टोन को 18 महीनों के भीतर निश्चित मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं; यदि उन्हें रूपांतरित नहीं किया गया, तो प्रारंभिक भुगतान जब्त हो जाएगा।
-

Ques: As per SEBI's new proposal, after how many years from maturity will unclaimed amounts from non-convertible securities be transferred to the IEPF?

SEBI के नए प्रस्ताव के अनुसार, नॉनकन्वर्टिबल सिक्क्योरिटीज से अनक्लेम्ड राशि को - परिपक्वता के कितने वर्षों बाद IEPF में ट्रांसफर किया जाएगा?

- A) 3 years
- B) 5 years
- C) 7 years
- D) 10 years
- E) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SEBI has proposed amendments to standardize the treatment of unclaimed amounts from non-convertible securities, aligning them with the Companies Act, 2013 and IEPF Rules.
- SEBI ने नॉनकन्वर्टिबल सिक्क्योरिटीज से अनक्लेम्ड राशि के प्रावधानों को कंपनी - अधिनियम, 2013 और IEPF नियमों के अनुरूप मानकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है।
- Under the new guidelines, unclaimed amounts related to matured debentures, including accrued interest, will be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) only after seven years from the date of maturity.
- नए दिशानिर्देशों के तहत म्याच्योर डिबेंचर और ब्याज सहित अनक्लेम्ड राशि को - परिपक्वता की तारीख से सात वर्ष बाद ही IEPF में ट्रांसफर किया जाएगा।
- This replaces the existing inconsistency in LODR Regulation 61A(3), which required transfer of unclaimed interest even before debenture maturity.
- यह LODR रेगुलेशन 61A(3) में मौजूद असंगति को दूर करता है, जिसमें डिबेंचर के परिपक्व होने से पहले भी अनक्लेम्ड ब्याज को ट्रांसफर करने का प्रावधान था।

Genius

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has released a draft circular proposing limits on banks' exposure to which sectors?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के किस क्षेत्र में निवेश पर सीमा निर्धारित करने का मसौदा परिपत्र जारी किया है?

- A) Infrastructure and Real Estate / अवसंरचना और रियल एस्टेट
- B) Renewable Energy Projects / नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ
- C) MSMEs and Startups / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप
- D) Agriculture and Rural Credit / कृषि और ग्रामीण ऋण

E) Capital Markets and Acquisition Finance / पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) released a draft circular proposing limits on banks' exposure to capital markets and acquisition finance.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त में निवेश पर सीमा निर्धारित करने के लिए मसौदा परिपत्र जारी किया है।
- The proposed rationalised norms are expected to be implemented from April 1, 2026.
- प्रस्तावित तर्कसंगत मानदंड 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे।
- Under the draft guidelines, a bank's total exposure towards acquisition finance must not exceed 10% of its Tier 1 capital.
- मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार-, बैंक का अधिग्रहण वित्त के प्रति कुल जोखिम उसकी टियर-1 पूंजी का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- Banks' total direct investments in capital markets and acquisition finance must not exceed 20% of their Tier 1 capital.
- बैंकों का पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त में कुल प्रत्यक्ष निवेश उनकी टियर-1 पूंजी का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- Additionally, the aggregate capital market exposure of banks should not exceed 40% of their Tier 1 capital.
- इसके अतिरिक्त, बैंकों का कुल पूंजी बाजार जोखिम उनकी टियर-1 पूंजी का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- Banks may finance up to 70% of the deal value, while the acquiring company must fund at least 30%.
- बैंक सौदे के मूल्य का 70% तक वित्तपोषण कर सकते हैं, जबकि अधिग्रहण करने वाली कंपनी को कम से कम 30% स्वयं वहन करना होगा।
- Acquisition finance can be offered only to listed companies with satisfactory net worth and profitability for the last three years.
- अधिग्रहण वित्त केवल सूचीबद्ध कंपनियों को ही प्रदान किया जा सकेगा, जिनकी नेट वर्थ संतोषजनक हो और जो पिछले तीन वर्षों से लाभ में रही हों।

Ques: As per RBI's draft guidelines, what is the maximum percentage of acquisition value that banks can finance?

RBI के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अधिग्रहण मूल्य का अधिकतम कितना प्रतिशत वित्तपोषण कर सकते हैं?

- A) 50%
- B) 60%
- C) 70%
- D) 80%
- E) 100%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed allowing banks to finance up to 70% of the acquisition value for corporate takeovers.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक कॉर्पोरेट अधिग्रहणों के लिए अधिग्रहण मूल्य का 70% तक वित्तपोषण कर सकेंगे।
- The remaining 30% must be funded by the acquiring company through its own equity or internal resources.
- शेष 30% अधिग्रहणकर्ता कंपनी को अपनी स्वयं की पूंजी या आंतरिक संसाधनों से जुटाने होंगे।
- This marks a major policy shift, as earlier Indian banks were not allowed to fund corporate acquisitions directly.
- यह एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन है, क्योंकि पहले भारतीय बैंकों को सीधे कॉर्पोरेट अधिग्रहणों के लिए फंडिंग की अनुमति नहीं थी।
- Only listed companies with a profit record of at least three years will be eligible for such financing.
- केवल वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनका कम से कम तीन वर्षों का लाभ रिकॉर्ड है, इस प्रकार के वित्तपोषण के लिए पात्र होंगी।

Ques: Which bank recently joined other lenders in labeling Reliance Communications' ₹488 crore loan as fraudulent?

हाल ही में किस बैंक ने अन्य ऋणदाताओं के साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस के ₹488 करोड़ के ऋण को धोखाधड़ी वाला (fraudulent) करार दिया?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- C) Bank of Maharashtra / महाराष्ट्र बैंक
- D) Bank of India / बैंक ऑफ़ इंडिया
- E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Bank of Maharashtra has joined three other lenders—State Bank of India, Bank of Baroda, and Bank of India—in labeling Reliance Communications' ₹488 crore loan as fraudulent, adding to the telecom company's financial troubles.
- महाराष्ट्र बैंक ने अन्य तीन ऋणदाताओं—भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक ऑफ़ इंडिया—के साथ मिलकर रिलायंस कम्युनिकेशंस के ₹488 करोड़ के ऋण को धोखाधड़ी वाला (fraudulent) घोषित किया है, जिससे टेलीकॉम कंपनी की वित्तीय परेशानियाँ बढ़ गई हैं।
- Reliance Communications is already undergoing a Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.
- रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले ही 2016 के दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रहा है।

About Bank Of Maharashtra :

- Established : 1935
- HQ : Pune, Maharashtra
- MD & CEO : Nidhu Saxena
- Tagline : One Family One Bank

Ques: When was the SWAMIH Fund announced by the Government of India?
भारत सरकार द्वारा SWAMIH फंड की घोषणा कब की गई थी?

- A) 6 November 2019
- B) 10 March 2020
- C) 1 January 2021
- D) 5 May 2018
- E) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The SWAMIH (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) Fund was announced on 6 November 2019 as a 'Special Window' to support completion of stalled housing projects.
 - SWAMIH (सस्ती और मध्यम फंड की घोषणा (आय आवास के लिए विशेष विंडो-6 नवंबर 2019 को एक 'विशेष विंडो' के रूप में की गई थी ताकि अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता की जा सके।
 - It operates as an Alternative Investment Fund (AIF) aimed at providing priority debt financing for such projects.
 - यह एक वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) के रूप में कार्य करता है, जो ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राथमिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है।
 - SBI Ventures acts as the investment manager of the SWAMIH Fund under RBI supervision.
 - RBI के पर्यवेक्षण में SBI वेंचर्स SWAMIH फंड के निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
-